फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी 12:22 उपरांत एकादशी विक्रम संवत 2082

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

लखनऊ

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ बरेली कानपुर मुरादाबाद अयोध्या हल्द्वानी

गुरुवार, 12 फरवरी 2026, वर्ष 36, अंक 8, पृष्ठ 12+4 मूल्य 6 रुपये

यूपी बजट 2026-27

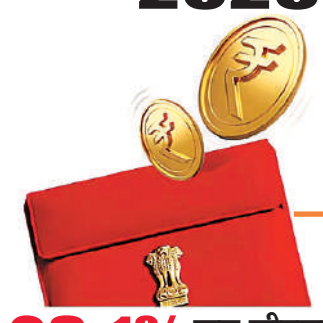

9.12 लाख करोड़ कुल बजट

19.5% पूंजीगत व्यय

12.4% शिक्षा आवंटन

6% स्वास्थ्य आवंटन

9% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

23.1% ऋण-जीएसडीपी अनुपात लक्ष्य

योगी का बाहुबली बजट

नव निर्माण के 9 वर्ष

अहम बातें

₹18,290 करोड़ से सिंचाई परियोजना

2100 नए राजकीय नलकूप

₹3,04,321 करोड़ से अधिक का गन्ना भुगतान

₹14,997 करोड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग

₹37,956 करोड़ चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं। (आयुष्मान टॉप-अप 500 करोड़)

₹5,000 करोड़ से औद्योगिक विस्तार

₹3,822 करोड़ एमएसएमई के लिए

₹27,103 करोड़ अवसंरचना मद में

₹22,676 करोड़ नमामि गंगे/ग्रामीण जल मिशन

सुरेश कुमार खन्ना
वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश

बजटीय सौगात

49.86 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन

₹400 करोड़ से मेधावी बेटियों को स्कूटी

10,00,000 युवाओं को रोजगार

₹1374 करोड़ से पुलिस भवन निर्माण

₹200 करोड़ फायर स्टेशन के लिए

₹25 करोड़ से महिला बीट कर्मियों के लिए वाहन

₹34,468 करोड़ सड़क-सेतु के लिए

₹225 करोड़ से एआई मिशन की शुरुआत

यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ बना राजस्व सरप्लस राज्य

9 साल में कोई नया टैक्स नहीं, तीन गुना बढ़ा बजट : मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, फिर भी बजट का आकार तीन गुना से अधिक बढ़कर 9.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब "अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट" के रूप में उभरा है और यह बजट उसी आत्मविश्वास का दस्तावेज है।

विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत होने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह उनके नेतृत्व में सरकार का दसवां बजट है। उन्होंने बताया कि 43,565 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि दो लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए रखी गई है। उनका कहना था कि परिसंपत्तियों के निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास से ही रोजगार सृजन को गति मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में प्रदेश में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 30 प्रतिशत से अधिक था, जिसे घटाकर 27 प्रतिशत तक लाया गया। इस वित्तीय वर्ष में इसे 23 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की 30 प्रतिशत सीमा के भीतर रहते हुए उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है और आज प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है।

स्टेट डेटा अथॉरिटी का होगा गठन

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत एआई मिशन और डेटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का प्रावधान किया गया है। स्टेट डेटा अथॉरिटी गठित की जाएगी, जो रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग के जरिए नीति निर्माण में मदद करेगी।

निवेश और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्रदेश में आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दूसरे स्थान पर पहुंचकर 'चीफ अचीवर स्टेट' बना है। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना को आगे बढ़ाया जाएगा और सिटी इकॉनमिक जोन विकसित किए जाएंगे।

कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस

योगी ने कहा कि 23 लाख डीजल ट्यूबवेल को सोलर से जोड़ने की घोषणा की गई है। एससी-एसटी, महिला और लघु सीमांत किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। दो लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य। गन्ना, दलहन-तिलहन, मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र में विशेष प्रावधान किए गए हैं। पशुधन बीमा योजना में 85 प्रतिशत तक प्रीमियम सरकार वहन करेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल हब

सीएम ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे और नए औद्योगिक क्लस्टर के लिए बजट में प्रावधान। हर जिले में स्किल डेवलपमेंट हब स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम इस बजट की मूल भावना है, जो उत्तर प्रदेश को देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

यूपी बजट 2026-27 विधानसभा में पेश करने जाते मुख्यमंत्री योगी तथा वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना।

मेगा बजट

स्वच्छताकर्मियों को सीधे अकाउंट में मिलेंगे 16 से 20 हजार रुपये बजट में किया गया प्रावधान

बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय, शिक्षा-स्वास्थ्य और कृषि पर योगी सरकार का विशेष फोकस

नव निर्माण के नौ वर्ष की थीम पर 43,565 करोड़ की नई योजनाएं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अमृत विचार : विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए "नव निर्माण के नौ वर्ष" थीम के तहत 43,565 .33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का एलान किया। कुल बजट आकार 9,12,696 .35 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष से लगभग 12 .9 % अधिक। सरकार का कहना है कि यह बजट विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी का संतुलित खाका है। एलान किया कि स्वच्छताकर्मियों को सीधे अकाउंट में 16 से 20 हजार रुपये मिलेंगे, इसका बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को बताया कि यह बजट राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता, निवेश के अनुकूल माहौल और सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन का परिणाम है। यह बजट न केवल राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है, बल्कि दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। बजट 2026-27 सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें विकास, वित्तीय अनुशासन और भविष्य की तैयारी तीनों को समान महत्व दिया गया है। इस बजट में अन्नदाता किसान, युवा, महिला, छात्र-छात्राओं समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।

राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में

उन्होंने बताया कि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह राजकोषीय अनुशासन से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 1,18,480 .59 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2 .98 प्रतिशत है। यह 3 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर है और वित्तीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। समग्र परिप्रेक्ष्य में, बजट 2026-27 में एक ओर जहां विकासोन्मुख नई योजनाओं का विस्तार है, वहीं दूसरी ओर राजस्व बचत और नियंत्रित राजकोषीय घाटे के माध्यम से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को प्राथमिकता

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 19 .5 प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो आधारभूत ढांचे, औद्योगिक विकास, सड़क, ऊर्जा और शहरी-ग्रामीण अधोसंरचना को नई गति देगा। पूंजीगत निवेश से रोजगार सृजन होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। योगी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों को बजट में प्रमुख स्थान दिया है। इसके अंतर्गत शिक्षा के लिए कुल बजट का 12 .4 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए 6 प्रतिशत और कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 9 प्रतिशत का आवंटन किया गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार मानव संसाधन विकास और किसानों की आय बढ़ाने को विकास की धुरी मानकर चल रही है।

19.5
प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान

शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्मिकों तथा पीएम पोषण योजना की रसोइयों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए 357 .84 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 89 .25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निशुल्क सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्कूल उपस्थिति में सुधार की उम्मीद है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों के शिक्षा ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना

वाराणसी रीजन चयनित

केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना में 7 रीजन की पहचान की गई है, जिनमें वाराणसी रीजन भी शामिल है। नीति आयोग की जनवरी 2026 की रिपोर्ट में काशी-विन्ध्य क्षेत्र को 'इकोनॉमिक हब' के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें 34 प्राथमिकता परियोजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, पर्यटन, विनिर्माण, ऊर्जा और आवास क्षेत्रों में समेकित विकास किया जाएगा।

यूपी एआई मिशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' (यूपीएआई मिशन) शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अगले तीन वर्षों में लगभग 2000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे। इसके लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। स्टेट डाटा सेंटर 2 .0 के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ नियोजन विभाग के अंतर्गत स्टेट डाटा अथॉरिटी की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 53 विभागों में 'जन विश्वास सिद्धांत' लागू किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

एमएसएमई और रोजगार को बढ़ावा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के तहत सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉइमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की स्थापना के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादों को पहचान और बाजार मिलेगा। इसके साथ ही, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश में फिल्म उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और एफपीओ को मजबूती

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का कोष नाबार्ड की सहभागी संस्था 'नैब किसान' के साथ मिलकर स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार 75 करोड़ रुपये का अंशदान देगी। प्रत्येक पात्र एफपीओ को अधिकतम 50 लाख रुपये तक की ऋण सीमा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, यूपी एग्रीज के अंतर्गत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत 38 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रदेश में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बजट में स्वच्छताकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके अकाउंट में सीधे 16 से 20 हजार रुपये भेजने का भी प्राविधान किया गया है। इसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही स्कीम का फायदा स्वच्छताकर्मियों को मिलेगा।

ऋण प्रबंधन में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि

वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2016-17 में राज्य को 29 .3 प्रतिशत ऋण-जीएसडीपी की अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे 2019-20 तक घटाकर 27 .9 प्रतिशत कर दिया गया। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण यह अनुपात वर्ष 2021-22 में बढ़कर 33 .4 प्रतिशत हो गया था, लेकिन सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के चलते वर्ष 2024-25 में इसे पुन : 27 प्रतिशत से नीचे लाया गया है। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात को 23 .1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य तय किया है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में इसे चरणबद्ध रूप से 20 प्रतिशत से नीचे लाने का संकल्प भी दोहराया गया है। इसका उद्देश्य राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करना है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर

यूपी बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को आसान, ब्याज-मुक्त एवं चरणबद्ध पूंजी उपलब्ध कराकर 'लखपति दीदी' लक्ष्य को गति दी जाएगी। वहीं महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बड़े बाजारों में महिलाओं द्वारा संचालित शोरूम व दुकानों की व्यवस्था की जाएगी, जिनका किराया शुरुआती तीन वर्षों तक राज्य सरकार वहन करेगी।

बजट में पूंजीगत निवेश को विशेष प्राथमिकता

राज्य सरकार ने कुल 9,12,696 .35 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें पूंजीगत निवेश को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसमें से 6,64,470 .55 करोड़ रुपये राजस्व लेखा व्यय तथा 2,48,225 .81 करोड़ रुपये पूंजी लेखा व्यय के रूप में निर्धारित किए गए हैं। पूंजीगत व्यय का यह उच्च स्तर राज्य में दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण, आधारभूत संरचना के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को गति देने की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने बताया कि समेकित निधि की प्राप्तियों में से कुल व्यय घटाने पर 64,463 .17 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। वहीं लोक लेखे से 9,500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। इन दोनों को समायोजित करने पर समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 54,963 .17 करोड़ रुपये ऋणात्मक आंका गया है, जो वित्तीय प्रबंधन के संतुलन की आवश्यकता को इंगित करता है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रारंभिक शेष 96 .41 करोड़ रुपये ऋणात्मक को जोड़ने पर अंतिम शेष 55,059 .58 करोड़ रुपये ऋणात्मक अनुमानित है। एक सकारात्मक संकेत यह भी है कि राजस्व बचत 64,457 .57 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो दर्शाता है कि राज्य की नियमित आय उसके नियमित व्यय से अधिक है और राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने में सहायता कर रही है।

नई योजनाओं और सुदृढ़ वित्तीय संरचना की दिशा में बड़ा कदम

प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 43,565 .33 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया है, जिनका उद्देश्य अधोसंरचना विकास, सामाजिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और उत्पादक निवेश को गति देना है। यह प्रावधान राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राज्य की कुल प्राप्तियां 8,48,233 .18 करोड़ रुपये अनुमानित की गई हैं। इसमें से राजस्व प्राप्तियां 7,28,928 .12 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत प्राप्तियां 1,19,305 .06 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का बड़ा हिस्सा 6,03,401 .76 करोड़ रुपये है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910 .76 करोड़ रुपये शामिल है। यह वित्तीय संरचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य की आय में स्वयं के संसाधनों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, जिससे राज्य आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनता जा रहा है।

विधान सभा में यूपी बजट 2026-27 की प्रस्तुति का दृश्य।

श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के अंतर्गत गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद और लखनऊ में निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य जनपदों (अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर एवं मुरादाबाद) में विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जनमानस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एसजीपीजीआई में क्वाटर्नरी हेल्थ केयर सुविधा प्रारंभ करने के लिए 359 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कैंसर मिशन के अंतर्गत हब एवं स्पोक मॉडल पर राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों तथा निजी क्षेत्र के समन्वय से कैंसर उपचार व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

डीजल से सोलर की ओर बड़ा कदम

बजट में विशेष रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 637 .84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यूपी बजट 2026-27 : चुनावी वर्ष में विकास का संतुलित संदेश

विशेष टिप्पणी

● राजेश श्रीनेत

उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह चुनावी माहौल में भी विकास के एजेंडे को केंद्र में रखना चाहती है। विधान सभा में पेश यह बजट आकार में पिछले साल से लगभग 12.2 प्रतिशत बड़ा है और पूंजीगत व्यय को 19.5 प्रतिशत तक बनाए रखते हुए दीर्घकालिक आधारभूत संरचना निर्माण पर जोर देता है। राजनीति के नजरिये से देखें तो यह केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और चुनावी रणनीति का संकेत भी है।

चुनावी वर्ष के बजट अक्सर तात्कालिक राहत और लोकलुभावन घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं, किंतु इस बजट में राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत की सीमा में रखने की प्रतिबद्धता वित्तीय अनुशासन का संदेश देती है। इससे लगता है कि सरकार विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है। निवेशकों के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण है कि राज्य की वित्तीय सेहत नियंत्रित दायरे में है और बड़े बुनियादी प्रकल्पों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रावधान भी चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए उल्लेखनीय आवंटन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्वास्थ्य बजट में वृद्धि ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास है। यह उन मतदाताओं के लिए संदेश है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की अपेक्षा रखते हैं। युवा मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई मिशन के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। डिजिटल कौशल, स्टार्टअप संस्कृति और तकनीकी निवेश को बढ़ावा देना यह दर्शाता है कि सरकार नई पीढ़ी को अवसरों से जोड़ना चाहती है। टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण जैसी योजनाएं राजनीतिक दृष्टि से भी संवाद का माध्यम बनती हैं। हालांकि, युवाओं की अपेक्षाएं अब केवल उपकरणों से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण और स्थायी रोजगार के अवसरों पर केंद्रित हैं। इस दिशा में घोषित निवेश और संभावित रोजगार के आंकड़ों का धरातल पर क्रियान्वयन ही वास्तविक कसौटी होगा।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एमएसएमई प्रोत्साहन और निवेश नीति के लिए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार राज्य को विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। बड़े निवेश के समझौते और संभावित रोजगार सृजन के अनुमान चुनावी विमर्श में विकास आधारित राजनीति को बल देते हैं। फिर भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन परियोजनाओं का लाभ स्थानीय युवाओं और छोटे उद्यमियों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई विस्तार, फसल सघनता में वृद्धि और उत्पादन में बढ़ोतरी के आंकड़े ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में वृद्धि और सौर परियोजनाओं का विस्तार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संकेत है।

हालांकि आलोचनात्मक दृष्टि से यह भी कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन की गति और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देना होगा। बड़े बजट का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब योजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी हों और लाभ लक्षित वर्गों तक पहुंचे। समग्र रूप से देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट विकास, निवेश और वित्तीय अनुशासन के संतुलन का प्रयास है। इसमें चुनावी संदर्भ की झलक अवश्य है, परंतु अत्यधिक लोकलुभावन रुख से बचते हुए दीर्घकालिक दृष्टि को सामने रखा गया है। मतदाता इस बात का मूल्यांकन करेंगे कि घोषित योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी सिद्ध होती हैं। फिलहाल यह बजट विकास और विश्वास के संदेश के साथ चुनावी वर्ष की राजनीतिक पृष्ठभूमि को आकार देता हुआ दिखाई देता है।

केंद्रीय करों के हिस्सेदारी में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया : सीतारमण
-08

भारत-अमेरिका समझौते में संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित : वाणिज्य सचिव
-08

चीन ने कहा- आपसी मतभेदों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखे भारत
-09

दक्षिण अफ्रीका की अफगानिस्तान पर दूसरे सुपर ओवर में रोमांचक जीत
-10

आज का मौसम

24.0° अधिकतम तापमान

11.0° न्यूनतम तापमान

सूर्योदय 06.54

सूर्यास्त 05.59

अमृत विचार

लखनऊ

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ बरेली कानपुर मुरादाबाद अयोध्या हल्द्वानी

फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी 12:22 उपरांत एकादशी विक्रम संवत 2082

गुरुवार, 12 फरवरी 2026, वर्ष 36, अंक 8, पृष्ठ 12+4 ■ मूल्य 6 रुपये

न्यूज ब्रीफ

उज्ज्वल निकम को नामित किए जाने पर याचिका दायर की

नई दिल्ली। कई हत्याओं के आरोपी गैंगस्टर विजय पलांडे ने बुधवार को अपने मामले में वकील उज्ज्वल निकम को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नामित किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। अपनी याचिका में पलांडे ने दलील दी कि राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होने के कारण निकम इस मामले में एसपीपी नहीं रह सकते, क्योंकि यह लाभ के पद पर आसीन होने के बराबर होगा। निकम ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।

भारतीय सेना से मिजोरम की साझेदारी, स्थानीय स्तर पर बढ़ेगी भर्ती

आइजोल। मिजोरम युवा आयोग (एमवाईसी) ने भारतीय सशस्त्र बलों में राज्य के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। एआरओ मुख्यालय में 'यंग मिजो एसोसिएशन' के अध्यक्ष मालसॉमजुआला राल्ते और एआरओ निदेशक कर्नल प्रकाश कुमार सिंह के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस सहयोग को अंतिम रूप दिया गया।

सलमान के बहनोई एवं अभिनेता आयुष को बिश्नोई गैंग की धमकी

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान के बहनोई आयुष शर्मा को धमकी भरा ईमेल मिला है। यह घटना अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप के माध्यम से मिली धमकी के एक दिन बाद हुई है। पुलिस ने कोई अन्य जानकारी दिए बिना बताया कि शर्मा को ईमेल भेजने वाले ने दावा किया कि वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य है।

योगी ने 10वीं बार बजट पेश कर ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया

महाबजट @9.12 लाख करोड़

- **विकास और वित्तीय अनुशासन का संतुलन निवेश रोजगार और कल्याण पर सरकार का फोकस**
- **उच्च शिक्षा की मेधावी बेटियों को मिलेगी स्कूटी सिंचाई, बीमा एवं मुफ्त बिजली पर भी जोर**

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : लोकलुभावन घोषणाओं के महाबजट के साथ बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने लगातार 10वीं बार बजट पेश कर इकलौते मुख्यमंत्री होने का रिकार्ड भी अपने नाम कर लिए। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। इसमें विकास और वित्तीय अनुशासन का संतुलन दिखा। 10 लाख युवाओं को रोजगार, लड़कियों की शादी के लिए एक लाख रुपये समेत मेधावी बेटियों को स्कूटी के एलान से युवा मतदाताओं और सिंचाई, बीमा व मुफ्त बिजली से किसानों को साधने की कोशिश हुई है।

योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 912696 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 13 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय 19.5 प्रतिशत रखा गया है, जिससे साफ है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और दीर्घकालिक विकास पर बड़ा दांव खेल रही है। राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में रखने और ऋण-जीएसडीपी अनुपात 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन का संकेत देता है। शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, लड़कियों की शादी के लिए एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा भी की गई है। बजट में नौकरीपेशा, कामगार, व्यापारी-उद्यमी समेत सबके लिए राहत और तरक्की का पिटारा है। यह बजट चुनावी वर्ष से पहले सरकार का विकास और रोजगार केंद्रित रोडमैप माना जा रहा है, जिसमें निवेश और सामाजिक योजनाओं के संतुलन के जरिए व्यापक मतदाता वर्ग को साधने की कोशिश दिखती है। फोकस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, मेडिकल शिक्षा, एमएसएमई, ऊर्जा, डिजिटल एवं एआई मिशन है। इसका विकसित यूपी @-2047 से तालमेल है।

सामाजिक कल्याण पर सरकार का विशेष ध्यान

लखनऊ : वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए 14,953 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में अल्पसंख्यक कल्याण योजना के लिए 2,058 करोड़, वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजनाओं के लिए 8,950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में 67 .50 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत लगभग 11 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इसके लिए 1,470 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- **14,953 करोड़ रुपये का प्रावधान, पेंशन से छात्रवृत्ति तक व्यापक कवरेज**

छात्रवृत्ति और छात्रावास योजनाएं

- अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति : 977 करोड़ रुपये
- सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति : 950 करोड़ रुपये
- पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (पूर्वदशम/दशमोत्तर) : 3,060 .50 करोड़ रुपये
- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति : 391 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 21 जिलों में 500 करोड़ रुपये
- मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर और मुरादाबाद में छात्रावास निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपये

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र

बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए मिशन मोड में कौशल संवर्धन अभियान चलाने की घोषणा की है। पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र खोले जाएंगे। निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

बनाए जाएंगे एग्री-एक्सपोर्ट हब

बजट में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना लागू करने की घोषणा की गई है। खन्ना कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत के आधार पर पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाएगा। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 29वें स्थान से सुधरकर 18वें स्थान पर पहुंच चुकी है।

विवाह योजना में बढ़ा 50 हजार

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1.01 लाख रुपये कर दी गई है। योजना के लिए 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति की पुत्रियों के विवाह हेतु 100 करोड़ रुपये और सामान्य वर्ग की निर्धन पुत्रियों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

पिछड़ा वर्ग और जनजाति विकास

पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजन कल्याण के लिए 2,140 करोड़, ई-ट्राईसाइकिल योजना को 60 करोड़ तथा तीन से सात आयुवर्ग के बच्चों हेतु बचपन डे-केयर सेंटर के लिए पांच करोड़ रुपये दिए गए हैं।

रामपुर : आतंकी हमला मामले में सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

- **उत्तर प्रदेश सरकार की हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को हुई सहमत**
- **2007 के आतंकी हमले में चार आरोपियों को दी गई मौत की सजा कर दी गई थी निरस्त**

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली उप्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें 2007 के रामपुर सीआरपीएफ शिविर आतंकी हमले के मामले में चार आरोपियों को दी गई मौत की सजा और एक अन्य को दी गई आजीवन कारावास की सजा निरस्त कर दी गई थी।

रामपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शिविर पर 31 दिसंबर 2007 की रात को हुए हमले में सीआरपीएफ के आठ जवान मारे गए थे और पांच घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर आरोपियों को नोटिस जारी किये और मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की। पांचों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता एम एस खान पेश हुए। राज्य सरकार ने पिछले साल 29 अक्टूबर को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें इस मामले में चार लोगों को मृत्युदंड और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी

- **राहुल गांधी के झूठे बयानों को सदन की कार्यवाही से हटाने का अनुरोध करेंगे : रीजीजू**

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। रीजीजू ने बुधवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी का भाषण झूठ से भरा था और सत्तारूढ़ गठबंधन लोस में नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए झूठे दावों को सदन की कार्यवाही से हटाए जाने का अनुरोध करेगा।

केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल के भाषण के तुरंत बाद, रीजीजू ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य आसन को एक नोटिस देंगे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष द्वारा बोले गए किसी भी कथन के प्रमाणीकरण की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जो भी झूठ बोला है, हम उसे रिकॉर्ड से हटाए जाने की मांग करेंगे। हालांकि, राहुल गांधी ने अपने बयानों को प्रमाणित करने का वादा किया है, लेकिन मंत्री ने कहा, मुझे पता है कि वह उन्हें प्रमाणित नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सदन में झूठ बोला है। रीजीजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अक्सर जानबूझकर झूठ बोलते हैं और फिर संबंधित मंत्री का जवाब सुनने के बजाय सदन छोड़कर चले जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पास लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के योग्य गंभीर स्वभाव वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कहा, हमारी पार्टी का रुख यह है कि हम राहुल के झूठ का जवाब सदन के बाहर देंगे, लेकिन सदन के अंदर नोटिस जारी किया जाएगा।

विपक्ष के नोटिस में कमियां पाई गईं

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी विपक्ष के नोटिस में कमियां पाई गईं थी, जिसके बाद खुद बिरला ने इसमें सुधार करवा के कार्यवाही करने का निर्देश अपने सचिवालय को दिया। लोकसभा सचिवालय सूत्रों ने बताया कि नोटिस में कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए चार जगहों पर वर्ष 2026 के बजाय 2025 लिखा गया था और इस आधार पर नोटिस को खारिज भी किया जा सकता था।

नरवणे की किताब मामले की जांच शुरू प्रकाशक को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के कथित प्रसार की जांच में आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े हैं और इसके प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ मामले की जांच कर रहा है।

यह मामला पुस्तक के प्रकाशन से पहले सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुस्तक के पीडीएफ संस्करण के अनधिकृत प्रसार से संबंधित है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच अब यह पता लगाने पर केंद्रित है कि क्या पांडुलिपि के लीक और उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसार के पीछे कोई आपराधिक साजिश थी। पेंगुइन ने एक बयान में कहा, पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ है। कोई भी प्रति - मुद्रित या डिजिटल रूप में - प्रकाशित, वितरित व अन्य तरीके से जनता को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

पत्नी के सामने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

फारुख अहमद

- **जिला पंचायत कार्यालय में हेड क्लर्क ने कहासुनी के बाद मारी गोली**

अमृत विचार : जिला पंचायत के हेड क्लर्क ने लाइसेंसी पिस्टल से बुधवार को एक अधिवक्ता को उसकी पत्नी के सामने ही जिला पंचायत परिसर में गोली मार दी। घायल अधिवक्ता ने अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। पत्नी के वेतन कटौती को लेकर अधिवक्ता का बाबू से विवाद हुआ था।

नगर कोतवाली नालापार निवासी वकील फारुख अहमद खान (45) की पत्नी गौसिया जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क हैं। यहीं पर थाना पटवाई क्षेत्र के मिलक तहव्वुर गांव का रहने वाला असगर अली हेड क्लर्क है। बताया जाता है कि अधिवक्ता की पत्नी का कार्यालय में लेट आने के कारण वेतन काट लिया गया था। इसी संबंध में बुधवार को गौसिया के साथ उनके पति अधिवक्ता फारुख अहमद जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। उन्होंने हेड क्लर्क असगर अली से इस विषय पर बात की। इसी बीच दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। अचानक हेड क्लर्क ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अधिवक्ता पर तीन फायर झोंक दिए।

गोली लगते ही अधिवक्ता फारुख अहमद तड़पकर गिर गए। गौसिया शोर मचाते हुए बाहर की ओर भागी। लोग आनन फानन में अधिवक्ता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तमाम वकील जिला अस्पताल पहुंच गए और हंगामा करने लगे। पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र ने मौका मुआयना कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

कनाडा में स्कूल में गोलीबारी, 10 की मौत

वैंकूवर, एजेंसी

- **ब्रिटिश कोलंबिया में वारदात, 25 से अधिक लोग घायल, दो गंभीर**

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल और एक मकान में हुई गोलीबारी की घटना में हमलावर सहित 10 लोगों की मौत हो गई। कनाडाई प्राधिकारियों ने बताया कि 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। लगभग 2,400 लोगों की आबादी वाला टंबलर रिज शहर वैंकूवर से 1,000 किलोमीटर उत्तर में अल्बर्टा की सीमा के पास स्थित है।

प्रांतीय सरकार की वेबसाइट के अनुसार, टंबलर रिज सेकेंडरी स्कूल में सातवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के 175 छात्र पढ़ते हैं। अधीक्षक केन फ्लॉयड ने बताया कि जांचकर्ताओं ने हमलावर की पहचान कर ली है, लेकिन उसका नाम जारी नहीं किया। न ही यह स्पष्ट है कि आरोपी ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। फ्लॉयड ने कहा, हम अभी इस बात को समझने की स्थिति में नहीं हैं कि इस त्रासदी का कारण क्या था। उन्होंने ने कहा कि पुलिस अभी यह जांच कर रही है कि पीड़ितों व आरोपी के बीच क्या संबंध थे। तलाशी के दौरान अधिकारियों को कई पीड़ित मिले।

संदिग्ध हमलावर भी मृत पाया गया

संदिग्ध हमलावर भी मृत पाया गया, जिसके शरीर पर खुद को चोट पहुंचाने के निशान दिखायी दे रहे थे। बयान में कहा गया है, संदिग्ध को छोड़कर छह अन्य व्यक्तियों को स्कूल के भीतर मृत पाया गया। गंभीर रूप से घायल दो लोगों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया है। तीसरे व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गयी। पीस रिवर साउथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने मंगलवार को कहा कि सेकेंडरी स्कूल और टंबलर रिज एलिमेंटरी स्कूल दोनों में किसी को अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

निर्देश

गृह मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रगीत गायन को लेकर प्रोटोकॉल तय किए

राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत के सभी छह छंद गाना जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी

- **जब भी राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएं तो राष्ट्रगीत पहले हो**

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जब भी राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' एक साथ गाए या बजाए जाएं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए राष्ट्रगीत के सभी छह छंद पहले गाए जाएं। आदेश में मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर प्रोटोकॉल तय किए हैं।

जिसके तहत राष्ट्रपति के आगमन, तिरंगा फहराए जाने और राज्यपालों के भाषण जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सभी छह छंद (कुल अवधि तीन मिनट 10 सेकंड) गाए जाएंगे। यह आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया। आदेश में कहा गया, जब भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाए या बजाए जाएं, तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जहां राष्ट्रगीत गाया जाएगा, वहां उपस्थित सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। इसमें कहा गया, जब भी राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाए, तो वहां मौजूद सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना होगा लेकिन अगर किसी समाचार रील या वृत्तचित्र के दौरान राष्ट्रगीत फिल्म के हिस्से के रूप में बजाया जाए, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इससे फिल्म दिखाने में रुकावट आएगी और सम्मान के बजाय अव्यवस्था एवं भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। मंत्रालय ने कहा कि विद्यालयों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से की जानी चाहिए। केंद्र सरकार 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

छात्रों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने के निर्देश

आदेश के अनुसार, राष्ट्रध्वज फहराने, सांस्कृतिक एवं औपचारिक कार्यक्रमों (परेड को छोड़कर), तथा किसी सरकारी या सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रपति के आगमन जैसे अवसरों पर राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण सामूहिक गायन के साथ गाया या बजाया जाएगा। राष्ट्रगीत ऐसे अवसरों पर भी गाया जा सकता है, जो भले ही पूरी तरह औपचारिक समारोह न हों, लेकिन मंत्रियों आदि की मौजूदगी के कारण महत्वपूर्ण हों। ऐसे मौकों पर (वाद्य यंत्रों के साथ या बिना) राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन वांछनीय है। यह भी कहा कि उन सभी अवसरों की पूरी सूची देना संभव नहीं है, जहां राष्ट्रगीत का गायन किया जा सकता है लेकिन यदि मातृभूमि को सम्मान देने और उचित मर्यादा बनाए रखने के साथ राष्ट्रगीत गाया जाता है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आदेश में विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना विकसित करें।

यूपी बजट 2026-27

लखनऊ, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

दुग्ध विकास को बढ़ावा

- मथुरा में 30 हजार लीटर क्षमता की प्रस्तावित परियोजना को संशोधित कर 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया डेयरी प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 23 करोड़ का प्रावधान है। 220 नई दुग्ध समितियों के गठन और 450 के पुनर्गठन के लिए 107 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पशुधन संरक्षण

- प्रदेश के 7,497 गो-आश्रय स्थलों में 12 .38 लाख गोवंश संरक्षित हैं। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ तथा वृहद गो-संरक्षण केंद्रों के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं। पशु रोग नियंत्रण हेतु 253 करोड़ और पशु चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण के लिए 155 करोड़ रखे गए हैं।

मत्स्य क्षेत्र में विस्तार

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 195 करोड़ (पुरुष घटक) और 115 करोड़ (महिला घटक) का प्रावधान है। एकीकृत एक्वा पार्क हेतु 190 करोड़ तथा अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार व प्रसंस्करण केंद्र के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।

खाद्य एवं रसद

- खाद्य एवं रसद विभाग की योजनाओं के लिए 20,124 करोड़ का प्रावधान है। अन्नपूर्ति योजना हेतु 15,480 करोड़, नि:शुल्क एलपीजी रिफिलिंग योजना के लिए 1,500 करोड़ और अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए 500 करोड़ रखे गए हैं।

उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण

- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए 2,832 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के लिए 715 करोड़, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 के क्रियान्वयन के लिए 300 करोड़ रखे गए हैं।

प्रमुख प्रावधान

2,400 करोड़ रुपये निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली के लिए

2,832 करोड़ रुपये उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण के लिए

100 करोड़ रुपये मत्स्य थोक बाजार/एक्वा पार्क/ प्रसंस्करण के लिए

2,000 छुट्टा गोवंश रखरखाव के लिए

20,124 करोड़ रुपये खाद्य एवं रसद योजनाओं के लिए

किसानों पर मेहरबानी

637.84 करोड़ रुपये कृषकों के डीजल पंप सेट को सोलर पम्प में परिवर्तित करने के लिए

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि, मत्स्य, उद्यान, दुग्ध विकास, खाद्य-रसद पर खास फोकस है।

बजट में कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपय का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20% अधिक है। सरकार ने 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कृषकों के डीजल पंप सेट को सोलर पम्प में परिवर्तित करने के लिए 637.84 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया गया।

डीजल पंप से सोलर की ओर

- किसानों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में बदलने के लिए 637 .84 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 298 करोड़ रखे गए हैं। निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु 2,400 करोड़ प्रस्तावित हैं।

एग्री-एक्सपोर्ट और यूपी एग्रीज

- यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ तथा किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए 75 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड प्रस्तावित है। एक्वा कल्चर अवसंरचना के अंतर्गत विश्वस्तरीय हैचरी व प्रशिक्षण केंद्र के लिए 155 करोड़ की बाह्य सहायता परियोजना भी शामिल है।

स्मार्ट तकनीक पुलिसिंग को मिली और ताकत

44 हजार करोड़ से साइबर अपराध नियंत्रण, डिजिटल जांच व महिला सुरक्षा

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कानून-व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, तकनीक-संपन्न और जवाबदेह बनाने के लिए 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट का उद्देश्य साइबर अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, महिला एवं बाल सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और वैज्ञानिक जांच प्रणाली को मजबूत करना है।

मिशन शक्ति के तहत महिला सुरक्षा को बल

- मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला बीट कर्मियों के लिए वाहनों की खरीद हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस की सक्रियता और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी।

साइबर थानों का आधुनिकीकरण

- साइबर थानों में संसाधन वृद्धि एवं वाहनों की खरीद के लिए 1215 .60 लाख रुपये और साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना हेतु 95 .16 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण, त्वरित जांच और साइबर हमलों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

अग्निशमन और आपदा प्रबंधन को मजबूती

- अग्निशमन वाहनों एवं उपकरणों की खरीद हेतु 190 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आपदा प्रबंधन के तहत राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) की तीन नई टीमों को सक्रिय किया जाएगा। एसडीआरएफ उपकरणों की खरीद हेतु 15 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

यूपी-112 को मिलेंगे नए वाहन

- त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया प्रणाली यूपी-112 को और मजबूत किया जाएगा। नए वाहनों की खरीद हेतु 27 .51 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

फॉरेंसिक लैब और वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा

- अपराधों की वैज्ञानिक जांच को तेज करने के लिए तीन नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को क्रियाशील किया जाएगा। न उपकरणों केलिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण, आवास के साथ सामाजिक सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 11 प्रतिशत वृद्धि करते हुए कुल 18,620 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय भागीदारी को नई ऊंचाई देना है।

सरकार ने महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है, ताकि वे स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बजट में सफाई कर्मियों और निर्माण श्रमिकों को आवास उपलब्ध कराने की पहल भी शामिल है। इससे शहरी क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास सुविधा मिलेगी। बजट 2026-27 में महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं का विस्तार करते हुए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने की स्पष्ट रणनीति पेश की है। यह बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ा

- निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान।
- 2016-17 में लाभार्थी : 17 .32 लाख
- 2025-26 में लाभार्थी : 38 .58 लाख से अधिक
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था।
- कामकाजी महिलाओं के छात्रावास निर्माण हेतु 100 करोड़।
- मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना के लिए 35 करोड़।

बच्चों के संरक्षण और पोषण पर जोर

- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़।
- मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत भवन निर्माण हेतु 80 करोड़।
- अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1 .57 करोड़ लाभार्थियों को पोषण सहायता।

तकनीकी महाशक्ति की दिशा में कदम

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को विकास की नई धुरी बनाया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस सेक्टर के लिए 2,059 करोड़ का प्रावधान किया है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। बजट में एआई मिशन के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

30,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य डाटा सेंटर में

30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने और 900 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 8 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किए गए हैं, जिनमें 6 डाटा सेंटर पार्क और 2 डाटा सेंटर इकाइयां शामिल हैं। इनसे लगभग 21,342 करोड़ का निवेश और 644 मेगावाट क्षमता अर्जित की जा चुकी है।

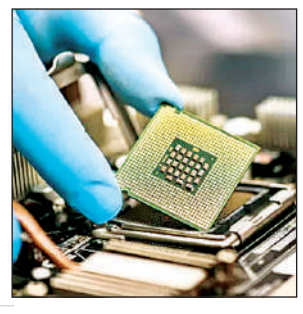

साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता

साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना को 95 .16 करोड़ का दिए गए हैं। पहले से संचालित 'एआई प्रज्ञा' कार्यक्रम के तहत माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम और वन एम वन बी जैसी कंपनियों के सहयोग से किसानों, स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों, चिकित्सकों और सरकारी कर्मियो को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अग्रणी

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी यहीं स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़कर 44,744 करोड़ तक पहुंच गया है।

बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता

अमृत विचार, लखनऊ : वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने शिक्षा को विकास की केंद्रीय धुरी बनाते हुए व्यापक प्रावधान किए हैं।

बेसिक से लेकर उच्च, प्राविधिक और कौशल विकास तक हर स्तर पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर प्रदेश को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा, कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण पर अभूतपूर्व निवेश कर सरकार

- **बजट 2026-27 में ज्ञान और कौशल पर सबसे बड़ा निवेश**

ने स्पष्ट कर दिया है कि नया उत्तर प्रदेश ज्ञान, नवाचार और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के मजबूत आधार पर ही निर्मित होगा।

पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे

बेसिक शिक्षा

- बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- कक्षा 1-8 के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म, बैग, जूते, मोजे व स्टेशनरी हेतु 650 करोड़।
- 75 जनपदों में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय। आवासीय बालिका विद्यालय विस्तार के लिए 580 करोड़।
- कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा : 358 करोड़। स्मार्ट स्कूल योजना : 300 करोड़।
- सहायता प्राप्त विद्यालयों के अनुरक्षण हेतु 300 करोड़।

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ (7% वृद्धि)।
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना : 400 करोड़
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन : 40 करोड़

नए विश्वविद्यालयों हेतु आवंटन

- मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर- 50 करोड़
- गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद- 50 करोड़
- मां पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर- 50 करोड़
- स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय शाहजहांपुर- 21 करोड़
- काशी नरेश विवि भदोही - 21 करोड़
- मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण : 14 .5 करोड़।
- एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति :10 करोड़
- मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना : 30 करोड़

माध्यमिक शिक्षा

- माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ (15% वृद्धि)।
- राजकीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 520 करोड़।
- सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 10 करोड़।
- संस्कृत पाठशालाओं की छात्रवृत्ति : 20 करोड़।
- ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर : 150 करोड़।
- शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा : 89 .25 करोड़।
- छात्राओं हेतु नि :शुल्क सेनेटरी नैपकिन : 300 करोड़।
- गोरखपुर में दूसरे सैनिक स्कूल का संचालन आरंभ।

व्यावसायिक शिक्षा

- व्यावसायिक शिक्षा बजट में 88% वृद्धि, कुल 3,349 करोड़। शिक्षा बजट में 72% वृद्धि, कुल 2,365 करोड़।
- 286 राजकीय आईटीआई 1 .90 लाख सीटें।
- 2,963 निजी आईटीआई 4 .58 लाख सीटें।
- 47 आईटीआई में महिला शाखाएं 12 महिला आईटीआई स्वतंत्र।
- टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से 149 आईटीआई उन्नत 62 और प्रगति पर।
- कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण व्यय : 1,000 करोड़।
- दस्तकार प्रशिक्षण योजना : 836 करोड़
- प्रोजेक्ट प्रवीण : 500 करोड़।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण : 20 करोड़

प्रतिक्रियाएं विशेषज्ञ बोले- डिजिटल कक्षाएं, आवासीय व्यवस्था और कैशलेस चिकित्सा से प्राथमिक शिक्षा का होगा कायाकल्प

ज्ञान, विज्ञान और नवाचार को मिलेगी उड़ान

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बजट में पिछले वर्षो की तुलना में बढोत्तरी की गई है, जिसका शिक्षाविदों और अर्थशास्त्र के जानकारों ने स्वागत किया है। बजट में प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस किया गया है।

बजट प्रस्तावों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में व्यापक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के साथ प्राविधिक और औद्योगिक शिक्षा में सरकार के नए प्रयोग, नवाचार और इंडिया एआई मिशन युवाओं को समर्पित है।

अर्थव्यवस्था को गति देगा यह बजट

- बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति को देने वाला विकासोन्मुखी बजट है। युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण योजनाओं, एवं प्रोत्साहन योजनाओं से उनकी सामाजिक आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी, जिससे निसंदेह कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। साथ ही कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधाएं महिला सुरक्षा की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि से निवेश बढ़ेगा, जो रोजगार सृजन में सहायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की नई योजना एक अच्छी पहल है जिससे ड्राप आउट रेट भी कम होगा।

-प्रो. पूनम वर्मा, अर्थशास्त्र विभाग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय

'सप्लाई-साइड इकोनॉमिक्स' की ओर झुकाव

- बजट केवल व्यय का ब्योरा मात्र नहीं है, बल्कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक 'मैक्रो-इकोनॉमिक रोडमैप' है। यह बजट स्पष्ट रूप से 'सप्लाई-साइड इकोनॉमिक्स' की ओर झुकाव दर्शाता है, जहां सरकार का प्राथमिक दर्शन 'इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्प्लॉयमेंट' के बहुआयामी प्रभाव पर आधारित है। पूंजीगत व्यय और ढांचागत प्रोत्साहन बजट का लगभग 19 .5% हिस्सा आवंटित करना एक साहसिक आर्थिक निर्णय है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयों में 55% की राष्ट्रीय हिस्सेदारी एक रणनीतिक कदम है। बजट में कौशल विकास के लिए पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव 'ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन' की आवश्यकता को रेखांकित करता है। औद्योगिक इकाइयों में महिलाओं की भागीदारी प्रगतिशील पहल है।

-डॉ. अनामिका चौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

संतुलित और स्वागत योग्य बजट

- प्रस्तुत बजट आम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है। शिक्षा के प्रत्येक मद में वृद्धि की गई है। इससे उत्तरप्रदेश का युवा अधिक ज्ञान और कौशल सम्पन्न होगा जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ वह सम्मन्न भी होगा। महिलाओं के कौशल विकास केंद्रों को विकसित करना आगामी चुनाव को देखते हुए घोषणा है। यह बजट सभी क्षेत्र की जरुरतों को पूरा करने वाला संतुलित बजट है।

-डॉ. पीयूष कुमार त्रिवेदी, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

विकसित उत्तर प्रदेश का बजट है यह

- पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में यह लगभग 12 .9 प्रतिशत अधिक है। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए 'विकसित उत्तर प्रदेश' पर फोकस करता है। बजट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सीएम युवा उद्यमी योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है। साथ ही 40 लाख युवाओं को टैबलेट बांटने का भी प्रावधान है। जिसके लिए 575 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओडीओसी (एक जिला एक व्यंजन) योजना लागू की गई है। राजकोषीय-जीएसडीपी अनुपात को अनुकूलतम 3 प्रतिशत पर रखा गया है।

-प्रो. भारती पाण्डेय, अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, श्रीजयनारायण पीजी कॉलेज

हरियाली पर जोर

सामाजिक वानिकी व रोपण

- सामाजिक वानिकी योजना : 800 करोड़
- पौधशाला प्रबंधन योजना : 220 करोड़
- राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना : 189 करोड़

रानीपुर बांध फाउंडेशन

- रानीपुर बांध से जुड़े रानीपुर बांध फाउंडेशन, चित्रकूट के कॉर्पस फंड गठन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वच्छ वायु

- उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (2025-26 से 2030-31) : 194 करोड़
- यह विश्व बैंक सहायतित बहु-क्षेत्रीय योजना है।

अपशिष्ट निस्तारण

- सामूहिक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण सुविधा
- ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग एवं उपचार सुविधा की स्थापना की कार्यवाही

प्राविधिक शिक्षा

- प्राविधिक शिक्षा बजट में 72% वृद्धि, कुल 2,365 करोड़।
- 195 डिप्लोमा संस्थान संचालित
- 23 नए पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन।
- उत्कृष्टता केंद्र व उन्नयन : 714 करोड़।
- स्मार्ट कक्षाएं (251 स्थापित, 143 प्रक्रियाधीन)।
- अवसंरचना विकास : 254 करोड़।
- नए पॉलिटेक्निक : 50 करोड़।

धुआं न शोर, इको फ्रेंडली ई-बसें बढ़ाने पर जोर

पर्यावरण की 'मित्र' इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी, बस स्टेशनों पर बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट

नीरज मिश्र, लखनऊ

अमृत विचार: न धुआं होगा और न ही शोर, इको फ्रेंडली ई-बसों के बढ़ाने पर इस बार सरकार का जोर। प्रदेश सरकार ने प्रदूषण पर गंभीर पहल करते हुए पर्यावरण के 'मित्र' इलेक्ट्रिक बसों की रफ्तार को और बढ़ाने का अपना विजन साफ कर दिया है। बजट में तात्कालिक लाभ से इतर दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उप्र. राज्य सड़क परिवहन निगम को 550 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया है। इससे न केवल इलेक्ट्रिक बसों का कुनबा बढ़ेगा, बल्कि उनके करंट का भी ठोस इंतजाम करने पर अपनी मुहर लगा दी है। ई-बसों और ई-वाहनों को भविष्य मानते हुए सरकार न केवल गाड़ी के पंजीकरण में छूट बल्कि क्रय सब्सिडी तक में रियायत दे रही है। इसकी समय सीमा तक बढ़ा दी गई है। और तो और प्रदेश में ई-वाहनों की निर्माता कंपनियों के लिए भी विशेष तरह के छूट के पैकेज जारी किए जा चुके हैं।

400 करोड़ से खरीदी जाएंगी ई-बस

परिवहन निगम के बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये मिले हैं। इस आवंटित धनराशि से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। इसका प्रयोग अन्यत्र नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ ई-बसें की कुनबे में शामिल की जाएंगी।

रोडवेज बेड़े में अभी 220 ई-बसें

परिवहन निगम के पास अब तक 220 ई-बसें आ गई हैं। यह बसें करीब 9 स्थानों पर चल रही हैं। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बाराबंकी, गोरखपुर, आगरा, मुरादाबाद, साहिबाबाद, नोएडा आदि शहरों में चल रही हैं। नई मिली धनराशि से ई-बसों की फ्लीट मजबूत और बड़ी होगी।

बस स्टेशनों पर 150 करोड़ से बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

बजटीय प्रावधान में इन बसों के ईंधन यानी ई-करंट की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया है। बस स्टेशन निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनसे रोडवेज प्रबंधन बस अड्डों पर ई-चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करेगा। यही नहीं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनमें से 50 करोड़ का आवंटन जीरो फैटलिटी के लिए उपलब्ध कराया गया है। "मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना" के अंतर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं दुर्घटना के पश्चात त्वरित कार्रवाई के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रदेश बजट में परिवहन विभाग के प्रावधानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार जताया है।

-दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

बजट में नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने, बस अड्डों के निर्माण एवं चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए दिए गए 600 करोड़ के लिए संगठन राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ने से परिवहन निगम की रफ्तार और तेज होगी। संगठन का कहना है कि परिवहन निगम में दशकों से कार्यरत संविदा चालकों-परिचालकों व आउटसोर्स कर्मियों के चरणबद्ध नियमितीकरण पर भी निर्णय कराने की कृपा करें। **-गिरीश चंद्र मिश्र, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उप्र.**

महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड से आधी आबादी को संबल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026-27 की प्रमुख उपलब्धियां बताते हुए कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यटन और दिव्यांगजन कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से महिलाओं को ब्याज-मुक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे छोटे उद्यम शुरू कर सकें। इसके साथ ही महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना लागू की जाएगी, जो केंद्रीय स्तर की सी-मार्ट अवधारणा की तर्ज पर कार्य करेगी। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। प्रत्येक जिले में श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास मिल सके।

दिव्यांग छात्राओं के लिए ई-ट्राइसाइकिल, डीडीआरसी केंद्र, कृत्रिम अंग वितरण केंद्र तथा 3-7 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, झांसी, मेरठ और आगरा में विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे।

पीपीपी मॉडल पर 1 लाख अतिरिक्त होटल कक्ष

- प्रदेश में 2024-25 में 122 करोड़ पर्यटकों के आगमन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने पीपीपी मॉडल पर 1 लाख अतिरिक्त होटल कक्ष और 50,000 होम-स्टे विकसित करने की घोषणा की। महिला गाइडों के लिए लाइसेंस शुल्क माफ किया जाएगा।

खेल के लिए ऐतिहासिक पहल

- "वन डिस्ट्रिक्ट, वन कमिश्नरी, वन डिविजनल मुख्यालय, वन स्पोर्ट्स कॉलेज" की परिकल्पना के तहत 18 मंडल मुख्यालयों पर स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्पोर्ट्स कालेज मेरठ अप्रैल-मई तक पूर्ण रूप से संचालित होगी। इन कॉलेजों को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक की तैयारी के दृष्टिकोण से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

श्रमिकों की उन्नति पर जोर

रोजगार मिशन को 200 करोड़ का प्रावधान

- **अमृत विचार, लखनऊ :** वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने श्रमिकों और असंगठित कामगारों के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में बताया कि उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के श्रमिकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। बजट 2026-27 में रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से श्रमिक परिवारों को सशक्त बनाने का स्पष्ट रोडमैप दिखाई देता है, जो प्रदेश में श्रम आधारित विकास मॉडल को मजबूती देने की दिशा में निर्णायक कदम है। सरकार ने घर से दूर शहरों में कार्यरत मजदूरों के लिए लेबर अड्डों के निर्माण की घोषणा की है, ताकि उन्हें सुरक्षित, संगठित और सुविधायुक्त कार्यस्थल मिल सके। इसे प्रवासी श्रमिकों के श्रम प्रबंधन और सुविधा विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य से सशक्तिकरण

- श्रमिक परिवारों के सामाजिक उत्थान के लिए अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में इन विद्यालयों में 10,876 श्रमिक बच्चों का नामांकन है। इस योजना के लिए 70 करोड़ की व्यवस्था की गई है। निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए पहली बार मोबाइल हेल्थ वैन पायलट परियोजना के रूप में संचालित की गई है। एक्स-ग्रेशिया अनुदान के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख तथा आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख की सहायता का प्रावधान जारी रखा गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मिला बूस्टर डोज

55,820 करोड़ से सुदृढ़ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा शिक्षा का मिलेगा विस्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: वर्ष 2026-27 के बजट में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 55,820 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 6.1 प्रतिशत है। इसे अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य आवंटन माना जा रहा है। इसमें आयुष सेवाओं में आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी के विस्तार के लिए 2,867 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार का फोकस स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने और ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाने पर है। बजट में चिकित्सा शिक्षा के लिए करीब 14,997 करोड़ रूप्ए की व्यवस्था की गई है। इसमें 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 1,023 करोड़ रूपए तथा लखनऊ स्थित कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे विशेष संस्थानों के लिए 315 रूपए करोड़ प्रस्तावित हैं। इसके अलावा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को 37,956 करोड़ रूपए का प्रावधान है, इनमें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत 8,641 करोड़ रुपये और आयुष्मान भारत योजना के लिए 2,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मातृ-शिशु स्वास्थ्य, सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को कैशलेस प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। इससे जन्मजात बीमारियों, कुपोषण और अन्य रोगों की समय रहते पहचान संभव हो रही है।

टीकाकरण और रोग नियंत्रण में प्रगति

- 8 दिसंबर 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के तहत अब तक 3.28 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा चुकी है। जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए 42 संवेदनशील जनपदों में नियमित टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविरों और निगरानी की व्यवस्था की गई है। संक्रामक रोगों की निगरानी के लिए एकीकृत डिजीज सर्विलांस पोर्टल को और मजबूत किया गया है, जहां 16 संक्रामक रोगों और 6 टीकाकरण योग्य बीमारियों की नियमित रिपोर्टिंग हो रही है।

आयुष्मान और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूती

- गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज से राहत देने के लिए आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रभावी संचालन हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 49.22 लाख लाभार्थी परिवार इस योजना से जुड़े हैं। साथ ही राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी 75 जनपदों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। बजट में इसे और प्रभावी बनाने का प्रावधान किया गया है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उपचार सुविधाएं सुलभ हो सकें।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को बल

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 8,641 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिससे दूरदराज और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा।

हर मंडल में खेल महाविद्यालय

2032-36 ओलंपिक में चमकने का लक्ष्य

- अमृत विचार, लखनऊ: वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश के खेल ढांचे को नई दिशा देने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रत्येक मंडल में एक खेल महाविद्यालय स्थापित कर उसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि वर्ष 2032 और 2036 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक तौर पर 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में प्रति विधानसभा 3 लाख रुपये और 80 संसदीय क्षेत्रों में प्रति क्षेत्र 10 लाख रुपये की दर से सांसद/विधायक खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण और स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय, मेरठ के नवीन भवन निर्माण एवं विकास कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए 30 करोड़ रुपये तथा शैक्षणिक व खेल गतिविधियों के संचालन के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार कुल 170 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान नई मांग के माध्यम से किया जा रहा है। कानपुर स्थित ग्रीनपार्क अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जिससे स्टेडियम का पुनर्विकास कर उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराएं और उत्तर प्रदेश खेल प्रतिभा का नया केंद्र बने। वर्तमान में गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज हैं।

दोगुनी आय और घटती बेरोजगारी का किया दावा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सर्वांगीण विकास को प्रमुखता से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से लेकर अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण, युवाओं के कौशल संवर्धन, किसानों की खुशहाली और गरीबी उन्मूलन तक व्यापक बदलाव दर्ज किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर है। वर्ष 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में राज्य की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आंकी गई है, जो वर्ष 2016-2017 की 54,564 रुपये प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले दोगुने से अधिक है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। सरकार ने लगभग छह करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है, जबकि बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने दावा किया कि आर्थिक वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार और निवेश-आधारित विकास मॉडल के चलते उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।

वित्त मंत्री का बजट भाषण

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

निवेश, निर्यात और नवाचार

अमृत विचार, लखनऊ : वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति को विस्तार से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2018-2019 में 29वें स्थान पर थी, जो बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट ने निवेश के नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। इनमें से करीब 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के चार ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश में निर्मित होता है। साथ ही, भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां भी प्रदेश में स्थित हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में "लीडर श्रेणी" का दर्जा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि निवेश, विनिर्माण और नवाचार के इस त्रिकोणीय मॉडल ने प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा कर दिया है।

भाजपा सरकार का आखिरी और विदाई बजट : अखिलेश

अमृत विचार, लखनऊ : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह भाजपा सरकार का आखिरी और विदाई बजट है। भाजपा जनता से किये वादों को भूल गयी। भाजपा जनता की भावनाओं से खेलती है। बजट में गरीबों, किसानों, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। बजट का आकार बड़ा है, मगर न तो मंहगाई कम हुई और न ही बेरोजगारी खत्म हुई। सपा प्रमुख बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग अयोग्य है, सरकार बजट खर्च नहीं कर पाती है। अभी तक पिछले बजट का 50 फीसदी भी नहीं खर्च कर पाई है। सरकार वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का सपना दिखाती है। उन्होंने कहा कि ट्रिलियन डालर इकोनामी के लिए जीएसडीपी 90 लाख करोड़ की होनी चाहिए और ग्रोथ रेट 30 फीसदी होनी चाहिए। जब आखिरी बजट पेश कर दिया तो 90 लाख करोड़ की जीएसटडीपी कहां से बनाएंगे।

बजट का आकार और तुलना

- कुल बजट : 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये
- कुल प्राप्तियां: 8.48 लाख करोड़
- राजस्व प्राप्तियां: 7.29 लाख करोड़
- कुल व्यय: 9.13 लाख करोड़
- राजस्व व्यय: 6.64 लाख करोड़
- पूंजीगत व्यय: 2.48 लाख करोड़

नई योजनाओं की भरमार

- सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन
- बायोप्लास्टिक औद्योगिक नीति-2024
- वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति
- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना
- महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना
- पशुधन बीमा एवं जोखिम प्रबंधन योजना
- सहकारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण
- ड्रीम स्किल लैब
- नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
- छात्राओं के लिए प्रत्येक जनपद में छात्रावास
- टेक युवा-समर्थ युवा योजना
- चार सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल (पीपीपी मोड)
- ट्रॉमा सेंटर लेवल-2
- चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्रावास
- उत्तर प्रदेश एआई मिशन
- स्टेट डेटा सेंटर
- डेटा सेंटर क्लस्टर
- यू-हब की स्थापना
- 'ग्रीन' और 'पिंक' बजट पर फोकस

बजट विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित

अमृत विचार, लखनऊ : विधान परिषद में बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को उप मुख्यमंत्री व नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित बजट है। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। इसमें नारीशक्ति, किसानों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों का खयाल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आवंटित बजट का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं। युवाओं को रोजगार देने, किसानों व आम जनता की खुशहाली के लिये संतुलित बजट है। बजट में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के लिए 25,550 करोड़ रुपये, इनमें मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए क्रमशः 5,544 करोड़ रुपये एवं 4580 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

विशेष टिप्पणी | लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रो. मनोज अग्रवाल ने बजट को बताया संतुलित

प्रदेश के समग्र विकास का प्रगतिगामी बजट

यह बजट चुनावी बजट होते हुए भी प्रगति का बजट है और दीर्घकालीन रणनीति वाला बजट है। सबसे बड़ी बात की इसमें संतुलन रखा गया है। बजट घाटे को सीमित दायरे में रखा गया है, 2.98 प्रतिशत जो 3 प्रतिशत से नीचे है। इसके अलावा राजस्व व्यय को सीमित रखते हुए राजस्व आय बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। जिसके कारण हमारा पूंजीगत परिव्यय राज्य आय का 4.5 प्रतिशत हो गया है। यह आज से 9 साल पहले 3 प्रतिशत से काफी कम था। इसका लाभ यह हो रहा है कि जब विधि व्यवस्था दुरुस्त हो गई है, डिजिटल चीजें अच्छी होने के साथ गर्वनेंस में सुधार हुआ है। इसके अलावा इज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हुआ है। सरकारी निवेश और आधारभूत संरचना बढ़ने से विदेशी निवेश के साथ घरेलू निवेश तेजी से बढ़ा है। जो इंवेस्टर समिट में दिखाई भी दिया।

प्रो. मनोज अग्रवाल, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

दूसरा, यह बजट युवाओं की संभावना वाला और महिलाओं के विकास वाला है। व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का बजट काफी बढ़ाया गया है, इसी के साथ आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रानिक का बजट बढ़ाया गया है। दोनों का तालमेल करके लैब बनाया जाना है, एआई का लैब, डेटा सेंटर के लिए 30 हजार करोड़ के 6 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यह सारी चीजें उत्तर प्रदेश को काफी आगे ले जाएंगी। कृषि में 20 प्रतिशत, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 30 प्रतिशत बजट बढ़ा है, इसी प्रकार पंचायती राज में बहुत ज्यादा बजट बढ़ाया गया है। खेती को आधुनिक करने के लिए डीजल पम्पिंग सेट की जगह सोलर पम्पिंग सेट को बढ़ावा देना, सड़क बनाना, पुलिया आदि के अवस्थापना के लिए पर्याप्त बजट है। केंद्र सरकार के साथ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से जो प्रस्ताव पास हुआ है। जिससे हमारा टैक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मित्र टैक्सटाइल पार्क योजना के तहत पार्क बनेगा। जिसका लाभ उठाते हुए हथकरघा और वस्त्र उद्योग का बजट 5 गुना कर दिया गया है, जिससे टैक्सटाइल सेक्टर में हमारा निर्यात बढ़ सके। इसी तरह एमएसएमई सेक्टर, अवस्थापना, उद्योग जगत का बजट भी बढ़ाया गया है। माइक्रो यूनिट में एक लाख लोगों को गारंटीमुक्त व ब्याज मुक्त ऋण देने की बात है, जिससे वह अपना व्यवसाय लगा सकें। युवाओं के प्रशिक्षण पर, मेडिकल एजुकेशन पर या मेडिकल सीट में जो बढ़ोत्तरी हुई है। उससे युवाओं के कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और उनके रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही है। यह सारी चीजें प्रगतिगामी हैं।

● अमृत विचार

विभागीय आवंटन में प्राथमिकताएं

सबसे अधिक आवंटन प्राथमिक शिक्षा (80,997 करोड़), ऊर्जा (65,926 करोड़), गृह (44,145 करोड़) और लोक निर्माण विभाग (33,740 करोड़) को मिला है।

बुनियादी ढांचा और निवेश

- सात संचालित एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट शीघ्र शुरू
- 16,000 स्टार्टअप, 8 यूनिकॉर्न
- 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव

पर्यटन और धार्मिक अर्थव्यवस्था

- महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु
- 234 गांव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित
- लखनऊ 'क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी'

यूपी बजट 2026-27

प्रतिक्रिया

अच्छे दिन की उम्मीदों पर पानी फिर गया : मायावती

अमृत विचार, लखनऊ : राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए पेश बजट को बसपा प्रमुख मायावती ने लोक लुभावन, अखबारों में सुर्खियां बटोरने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश 2026-27 का बजट जनता के वास्तविक उत्थान एवं प्रदेश में सर्वसमाज व सभी क्षेत्र के विकास का कम प्रतीत होता है। फिर भी जो घोषणाएं व आश्वासन आदि जनता को देने का प्रयास किया गया है, उसका सही से समयबद्ध तरीके से अमल जरूर हो ताकि ये केवल कागजी न रह जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार फिर लोगों को अपने 'अच्छे दिन' की उम्मीदों पर पानी फिर गया लगता है।

बजट में कुछ नया नहीं, सूखा और खाली : आराधना मिश्रा

अमृत विचार : नेता विधानमंडल दल कांग्रेस आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इस बजट में कुछ नया नहीं, सूखा और खाली बजट है। इतने बड़े बजट में सिर्फ 5 प्रतिशत भी नई योजनाएं नहीं हैं, पुरानी योजनाओं का बजट दिया गया है। वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए जनता की जेब काटने की तैयारी में है योगी सरकार। युवाओ, किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों सहित सभी को निराशा ,सरकार का ये अंतिम बजट ,अब इनकी विदाई तय है।

बजट केवल घोषणाओं का पुलिंदा जमीनी सच्चाई नहीं : लोकदल

अमृत विचार : लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया कि सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम" सिर्फ नारा है, हकीकत नहीं। बजट केवल घोषणाओं का पुलिंदा है, जमीनी सच्चाई से इसका कोई लेना-देना नहीं है। "सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम" सिर्फ नारा है, हकीकत नहीं।

ऊर्जा क्षेत्र को मिले 65,926 करोड़ रुपये, बढ़ेगा पावर

ग्रामीण-शहरी विद्युत आपूर्ति होगी सुदृढ़, हरित ऊर्जा पर दोगुना जोर, बजट 2025-26 की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन, आपूर्ति और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। बजट में ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए 65,926 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है।

सरकार के अनुसार दिसंबर 2025 तक औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 49 मिनट, जनपद मुख्यालयों पर 24 घंटे सुनिश्चित की गई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि बिजली आपूर्ति के मोर्चे पर राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 1 अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक 2,41,088 निजी नलकूप संयोजन जारी किए गए हैं। सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से अब तक 1,66,135 नलकूप संयोजन दिए जा चुके हैं।

1 अप्रैल 2022 से 2025-26 तक 2,410 नए 33/11 केवी उपकेंद्रों का निर्माण व क्षमता वृद्धि, 20,924 नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना, 85,684 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमतावृद्धि की गई है। वहीं, राज्य की पारेषण क्षमता वर्ष 2016-17 के 17,890 मेगावॉट से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 32,500 मेगावॉट कर दी गई है, जो 82 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

- उपकेंद्रों और ट्रांसफॉर्मरों का होगा व्यापक विस्तार

ग्राम्य विकास के लिए 25,500 करोड़ रुपये

अमृत विचार : 2026-27 के बजट में ग्राम्य विकास को प्राथमिकता दी गई है। गांवों की बुनियादी जरूरतों, आवास, सड़क और आजीविका सृजन को गति देने के लिए 25,500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। ग्राम्य विकास की योजनाओं के लिए कुल 25,500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 4,580 करोड़ तथा वीबी जीरामजी योजना के लिए 5,544 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के जरिए स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है।

शहरी विकास में मील का पत्थर साबित होगा बजट

अमृत विचार : वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शहरी विकास को नई रफ्तार देने का खाका पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नगर विकास विभाग के लिए 26,514 करोड़ रुपये तथा आवास एवं शहरी नियोजन के लिए 7,705 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। सरकार का दावा है कि यह बजट नए उत्तर प्रदेश की आधुनिक, सुव्यवस्थित और आत्मनिर्भर नगरीय संरचना की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में 113 नए नगरीय निकायों का गठन और 127 निकायों का सीमा विस्तार किया गया है, जिससे शहरीकरण को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर चयनित हैं : लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 7 नगर निगमों—अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ और शाहजहांपुर—को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की पहल की है।

एमएसएमई को 3,822 करोड़ वस्त्रोद्योग को 5,041 करोड़

अमृत विचार : वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), हथकरघा-वस्त्र उद्योग और खादी-ग्रामोद्योग को रोजगार व आत्मनिर्भरता की धुरी बनाया है। बढ़े हुए आवंटन और नई योजनाओं के साथ ग्रामीण-शहरी दोनों स्तरों पर उद्योग विस्तार और परंपरागत क्षेत्रों के आधुनिकीकरण का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई क्षेत्र की योजनाओं के लिए 3,822 करोड़ का प्रस्ताव है, जो पिछले वर्ष से लगभग 19% अधिक है। इस क्षेत्र से प्रदेश में करीब 3 .11 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है और राज्य एमएसएमई में अग्रणी बना हुआ है। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन, विपणन और प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए 5,041 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुने से अधिक है। 2026-27 में इस क्षेत्र में 30,000 नए रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

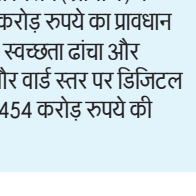

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़

अमृत विचार : प्रदेश सरकार ने बजट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सिंचाई, जल संसाधन और ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र में महत्वपूर्ण आवंटन प्रस्तावित किए हैं। यह बजट योगी आदित्यनाथ सरकार के दसवें बजट के रूप में विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें कृषि, सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 18,290 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो पिछले वर्ष 2025-26 की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास को मिले नए पंख

अमृत विचार, लखनऊ : प्रदेश में नागरिक उड्डयन और परिवहन अवसंरचना को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में व्यापक वित्तीय प्रावधान किए हैं। इस क्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास हेतु 2,111 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की। इसमें विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट में नए विकास कार्यों के साथ प्रदेश के अन्य एयरपोर्टों पर हवाई पट्टियों के निर्माण के लिए बजट प्रावधान किया गया है। साथ ही सड़क परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपये ईवी बसों की खरीद के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

अवस्थापना और औद्योगिक विकास को रफ्तार

अमृत विचार : वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश सरकार ने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए 27,103 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। यह आवंटन वर्ष 2025-26 की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य औद्योगिक विस्तार, पूंजी निवेश, एफडीआई आकर्षण और रोजगार सृजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनाना है।

67 प्रतिशत बढ़ा पंचायतों का बजट, 32090 करोड़ की व्यवस्था

अमृत विचार : 2026-27 के बजट में गांव की सरकार को सशक्त कर सीधे ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में बड़ा वित्तीय प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की योजनाओं के लिए लगभग 32,090 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ोतरी गांवों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को तेजी से विस्तार देने का संकेत है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के लिए 2,823 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गांवों में स्वच्छता ढांचा और मजबूत होगा। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

दो सहेलियों ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

संवाददाता, मलिहाबाद

- सुबह ही ससुराल से लौटी एक सहेली खेत पर गई थी मिलने
- रहीमाबाद-दिलावर नगर स्टेशन के बीच जमोलिया क्रॉसिंग की घटना

शशि

नीतू

अमृत विचार: रहीमाबाद-दिलावर नगर रेलवे स्टेशन के बीच जमोलिया रेलवे फाटक के पास बुधवार सुबह नीतू (23) और शशि (20) ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों के क्षतविक्षत शव रेलवे ट्रैक पर मिले। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे और कार्यवाहक थाना प्रभारी उमेश यादव फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन में पता चला कि दोनों बचपन की सहेलियां थी। शादी से पहले दोनों दिनभर साथ रहती थीं। शादी के बाद मिलना कम होने पर दोनों परेशान थीं। बुधवार सुबह नीतू ससुराल से लौटी। फिर शशि से मिलने खेत में गयी। उसके बाद दोनों ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली।

एसीपी मलिहाबाद सुजीत दुबे ने बताया कि बुधवार सुबह स्टेशन अधीक्षक ने रहीमाबाद-दिलावरनगर रेलवे स्टेशन के बीच जमोलिया फाटक पर दो युवतियों की ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की सूचना दी। जीआरपी और रहीमाबाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गयी। ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त नीतू और शशि निवासी राजाखेड़ा मनकौटी रहीमाबाद के रूप में की। इस बीच नीतू के पिता बुद्धा और शशि के पिता अशर्फी लाल व अन्य परिवारवाले मौके पर पहुंचे।

एक-दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थीं

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 11 बजे नीतू और शशि को खेत की ओर जाते देखा था। इसके बाद दोनों कब रेलवे ट्रैक पर पहुंच गयी, किसी को कुछ पता नहीं चला। छानबीन के दौरान पुलिस को दोनों की चप्पलें बाग में रखी मिलीं।

तय होकर टूट गई थी शशि की शादी

पुलिस ने शशि के पिता अशर्फी लाल से उसकी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ माह पूर्व शादी तय की थी। इसके बाद अचानक लड़केवालों ने शादी करने से इंकार कर दिया था। शशि के परिवार में एक बहन और पांच भाई हैं। वहीं, नीतू के परिवार में भाई नरेश और तीन बहने हैं।

रहीमाबाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पहचान के बाद दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। बातचीत में ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि नीतू और शशि में गहरी दोस्ती थी। दोनों सुबह से लेकर रात तक साथ ही रहती थीं। कई बार घरवालों ने डांटा भी था। इसके बाद भी दोनों ने मिलना बंद नहीं किया। घरवालों ने बताया कि मई 2025 में नीतू का विवाह उन्नाव जनपद के औरास के धनैया खेड़ा गांव में रहने वाले ईशू से किया था। नीतू जब कभी मायके आती तो वह सीधे शशि से मिलने चली जाती थी। देवर रवि ने पुलिस को बताया कि वह अपनी भाभी नीतू को लेकर सुबह करीब 10 बजे उनके मायके आया था। भाभी घर पहुंचते ही अपनी सहेली शशि से मिलने की बात कहकर चली गई थी। कुछ देर बाद जानकारी मिली कि भाभी और उनकी सहेली ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। एसीपी ने बताया कि परिजन ने कोई भी आरोप नहीं लगाया है।

पुराने वाद लंबित मिलने पर डीएम ने जताई नाराजगी

मलिहाबाद तहसील का निरीक्षण करते डीएम विशाख जी।

अमृत विचार, लखनऊ : जिलाधिकारी विशाख जी ने बुधवार को तहसील मलिहाबाद एवं विकास खंड माल का निरीक्षण किया। न्यायालय उप जिलाधिकारी मलिहाबाद के निरीक्षण में पुराने वादों में आदेश पत्रक न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सभी पुराने वादों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। धारा 24 के प्रकरणों एवं सीमांकन आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की। तहसीलदार न्यायालय में धारा 34/35 के पुराने वादों के लंबित रहने तथा वादों के स्टेटस ऑनलाइन न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। जिलाधिकारी ने संग्रह अनुभाग का निरीक्षण करके टॉप 10 बकायेदारों की सूची की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एक बार घटना, दो बार संयोग तीन बार दुश्मन की कार्रवाई

विधि संवाददाता,लखनऊ

- थाने के सीसीटीवी कैमरों पर एक जैसे जवाब पर हाईकोर्ट का कटाक्ष, मुख्य सचिव को जांच के आदेश

अमृत विचार: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मांगे जाने पर अलग-अलग मामलों में एक ही जैसे जवाब कि 'कैमरे काम नहीं कर रहे थे' पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पहले तो जेम्स बॉन्ड फिल्म का एक डॉयलॉग दोहराते हुए कहा कि एक बार कुछ होता है तो वह घटना है, दो बार वही घटना संयोग होती है लेकिन तीसरी बार वही घटना दोहराई जाए तो यह दुश्मन की कार्रवाई है।

कोर्ट ने कहा कि कैमरों में तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि ये फिक्शनल स्टोरी ज्यादा प्रतीत होती है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने थानों में सीसीटीवी के फेल हो जाने के मामलों की जांच मुख्य सचिव को करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तिथि नियत करते हुए, स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक जांच रिपोर्ट न दाखिल हुई तो मुख्य सचिव को हाजिर होना होगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन व न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ श्याम सुंदर अग्रहरी की याचिका अपर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब भी थानों से सीसीटीवी फुटेज मांगी जाती है तो एक ही जवाब मिलता है कि कैमरे बंद थे या खराब थे। इससे यह प्रतीत होता है कि अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज को समय पर प्रस्तुत नहीं करने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट ने यूपी पुलिस के इस व्यवहार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन करार दिया। इस मामले में याची जो एक विकलांग व्यक्ति है, उसे हत्या के प्रयास के कथित मामले में फर्जी तरीके से फंसाने तथा सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाने में उसे टॉर्चर किए जाने का आरोप याचिका में लगाया गया है।

टैंकर की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत

संवाददाता, सरोजनीनगर

- टक्कर से मौसी-भतीजा सड़क पर गिरे और पहिया ऊपर से गुजर गया

मृतक किरन

अमृत विचार: थाना क्षेत्र स्थित नादरगंज इलाके में बुधवार शाम बेकाबू टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर से मौसी-भतीजा सड़क पर गिरे और पहिया ऊपर से गुजर गया। हादसे में मौसी की मौत हो गयी, जबकि भतीजे को गंभीर हालत में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

चिल्लावां गांव निवासी निजी चालक चंद्रशेखर का बेटा रामसागर आलमबाग स्थित जनता इंटर कॉलेज में इंटर का छात्र है। बुधवार शाम करीब 4:30 बजे रामसागर की उन्नाव के इब्राहिमपुर में रहने वाली मौसी किरन (20) बहनोई के घर आ रही थी। घर पहुंचने से पहले वह अमौसी औद्योगिक क्षेत्र स्थित आर्यन हॉस्पिटल से दवा लेना चाहती थी। नादरगंज तिराहे पर पहुंचकर उन्होंने भतीजे रामसागर को फोन कर बुलाया।

रामसागर पल्सर बाइक से मौसी को लेकर अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिरे। जबतक वे संभलते टैंकर का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया। हादसे में रामसागर का बायां पैर टूट गया, जबकि किरन के पेट के पहिया गुजरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद चालक टैंकर लेकर फरार हो गया।

दो ट्रेनों के नंबर बदले सुपरफास्ट चार्ज खत्म

अमृत विचार, लखनऊः रेलवे ने हावड़ा-देहरादून और हावड़ा-जम्मू तवी ट्रेनों के नंबर बदल दिए हैं और इन्हें मेल एक्सप्रेस में परिवर्तित किया है। देहरादून-हावड़ा ट्रेन अब 15 फरवरी से 12238 की बजाय 13036 नंबर से चलेगी, जबकि हावड़ा-देहरादून सुपरफास्ट ट्रेन 13 फरवरी से नए नंबर 13037 से चलना शुरू करेगी। वापसी में यह ट्रेन 14 फरवरी से 13037 नंबर से चलेगी। हावड़ा-जम्मू तवी ट्रेन 14 फरवरी से 13041 नंबर और वापसी में जम्मू तवी-हावड़ा ट्रेन 16 फरवरी से 13042 नंबर से चलेगी। रेलवे ने यह कदम इन ट्रेनों की औसत गति 55 किमी/घंटा से कम होने के कारण उठाया है। अब स्लीपर क्लास यात्रियों को 30 रुपये और एसी क्लास यात्रियों को 45 रुपये का सुपरफास्ट चार्ज नहीं देना होगा।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में प्रशासनिक फेरबदल

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

- राजधानी से हटाए गए कई बाबू

अमृत विचार: राजधानी में लंबे समय से चर्चा में रहे और उपभोक्ताओं के बीच प्रभाव रखने वाले बाबुओं के साम्राज्य पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक आवश्यकता का हवाला देते हुए कई बाबुओं को राजधानी से हटाकर अन्य जनपदों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, कुछ बाबुओं की कार्यप्रणाली के कारण बिजली व्यवस्था की नई वर्टिकल प्रणाली प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही थी। उपभोक्ताओं और नए कनेक्शन के आवेदकों को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एमडी की ओर से जारी आदेश के तहत अमौसी जोन की कलेक्शन इकाई से अंजनी कुमार श्रीवास्तव, कैलाश चंद, रोहित यादव और कमलेश कुमार को बरेली स्थानांतरित किया गया है, जबकि रोहित यादव को सीतापुर भेजा गया है। इसी तरह जानकीपुरम जोन (बिलिंग) से संजीव कुमार, लखनऊ मध्य कलेक्शन से धीरेंद्र कुमार वर्मा के साथ 11 केवी इकाई से हेमंत कुमार धीमन को बरेली भेजा गया है। मीटर इकाई से अरुणेश कुमार सिंह, वाणिज्य शाखा से सौरभ मिश्रा और बिलिंग से प्रमोद कुमार गौतम को गोंडा स्थानांतरित किया गया है। मालूम हो कि जिन सात-आठ बाबुओं को राजधानी से हटाया गया है, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

डीआरएम ने किया काकोरी और आलमनगर स्टेशन का निरीक्षण

अमृत विचार, लखनऊ: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने बुधवार को काकोरी और आलमनगर रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और स्टेशन परिसर की साफ-सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। काकोरी स्टेशन के निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन स्थित फोटो संग्रहालय व शहीद पार्क का अवलोकन किया। आलमनगर रेलवे स्टेशनपर यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। ट्रैक, सिग्नलिंग प्रणाली और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का भी परीक्षण किया गया। डीआरएम ने दोनों स्टेशनों पर सुंदरीकरण कार्यों को गति देने तथा साफ-सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया।

बाबरी मस्जिद के विरोध में पुतला फूंका

अमृत विचार, लखनऊ: विश्व हिंदू रक्षा परिषद (वीएचआरपी) ने बाबरी मस्जिद निर्माण के विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में हुमायूं कबीर का पुतला जलाया गया। कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद जाने से रोकने पर नाराजगी जताई। राय ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की पहल माहौल खराब करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि यदि मस्जिद का निर्माण होता है तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसे चुनौती देंगे।

छावनी स्थित एएमसी स्टेडियम में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल अभ्यर्थी। अमृत विचार

अग्निवीर जीडी भर्ती में 823 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा

अमृत विचार, लखनऊ : भर्ती कार्यालय लखनऊ द्वारा छावनी स्थित एएमसी स्टेडियम में बुधवार को अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) श्रेणी की भर्ती रैली कराई गई। रैली में फतेहपुर और लखनऊ अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और दमखम दिखाया। कुल 1170 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था। इसमें 823 (70.34 फीसद) अभ्यर्थी शामिल हुए। दौड़, जंप समेत शारीरिक दक्षता परीक्षा दी। इसी तरह 12 फरवरी को अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए चित्रकूट जिले की कर्वी, मऊ, मानिकपुर और राजापुर तथा कानपुर देहात की रसूलाबाद, डेरापुर, अकबरपुर, सिकंदरा, मैथा और भोगनीपुर तहसील की भर्ती रैली कराई जाएगी।

26 रो-हाउस सील, दो प्लाटिंग ध्वस्त

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

- गोमती नगर में एलडीए के भूखंड पर बना मैरिज हॉल सील

गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-1 में मैरिज लॉन सील करती एलडीए की टीम।

अमृत विचार : लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को गुड़म्बा में अभियान चलाकर 26 अवैध रो-हाउस भवन, डुपलेक्स विला व एक व्यावसायिक निर्माण सील किया। वहीं, दुबग्गा में ले-आउट स्वीकृत कराये बिना 10 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही दो अवैध प्लाटिंग कर दी। साथ ही गोमती नगर विस्तार में एलडीए के भूखंड पर बना मैरिज हॉल सील किया।

प्रवर्तन जोन-1 में जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी के नेतृत्व में टीम ने अभियान चलाया। अहिमामऊ में प्लासियो मॉल के पास शिव कुमार सिंह द्वारा लगभग 30 वर्गमीटर के भूखंड पर किया गया अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। वहीं, गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-1 में ग्वारी पुल के नीचे एलडीए के भूखंड पर वीरेंद्र सिंह द्वारा लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाया गया मैरिज हाल सील किया गया। इस मामले पर वर्ष 2020 में एलडीए ने मुकदमा दर्ज कराया था।

प्रवर्तन जोन-5 में जोनल अधिकारी वन्दना पाण्डेय के नेतृत्व में गुड़म्बा में नहर रोड पर सुरेन्द्र वर्मा, अजय मिश्रा व अन्य द्वारा लगभग 2600 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 26 रो-हाउस भवन, इसी तरह अंशू बिल्डर द्वारा गुड़म्बा के ग्राम आधार खेड़ा में 300 वर्गमीटर के भूखंड पर डुप्लेक्स विला, व इंदिरा नगर के पानी गांव में नबील उस्मानी द्वारा लगभग 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर व्यावसायिक निर्माण मानचित्र स्वीकृत न होने पर सील किया गया।

बालगृह में रहने वाले नाबालिगों के विवरण में जाति व धर्म के उल्लेख पर हाईकोर्ट नाराज

मामले में उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निदेशालय के निदेशक और सचिव से किया जवाब-तलब

विधि संवाददाता, प्रयागराज

अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों को राजकीय बालगृह में रखे जाने के दौरान उनके अभिलेखों में जाति एवं धर्म के उल्लेख के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निदेशालय के निदेशक और सचिव से यह पूछा कि क्या राजकीय बालगृह में रह रहे नाबालिगों के परामर्शदाताओं और जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा तैयार किए गए अभिलेखों में जाति और धर्म का उल्लेख आवश्यक है। इस विषय पर कोर्ट ने पूर्व में पारित आदेशों के आलोक में महिला कल्याण निदेशालय और राज्य सरकार के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया। निदेशक एवं सचिव, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित

होने का निर्देश दिया गया।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि विभागीय अभिलेखों में संकलित जानकारी गोपनीय रखी जाती है और उसका उपयोग केवल पुनर्वास उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव को किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय नियम, 2016 के संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए सुझाव देते हुए पत्र लिखा गया है।

बता दें कि नाबालिग सुनीता व अन्य द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने बाल गृह में रखे जाने वाले नाबालिगों के विवरण में जाति एवं धर्म के उल्लेख पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार व आयोग से जवाब तलब किया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नाबालिग को विपक्षियों की अवैध अभिरक्षा में रखा गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूर्व आदेशों के अनुपालन में नाबालिग को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने यह पाया कि बालिका को कौशल उन्नयन, परामर्श एवं मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है, जिससे वह अपने भविष्य के संबंध में उचित निर्णय ले सके। इस संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 'इंडिविजुअल केयर प्लान' प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिया गया। मामले की अंतिम सुनवाई यानी 3 फरवरी 2026 को राज्य की ओर से यह सूचित किया गया कि नाबालिग वर्तमान में अपने भाई की सुरक्षित अभिरक्षा में है, साथ ही राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 2015 तथा नियम, 2016 में संशोधन हेतु सुझाव केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाने की जानकारी भी दी गई।

फर्जी मार्कशीट के आधार पर बार पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ता को जमानत नहीं

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 12 की कथित रूप से फर्जी मार्कशीट के आधार पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में पंजीकरण कराने वाले आरोपी अधिवक्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने संस्कृत श्लोक "आचार : परमो धर्म :" का उल्लेख किया और कहा कि सही आचरण ही सर्वोच्च कर्तव्य है और विधि व्यवसाय की गरिमा अटूट सत्यनिष्ठा पर आधारित है। अधिवक्ता केवल मुकदमेबाजी करने वाला पेशेवर नहीं, बल्कि न्याय प्रशासन का महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। यदि वही व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे तो यह न्याय व्यवस्था के साथ गंभीर और जानबूझकर किया गया धोखा है। ऐसे मामलों में किसी प्रकार की नरमी विधि पेशे की पवित्रता और विश्वसनीयता से समझौता होगी। उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकलपीठ ने आशीष शुक्ला की जमानत याचिका खारिज करते हुए की। याची के खिलाफ कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरिदमन सिंह ने आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468 और 471 के तहत पुलिस स्टेशन कोतवाली, कानपुर नगर में मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि अधिवक्ता ने वर्ष 1994 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने का झूठा दावा कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बार में पंजीकरण कराया। कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के संदर्भ में राज्य से मांगी 'व्यापक कार्य योजना' की जानकारी

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य सरकार से इस संदर्भ में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या अधिनियम की धारा 22(2) के तहत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हेतु कोई "व्यापक कार्य योजना" तैयार की गई है। यह जानकारी न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने 80 वर्षीय महिला गुलाब काली की याचिका पर सुनवाई के दौरान मांगी। दरअसल याची ने खराब स्वास्थ्य और पारिवारिक असुरक्षा का हवाला देते हुए आशंका जताई कि कुछ निजी व्यक्ति उसे उसकी पैतृक आबादी भूमि से अवैध रूप से बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं। वह अपनी दो पोतियों, जिनमें एक दिव्यांग है, के साथ अकेली रहती हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि सामान्यत: न्यायालय निजी पक्षों के बीच दीवानी विवादों में हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का व्यापक प्रश्न इस मामले में विचारणीय है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम में 'भरण-पोषण' का अर्थ केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा सुविधा भी शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अधिनियम के तहत शिकायतों के निस्तारण के लिए न्यायाधिकरण गठित किया जाना अपेक्षित है। राज्य की ओर से धारा 22 का उल्लेख किया गया, जो जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम लागू करने की शक्ति देती है तथा राज्य पर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनाने का दायित्व डालती है। अंत में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियम, 2014 के नियम 21 का भी हवाला दिया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कोर्ट ने राज्य से स्पष्ट जवाब मांगा कि जिला प्रशासन वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर कमजोर स्थिति में रह रहे लोगों, के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

सड़क हादसे के घायलों को अस्पताल पहुंचाया

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार। 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचाया। सोनवल गांव के समीप एनएच 28 सड़क पर दो बाइकों की टक्कर में युवक, महिला और एक बालिका घायल हो गई थी। वाहिनी के निरीक्षक/सामान्य संजय कुमार साह के नेतृत्व में जवानों ने वाहिनी की एम्बुलेंस से घायलों को एसएसबी के चिकित्सा कर्मियों की देख-रेख में जिला अस्पताल पहुंचाया। घायलों की पहचान सुग्रीव मौर्या, शुभावती पति सुग्रीव मौर्या और राधिका मौर्या पुत्री सुग्रीव मौर्या के रूप में हुई। जो गांव -कारोदा खालसा तहसील- इटवा के निवासी हैं। दंपति दवा लेने के लिए बालिका के साथ नौगढ़ जा रहे थे।

6 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद

कुशीनगर: अवैध शराब की बिक्री के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत बुधवार को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र से 06 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामदगी की गयी। पुलिस को देखकर अभियुक्त मौके से फरार हो गये। जिन्हे चिन्हित कर शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी। बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 015/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विशिष्ट व्याख्यान का हुआ आयोजन

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 58वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश) के पूर्व कुलपति एवं प्रख्यात राजनीतिक चिंतक प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और चिंतन साधना से सिद्धि का दर्शन है। उनका संपूर्ण जीवन साधुता, सादगी और मूल्यनिष्ठा से अनुप्राणित रहा। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि मानव-केंद्रित व्यवस्था का उपकरण माना।

होली में विशेष गाड़ी का संचलन

गोरखपुर, अमृत विचार। रेलवे प्रशासन द्वारा होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए 05011 गाजीपुर सिटी- बिलासपुर होली विशेष गाड़ी का संचलन गाजीपुर सिटी से 12 फरवरी को एकल यात्रा के लिए किया जायेगा। 05011 गाजीपुर सिटी-बिलासपुर होली विशेष गाड़ी 12 फरवरी को गाजीपुर सिटी से 20.35 बजे प्रस्थान करेगी। इस गाड़ी में एस.एल.आर.डी. के 02, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 02 एवं शयनयान श्रेणी के 14 कोचों सहित कुल 18 कोच लगाये जायेंगे।

गाड़ियों के मार्ग व समय में किया गया परिवर्तन

गोरखपुर, अमृत विचार। रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालनिक सुगमता हेतु चौरी चौरा स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक लिए जाने के कारण 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी का मार्ग परिवर्तन किया जायेगा। दरभंगा से 14, 18, 23 एवं 28 फरवरी को चलने वाली 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग सीवान-कप्तानगंज-गोरखपुर कैंट के रास्ते चलाई जायेगी।

इसके अलावा रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालनिक सुगमता के लिए कुछ गाड़ियों के समय में परिवर्तन किया गया है। 19716 गोमती नगर-जयपुर एक्सप्रेस 13 अप्रैल से मथुरा कैण्ट स्टेशन से निर्धारित समय 01.52 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 01.42 बजे छूटेगी। 15672 रोहतक-कामाख्या एक्सप्रेस 13 अप्रैल से प्रयागराज रामबाग स्टेशन से निर्धारित समय 10.02 बजे के स्थान से परिवर्तित समय 09.37 बजे तथा ज्ञानपुर रोड स्टेशन से निर्धारित समय 10.50 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 10.30 बजे छूटेगी।

ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा के घर ईडी का छापा

जिला संवाददाता, संतकबीरनगर।

अमृत विचार। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मीट मंडी मोहल्ले में मंगलवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के आवास पर छापेमारी की। सुबह करीब आठ बजे लखनऊ से पहुंची तीन सदस्यीय टीम ने घर को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, जो देर शाम तक जारी रही। इस दौरान टीम ने मौलाना के संपत्तियों से कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। ईडी अधिकारियों ने मोबाइल फोन व महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाले।

सूत्रों के अनुसार, मौलाना व परिजनों से जुड़े 19 बैंक खातों में हुए लेनदेन की पड़ताल की जा रही है। आवास के बाहर सीआरपीएफ के करीब 16 जवान तैनात रहे और आम लोगों की आवाजाही

खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मीट मंडी मोहल्ले में शमसुल हुदा ख़ान के घर ईडी की छापेमारी के दौरान गेट के बाहर चौकसी करते सीआरपीएफ के जवान।

- **देर शाम तक जारी रही जांच, 19 खातों के लेन-देन और संपत्तियों की हुई पड़ताल**

पर रोक रही। टीम ने मौलाना की पत्नी व बहू से पूछताछ की। इसके अलावा उन्होंने लोगों के मोबाइल को भी अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं, ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा का बेटा तौसीफ रजा घर पर नहीं मिला। देर शाम तक चली ईडी की कार्यवाही में किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। आपको बता दें कि ब्रिटिश मौलाना ने आजमगढ़ में 2017 तक सहायक अध्यापक की नौकरी की थी। उसने वहां भी घर बनवा रखा है। मौलाना 2007 से लंदन में रह रहा। उसने 2013 में वहां की नागरिकता ले ली है। उसके खिलाफ विदेशी फंडिंग और पाकिस्तान कनेक्शन की जांच एटीएस कर रही।

दरअसल, मूल रूप से दुधारा क्षेत्र के देवरिया लाल गांव निवासी शमसुल हुदा ने 2017 में खलीलाबाद में मदरसा 'कुल्लियातुल बनातिर रजविया निस्वा' संचालित किया था। एटीएस वाराणसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश पर डीएमओ ने उनके खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज कराया है। रिपोर्ट में विदेशी संस्थानों से मदरसों के नाम पर चंदा जुटाकर उसे अपनी संस्थाओं—कुल्लियातुल बनातिर रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी व रजा फाउंडेशन—के माध्यम से खर्च करने तथा वितरण में कमीशन के आरोप हैं। प्रकरण की विवेचना एसआई ललितकांत यादव को सौंपी गई है। एएसपी सुशील कुमार सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर खातों को डेबिट फ्रीज कराया गया है।

होमियोपैथिक क्लीनिक का हुआ शुभारम्भ

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर अमृत विचार। तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत शोहरतगढ़ कस्बे में बुधवार को दुल्लीचन्द खाद भण्डार, शोहरतगढ़ के समीप स्वास्थ्य होमियोपैथिक क्लीनिक का शुभारम्भ चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल एवं मण्डल अध्यक्ष शिवशक्ति शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना : ओटी-18-2025

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर / निर्माण, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये "खुली" निविदा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सं०:-** ओटी-18-2025, **कार्य का विवरण:-** कुसुम्ही-गोरखपुर- डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और गोरखपुर- नकहा दोहरीकरण परियोजना के अन्तर्गत गोरखपुर में 25 केवी, 50 हट्‌र्ज, सिंगल फेज, एसी नए स्विचिंग पोस्ट (एसएसपी) का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग का कार्य। **अनुमानित लागत:-** रु. 1,48,35,483.35, **बयाना राशि:-** रु. 2,24,200.00, **निविदा प्रपत्र का मूल्य** – रु निल, **कार्य पूर्ण करने की अवधि** – 06 माह, **निविदा बन्द होने की अंतिम तिथि व समय:** 05.03.2026 को 15.00 बजे।, **नोट:** • इस निविदा के विरुद्ध कोई मैनुअल आफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे प्राप्त मैनुअल आफर को उपेक्षित कर दिया जायेगा। विस्तृत विवरण व निविदा जमा करने हेतु कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाइट **www.ireps.gov.in** को देखें।, • निविदा सूचना में यदि हिन्दी या अंग्रेजी के आलेखों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के ही आलेख मान्य होगें।

उप मुख्य विद्युत इंजीनियर / निर्माण, गोरखपुर
मुजाधि / विद्युत-277

ट्रेनों में बीड़ी / सिगरेट न पियें

योजना : क्यूआर कोड से खुलेगा काशी का प्राचीन इतिहास

बनारस, अमृत विचार। काशी को जल्द ही एक नए घाट की सौगात मिलेगी। पर्यटन विभाग नमो और आदि केशव घाट के बीच एक नया 'मॉडल घाट' बनाएगा। नए कॉरिडोर के बनने से काशी की भौगोलिक सुंदरता बढ़ेगी। साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नया घाट पर्यटकों को काशी के उस प्राचीनतम हिस्से से भी जोड़ेगा, जो अब तक मुख्यधारा से थोड़ा दूर है। विभाग ने परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

वर्तमान में काशी आने वाले पर्यटक नमो घाट की आधुनिक चमक-धमक और सुविधाओं को देखकर लौट जाते हैं। इसी को ध्यान में रख नए घाट का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो नमो घाट को सीधे आदि केशव घाट से जोड़ेगा।

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार के अनुसार, आदि केशव घाट का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है और इसे काशी के पांच प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। भगवान विष्णु का प्रथम और प्रमुख 'विष्णु तीर्थ' होने के कारण इसका धार्मिक महत्व है। नया घाट बनने से श्रद्धालु सुगमता पूर्वक इस प्राचीन स्थल तक पहुंच सकेंगे और पौराणिक महत्ता को करीब से जान पाएंगे। यह नया घाट केवल पत्थर की संरचना मात्र नहीं होगा, बल्कि सूचनाओं का एक जीवंत केंद्र बनेगा। विभाग की योजना के अनुसार, घाट की दीवारों पर काशी के गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाले भव्य म्यूरल (भित्ति चित्र) उकेरे जाएंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक क्यूआर कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन करते ही पर्यटक उस स्थान और काशी के इतिहास से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह जानकारी ऑफलाइन मोड में होगी, ताकि नेटवर्क की समस्या होने पर भी ज्ञान की गंगा बहती रहे। पूरे क्षेत्र में साइनेज लगाए जाएंगे ताकि पर्यटकों को भ्रमण में आसानी हो। पर्यटन के इस नए मॉडल में जल परिवहन पर भी विशेष जोर दिया गया है। नए घाट के निर्माण के साथ ही पर्यटकों को गंगा के उस पार चंदौली क्षेत्र में अवधूत भगवान राम समाधि स्थल के दर्शन कराने की भी तैयारी है। इसके लिए विशेष वॉटर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। इससे काशी के घाटों पर भीड़ का दबाव कम होने के साथ ही गंगा पार के आध्यात्मिक स्थलों तक भी पर्यटकों की पहुंच बढ़ेगी। काशी की प्राचीनता और आधुनिकता के संगम को विस्तार देने के लिए नमो घाट और आदि केशव घाट के बीच एक नया "मॉडल घाट" प्रस्तावित है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को काशी के सबसे प्राचीन "विष्णु तीर्थ" यानी आदि केशव घाट तक पहुंचाना है। यह घाट न केवल स्थापत्य का बेजोड़ नमूना होगा, बल्कि क्यूआर कोड और म्यूरल्स से काशी के इतिहास का डिजिटल झरोखा भी बनेगा।

मुसहर समाज ने पट्टा निरस्त की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

कुशीनगर, अमृत विचार: दुदही विकासखंड के ग्राम पंचायत लोहारपट्टी टोला चिरकुटहां में सामुदायिक बंजर भूमि के कथित अवैध पट्टे को लेकर मुसहर समाज ने बुधवार को सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विवादित पट्टे को तत्काल निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि मुसहर बस्ती के बीच स्थित आराजी संख्या 358 की नवीन परती एवं बंजर भूमि का वर्षों से समाज द्वारा शादी-विवाह, सामाजिक बैठक और अन्य सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। समाज के लोगों ने अपने संसाधनों से इस भूमि की चारदीवारी भी कराई थी, ताकि यह सामूहिक उपयोग के लिए सुरक्षित रह सके। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधान ने कथित रूप से लगभग छह लाख रुपये लेकर उक्त भूमि का कृषि पट्टा ग्राम पंचायत निवासी कन्हई कुशवाहा के नाम कर दिया।

सूचना

सूचित हो कि पहले मेरा पुराना नाम प्रभाप्रीत कौर (PRABHAPREET KAUR) था। जो अब बदल कर नया नाम प्रभप्रीत कौर (PRABHPREET KAUR) हो गया है। अब मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए। **Prabhpreet Kaur D/o Balpreet Singh Makkar R/o- 63, Samar Vihar Colony Manaknagar, Lucknow, U.P.-226011**

चार रेलवे कर्मचारी किए गए सम्मानित

गोरखपुर,अमृत विचार। महाप्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर ने बुधवार को महाप्रबन्धक सभाकक्ष गोरखपुर में संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चार कर्मचारियों को 'सेफ्टी स्टार ऑफ द मंथ' घोषित कर नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में लखनऊ मंडल के शोहरतगढ़ स्टेशन पर कांटावाला के पद पर कार्यरत बद्री विशाल दूबे, वाराणसी मंडल के वाराणसी स्टेशन पर गाड़ी प्रबंधक/माल के पद पर कार्यरत योगेन्द्र सिंह, वाराणसी मंडल के बनारस कोचिंग डिपो में तकनीशियन के पद पर कार्यरत सर्वेश तिवारी और इज्जतनगर मंडल पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर/रेलपथ, बदायूं के अधीन ट्रैकमेंटेनर के पद पर कार्यरत देवेन्द्र कुमार को सम्मानित किया गया।

यूपी बजट | उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर दी प्रतिक्रिया

सिद्धार्थनगर के लिए उपेक्षापूर्ण है यूपी बजट : मणेन्द्र

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया। योगी सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेन्द्र मिश्रा ने कहा कि 2026-27 का यूपी बजट बुद्धभूमि सिद्धार्थनगर की दृष्टि से उपेक्षापूर्ण है। जिले के महत्व से जुड़े कपिलवस्तु, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कालानमक चावल सहित अन्य प्रमुख विषयों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। भाजपा सरकार के अंतिम बजट से जनपदवासी निराश है।

श्री मिश्रा ने कहा कि सिद्धार्थनगर भारत/नेपाल सीमा से सटा होने के

सपा नेता मणेन्द्र मिश्रा।

कारण उत्तर प्रदेश में विशेष महत्व का जिला है। तथागत गौतम बुद्ध की क्रीड़ास्थली होने के कारण इसकी प्रसिद्धि वैश्विक है। कालानमक चावल की महक से यहां किसान सुदूर देशों तक जाने जाते हैं। लेकिन भाजपा सरकार के बजट में इन सभी बिन्दुओं पर घोर उदासीनता है। भारत/नेपाल सीमा का प्रमुख केंद्र बढ़नी लंबे समय से जाम से कराह रहा है जिसका स्थाई समाधान नहीं हो रहा। सामाजिक कार्यकर्ता वकार मोईज खान ने कहा कि सरकार ने बजट में कई जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा हुई है जिससे प्रदेश के लोगों को व्यापक लाभ होगा जनपद में रोजगार को लेकर घोषणा न होने से निराशा हाथ लगी।

इन्होंने कहा

शोहरतगढ़ क्षेत्र निवासी भाजपा नेता नीलेश चौधरी ने कहा कि योगी सरकार का ऐतिहासिक बजट है, जिसमें सभी वर्गों के उत्थान की बात की गयी है। यह बजट राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित है।

सपा नेता विष्णु उमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नौकरी-रोजगार की मांग कर रहे नौजवानों को फिर निराश किया है। बजट में सिद्धार्थनगर का जिक्र न होने से मायूसी हई।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
30वाँ (वि०/यां०)वृत्त
लो०नि०वि०,लखनऊ ।

पत्रांक:-282 /67 सी0बी0-30/2026 दिनॉक:-05/02/2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय उ०प्र०की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रतिशत दर के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र दिनांक 13.02.2026 से 18.02.2026 तक अपरान्ह 2.0 बजे तक निर्धारित मूल्य जमा कर अधिशासी अभियंता विद्युत् अनुरक्षण खंड -1 लो०नि०वि० लखनऊ एवं अधिशासी अभियंता विद्युत् अनुरक्षण खंड -2 लो०नि०वि० लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

मुहरबन्द निविदाए सील्ड लिफाफों में दिनांक 19.02.2026 को अपरान्ह 2.0 बजे तक उक्त कार्यालय में प्राप्त की जायेंगी तथा दिनांक 19.02.2026 को अपरान्ह 3.30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियो के समक्ष खोली जाएगी । यदि दिनांक 19.02.2026 को अवकाश होता है तो निविदाए अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेंगी । निविदा के साथ 100रु० का जनरल स्टैम्प जिस पर रु० 1.0 का रसीदी स्टैम्प हस्ताक्षरित किया हुआ लगा हो,जमा करना अनिवार्य होगा । निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा ।

क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत रु० (लाख में)	धरोहर धनराशि रु० (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य कर सहित(रु०)	फर्म के पंजीयन की श्रेणी
1.	विधायक निवास-1व 2(पुराना), दारुलशफा में क्षतिग्रस्त राइजिंग मेन्स के स्थान पर नई केबल की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य ।	7.57 लाख	0.76 लाख	02 माह	856.00	लो०नि०वि० में विद्युत् कार्यो हेतु 'ए', श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा के पात्र होंगे ।

शर्तें:-1.निविदा सम्बन्धी अन्य जानकारी दिनांक 12.02.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियंता विद्युत् अनुरक्षण खंड -1 लो०नि०वि० लखनऊ के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
2.सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।
3-बिड डॉक्यूमेंट के आई०टी०बी०क्लॉज़ 4.4 बी(ii)के अनुरूप निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी सूचनाओ की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ -पत्र (टी-6) मूल में एवं चरित्र प्रमाण पत्र (टी-4) संलग्न करना अनिवार्य है।
4.आयकर /जी०एस०टी०/लेबर सेस की कटौती नियमानुसार की जाएगी ।
5.निविदा के साथ धरोहर धनराशि की एफ़०डी०आर०,एन०एस०सी०आदि जो अधिशासी अभियंता विद्युत् अनुरक्षण खंड-1,लो०नि०वि०लखनऊ के पक्ष में बंधक हो,लगाना अनिवार्य होगा,अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

(मुनेश्वर सिंह)
अधिशासी अभियंता
विद्युत् अनुरक्षण खंड -1
लो०नि०वि०,लखनऊ ।

(अभय कुमार गुप्ता)
अधीक्षण अभियंता
30वाँ (वि०/यां०)वृत्त
लो०नि०वि०,लखनऊ ।

UP - 245770 दिनांक: 10/02/2026
विज्ञापन वेबसाइट www.up.gov.in पर उपलब्ध है।

अमृत विचार
क्लासीफाइड
विज्ञापन हेतु अमृत विचार कार्यालय में सम्पर्क करें

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पोस्ट आफिस के खाता में आरती देवी लिखा जोकि मेरे आधार कार्ड में विमला देवी लिखा है जोकि दोनो नाम एक व्यक्ति के है। **विमला देवी पत्नी आलोक कुमार निवासी ग्राम पूरे भवन शाह मजरे ताला गोपालपुर जिला रायबरेली**

सूचना

मैं **राजू पुत्र सुखनन्दन निवासी पूरे सुबेदार पो. रोखा जिला रायबरेली** का निवासी हूं। मेरी भारतीय जीवन बीमा की पालिसी संख्या 214974086 में नाम राजूलाल पुत्र औसान यादव दर्ज है, जबकि आधार कार्ड व अन्य कागजात में नाम राजू पुत्र सुखनन्दन अंकित है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। मुझे और मेरे पिता को उक्त नामों से जाना और पहचाना जाता है।

सूचना

सूचित् किया जाता है कि मैंने अपना नाम NEERAJ से बदल कर NEERAJ KUMAR रख लिया है अब भविष्य में मुझे मेरे बदले हुए नाम से जाना वह पहचान जाए पुत्र RAM BAHADUR ग्राम किशनपुर कौड़िया बंथरा लखनऊ का रहने वाला हूं।

सूचना

पहले मेरा नाम अली खान (ALI KHAN) था अब मैंने अपना नाम बदलकर अली मुहम्मद (ALI MUHAMMAD) रख लिया है। अत: भविष्य में मुझे अली मुहम्मद (ALI MUHAMMAD) के नाम से जाना व पहचाना जाए। S/0 DLLDAR HUSAIN KHAN R/O VILL & POST-GORABARIK Thana KOTWALI NAGAR DIST-SULTANPUR, U.P.-228001

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राममिलन पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी भटरी तहसील राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पुत्र दौलत राम का चाल चलन व चरित्र ठीक न होने के कारण मैं अपनी चल व अचल संपत्ति से बेदखल करने की घोषणा करता हूं आज दिनांक 11/02/26 से मेरी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा । **प्रार्थी - राममिलन पुत्र लक्ष्मी प्रसाद, निवासी भटरी तहसील राजापुर जनपद चित्रकूट**

सूचना

मैने अपना नाम JAHEEN HAYDAR से बदलकर ZAHEEN HAIDER रख लिया अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। S/0-MAZHAR HAYDAR ADD-22/435 SECTOR -12 HAIDER HOUSE INDIRA NAGAR DIST-LUCKNOW-226016 (U.P.)

सूचना

मैं RAJESH KUMAR पुत्र श्री SUMER SINGH निवासी- म0नं0-462, एल्डिको सिटी, आईआईएम रोड, भिटौली खुर्द डुगरिया, लखनऊ, कहना चाहता हूँ कि मेरी पुत्री के हाई स्कूल के प्रमाण पत्र पर त्रुटिवश मेरा नाम RAJESH KUMAR SINGH अंकित हो गया है, अत: सबसे अनुरोध है कि मेरी पुत्री को आकांक्षा सिंह पुत्री RAJESH KUMAR के नाम से जाना पहचाना व लिखा जाये।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दीपाली (DEEPALI) पुत्री राम धीरज है जोकि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 3277 5755 2279 में उसका नाम देपिले (depile) अंकित हो गया है, जोकि गलत है। अतरू भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दीपाली (DEEPALI) पुत्री रामधीरज के नाम से जाना व पहचाना जाये। एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं। **राम धीरज पुत्र राम औतार, निवासी-रसूलपुर, थाना-सतरिख, ब्लॉक हरख, जनपद बाराबंकी, उ0प्र0।**

अमृत विचार

गुरुवार, 12 फरवरी 2026

हम खेलना बंद नहीं करते, क्योंकि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं।

–जार्ज बर्नाड शॉ, आइरिश लेखक

डीपफेक पर शिकंजा

एआई के दौर में डीपफेक लोकतंत्र, निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। आईटी नियमों में हालिया संशोधन, डीपफेक और एआई-जनित सामग्री की नई परिभाषाएं, निर्दिष्ट सामग्री को शीघ्रता से हटाने का अनिवार्य प्रावधान नियामकीय ढांचे को ताकत देंगे। ये इस चुनौती से निबटने का सराहनीय प्रयास है। संशोधित नियमों में 'एआई-जनित या सिंथेटिक मीडिया', 'डीपफेक', 'मॉर्फ्ड या मैनिपुलेटेड कंटेंट' और 'भ्रामक लेबलिंग' जैसी स्पष्ट परिभाषाएं शामिल करने के बाद प्लेटफॉर्म का यह तर्क कि सामग्री 'यूजर-जनरेटेड' है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी सीमित है, कुतर्क में बदल गया है। अब यदि कोई ऑडियो-वीडियो एआई जनित है और उसे वास्तविक बताकर प्रसारित किया गया, तो साफ बताना होगा। गंभीर मामलों में शिकायत होने के तीन घंटे के भीतर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को इसे हटाना या निष्क्रिय करना होगा। यह प्रावधान महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, मैसेजिंग सेवाओं, वीडियो-शेयरिंग साइट्स और होस्टिंग प्रदाताओं सभी पर लागू होगा।

आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्लेटफॉर्म को 'सेफ हार्बर' सुरक्षा मिलती है, यानी यूजर की पोस्ट के लिए वे स्वतः दोषी नहीं माने जाते। अब नए नियमों के तहत यदि प्लेटफॉर्म समयबद्ध तरीके से डीपफेक हटाने, लेबलिंग और शिकायत-निवारण अपनाएंगी, तभी उनकी सेफ हार्बर सुरक्षा बचेगी। इसका अर्थ है कि अब उनकी जिम्मेदारी अधिक है और बचाव की गुंजाइश थोड़ी कम, हालांकि इन संशोधनों के बाद भी यह चुनौती बाकी है कि नियम मुख्यतः शिकायत-आधारित हैं, कंटेंट हटाने की प्रक्रिया तब सक्रिय होती है, जब कोई यूजर शिकायत करे और सरकार उस संबंधित सामग्री को फ्लैग करे। डीपफेक का शिकार स्थानीय पुलिस के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करा सकता है, साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है अथवा ग्रिवेंस ऑफिसर को ईमेल के जरिये औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। पर सवाल यह है कि हर यूजर दिन रात इसकी बात पर निगरानी नहीं रख सकता कि वह कब कहां और किस प्लेटफॉर्म पर डीपफेक का शिकार हो चुका है। इस मामले में आम उपयोगकर्ता विकल्पहीन नजर आता है, इसलिए भले ही एआई टूल्स सुलभ हैं और 'क्राइम-एज़-ए-सर्विस' मॉडल ने इसे संगठित अपराध का रूप दे दिया हो, नये नियमों के सख्त लेबलिंग, त्वरित टेकडाउन और ट्रेसबिलिटी से नुकसान को किंचित कम किया जा सके, लेकिन अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्लेटफॉर्म को प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, एआई-आधारित डिटेक्शन और जोखिम-आधारित फ्लैगिंग अपनानी ही होगी। सर्विस प्रोवाइडर समय सीमा में कार्रवाई नहीं करता, तो सेफ हार्बर तत्काल समाप्त होने, भारी जुर्माने के साथ उसके विरुद्ध आपराधिक मामला बनना चाहिए, लेकिन यहां स्पष्ट आर्थिक दंड और पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति तंत्र का अभाव है, जो नियमों को कमजोर बनाएगा। जब तक अनुपालन न करने पर ठोस दंड, जैसे- राजस्व-आधारित जुर्माना, अस्थायी निलंबन या लाइसेंस शर्तें स्पष्ट न हों, तब तक नियमों की प्रभावशीलता सीमित रहेगी।

प्रसंगवश

स्वराष्ट्र, स्वभाषा के पक्षधर थे महर्षि दयानंद सरस्वती

महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे युग पुरुष थे, जिन्होंने सामाजिक कुरीति उन्मूलन, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक समरसता के लिए काम कर समाज सुधार की नई क्रान्ति का सूत्रपात किया। उन्होंने देश में स्वराज्य तथा आजादी की भावना को सुदृढ़ किया। महर्षि दयानंद और उनका आदर्श था- 'कृण्वंतो विश्वमार्यम्' ॥ अर्थात, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ विचारों का, मानवीय आदर्शों का संचार करें, इसलिए, 21वीं सदी में आज जब विश्व अनेक विवादों में फंसा है, हिंसा और अस्थिरता में घिरा हुआ है, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का संचार करता है।

उनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के टंकारा में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मूल शंकर तिवारी था। उनके माता-पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी

सुधांशु टाक

लेखक

समर्पित हिंदू थे। छोटी उम्र में ही उनमें आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित हो गई और उन्होंने मूर्ति पूजा, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों पर प्रश्न उठाए।

19 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन त्यागकर, वे सत्य की खोज में लगभग 15 वर्षों तक एक तपस्वी के रूप में भ्रमण करते रहे। उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने तथा वेदों के सच्चे अर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करने का आग्रह किया। जब महर्षि दयानंद जी का जन्म हुआ, तब देश सदियों की गुलामी से कमजोर पड़कर अपनी आभा, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास, सब कुछ खोता चला जा रहा था। प्रतिपल हमारे संस्कारों को, हमारे आदर्शों को, हमारे मूल्योंर को चूर-चूर करने की लाखों कोशिशें होती रहती थीं। जब किसी समाज में गुलामी की हीन भावना घर कर जाती है, तो आध्यात्म और आस्था की जगह आडंबर आना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया और उन्होंने ये बार-बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है। खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं।

स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वसंस्कृति और स्वतंत्रता के प्रबलतम पक्षधर महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसे दिव्य राष्ट्र पुरुष थे, जिनका संपूर्ण चिंतन और कार्य जहां आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था, वहीं राष्ट्र उनके लिए प्रथम था। महर्षि दयानंद मानते थे कि व्यक्ति की सर्वांगीण उन्नति 'स्व' से ही प्रारंभ होती है। किसी भी क्षेत्र की पराधीनता व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अधोगति का कारण बनती है। पराधीन व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है।

भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए एकदम साफ और बुलंद शब्दों में आवाज उठाने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति महर्षि दयानंद ही थे और इसके लिए कष्ट और अमानवीयता की सीमा तक यातनाएं सहने वाले अधिकांशतः व्यक्ति देव दयानंद के अनुयाई और पथानुगामी ही थे। उसे समय के प्रायः सभी युगपुरुष और महापुरुष जहां कुछ एक क्षेत्र में कार्य करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे थे वहां मात्र महर्षि दयानंद ने संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य किया। अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना से भी पहले सन् 1874 में ऋषि दयानंद सरस्वती ने 'आर्याभिविनय' की रचना की थी। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था- 'अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी शासन न करें। हम कभी पराधीन न हों।'

उत्तराखंड के लिए संजीवनी बनेगी होमस्टे की नीति

अमित शर्मा

हल्द्वानी

पर्वतीय और पर्यटन राज्य की बेशुमार खूबियां समेटे उत्तराखंड के लिए होमस्टे की नयी नीति को किसी संजीवनी से कम नहीं आंका जा सकता है। होमस्टे के कॉन्सेप्ट ने न केवल यहां रोजगार के द्वार खोले हैं, बल्कि अकल्पनीय पर्यटन का विस्तार भी किया है। प्रदेश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे अलग से पहाड़ की लोक संस्कृति, परंपरा, संस्कार और स्थानीय उत्पादों की पहचान देश-विदेश में करवा रहा है। मात्र 10 वर्षों में होमस्टे का प्रचलन राज्य के कोने-कोने में पैर जमाने में सफल हुआ है।

अलग राज्य बनने के बाद प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की थी जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा था और पलायन रोकना ही प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहती आई है। रोजगार के अभाव में प्रदेश में गांव के गांव वीरान होने लगे थे। इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कोई युक्ति नहीं थी, लेकिन करीब दस वर्ष पहले होमस्टे का कॉन्सेप्ट वापसी की लौ बनकर सामने आया। यह देखने में बेहद मामूली नजर आ रहा था, लेकिन रोजगार के साथ पर्यटन के विस्तार का बड़ा मार्ग था। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए और करीब छह बरस पहले इसके महत्व को समझते हुए प्रदेश सरकार ने होमस्टे को आगे ले जाने के लिए युवाओं को इससे जोड़ने व प्रेरित करने का अभियान शुरू कर दिया।

दरअसल, यह पर्यटन की ऐसी अवधारणा थी, जिसमें खर्च न के बराबर और आकर्षण अनूठा था। अधिक कुछ न कर पुराने घरों को संवारना था और पर्यटक के रूप में आने वाले मेहमानों को घर जैसे प्यार के साथ आवभगत करना था। कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जो देश और दुनिया में अलग पहचान रखती है, लेकिन इसका विस्तार तभी संभव था, जब महानगरों से लोग आएं और यहां की संस्कृति, सौहार्द, खान-पान और रहन-सहन की अनुभूति को अनुभव कर सकें।

उत्तराखंड के लिए होमस्टे की नई नीति को किसी संजीवनी से कम नहीं आंका जा सकता। होमस्टे के कॉन्सेप्ट ने न केवल यहां रोजगार के द्वार खोले हैं, बल्कि पर्यटन का विस्तार भी किया है।

प्रदेश के पारंपरिक कुमाऊंनी, गढ़वाली घर मिट्टी-पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। पर्यावरण संरक्षण की झलक और उदाहरण देते प्रतीत होते हैं। पर्यटकों के लिए यह ऐसा आकर्षण और अनुभव है, जो कल्पना से परे होता है। मगर इस अहसास को जगाने के लिए सैलानियों की मौजूदगी बेहद जरूरी थी। इस बीच कोविड महामारी शुरू हो गई। यह महामारी अभिशाप जरूर थी, लेकिन राज्य के होमस्टे का सुहाना सफर यहीं से शुरू हुआ। पलायन कर चुके युवाओं का रिवर्स पलायन शुरू हो गया और उनके लिए उन्हें जब होमस्टे के बारे में पता लगा तो उन्हें अपने सपनों का संसार घर में बसाने का सुनहरा अवसर मिल गया।

एक खास बात यह भी है कि उत्तराखंड की एक विशेष पहचान कुकिंग को लेकर भी रही है। गांव छोड़ महानगरों की शरण लेने वाले लोगों में एक तबका बड़े-नामी होटलों में खाना बनाने में माहिर माने जाते हैं। यह ऐसा हुनर है, जो होमस्टे की सफलता की बुनियाद है। यही वजह है कि वर्तमान में प्रदेशभर में 6545 होमस्टे सफलता के साथ संचालित हो रहे है और 20 हजार से अधिक लोग इन होमस्टे में आजीविका कमाने के साथ अपनी जड़ों से वापस जुड़ रहे हैं।

इसमें जरा भी संदेह नहीं कि उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता दुनिया में अलग और बेपनाह खूबसूरत है। इधर, होमस्टे ने जहां रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाया, वहीं प्रदेश की तमाम खूबियों के चलते देश-विदेश के लोगों के प्रति आकर्षण पैदा किया है। देवभूमि की बड़ी विशेषता यहां का भोजन है, जो औषधि का काम करता है। गहत और भट्ट की दाल और राजमा का कोई सानी नहीं। इसके अलावा बिच्छू समेत पहाड़ी सब्जियों का भंडार ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध है, जो शहरों की हाईब्रिड सब्जियों से कहीं अधिक उत्तम व ऑर्गेनिक है। भाग दौड़ भरी जिंदगी से पहाड़ों का सुकून व शांति का वातावरण पर्यटकों को बेहद भाने लगा है। आदर सत्कार, स्नेह, प्रेम और संस्कार, जो होटलों में संभव नहीं, वह होमस्टे में मिलता है। कम खर्च और ढेर सारी मौज-मस्ती का आनंद होमस्टे में मिल जाता है। यही वजह है कि वर्तमान में होटलों की जगह होमस्टे की मांग बढ़ने लगी है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने बीते माह होमस्टे योजना को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अहम बदलाव किए। इसके अनुसार, अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही होमस्टे योजना का लाभ उठा सकते हैं, हालांकि अन्य राज्यों के होम स्टे संचालक बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में शामिल होंगे, जिन्हें जीएसटी और व्यावसायिक दरों पर बिजली-पानी मिलेगा। नई 'उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026' का स्पष्ट उद्देश्य स्थानीय निवासियों के हितों की रक्षा करना है।

इस योजना के बड़े फायदों में, स्थानीय निवासियों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और रिवर्स पलायन में यह योजना संजीवनी का काम करेगी। पहाड़ की जवानी पहाड़ के ही काम आएगी। स्थानीय होने के चलते वे स्वयं पहाड़ व अपने आसपास की संस्कृति, विशेषताओं से मेहमान पर्यटकों को बता सकेंगे। स्थानीय होम स्टे संचालकों को बिजली और पानी की सुविधा घरेलू दरों पर मिलने से उनकी लागत भी कम होगी।

पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी कहते हैं कि होमस्टे दूरदराज के ग्रामीण अंचल के लिए किसी वरदान से कम नहीं। प्रदेश की बड़ी आबादी दूर गांवों में रहती है, जहां रोजगार के रूप में होमस्टे लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है। होमस्टे खोलने को लेकर सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है, तो बैंक से मिलने वाले ऋण में बैंक ब्याज में 50 फीसद छूट दे रहा है। होमस्टे ने रिवर्स पलायन में बड़ी भूमिका निभाई है। ग्रामीण विकास और पलायन आयोग की रिपोर्ट 2025 के अनुसार 6000 से अधिक प्रवासी अपने गांवों में लौटकर अधिकांश होमस्टे का स्वरोजगार कर रहे हैं।

आमने

आपने भारत बेच दिया है। क्या आपको भारत बेचने में शर्म नहीं आती? आपने हमारी मां, भारत माता को बेच दिया है। आपको पता है उन्होंने भारत क्यों बेचा? क्योंकि वे उनका गला घोंट रहे हैं। उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं।

–राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष

सामने

आपने कहा कि इन्होंने देश बेच दिया, पर मैं कहना चाहता हूं कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, जो देश को बेच सके और न कोई है जो हमारे देश को खरीद सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

–किरेन रिजिजू
संसदीय कार्यमंत्री

बजट: चुनावी रेवड़ियों की जगह मजबूत रोडमैप

मनोज त्रिपाठी

कानपुर

उत्तर प्रदेश में 2027 के पूर्वार्द्ध में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट उम्मीदों के विपरीत चुनावी घोषणाओं, लोक लुभावन योजनाओं और मुफ्त की रेवड़ियों से परहेज करता हुआ जनता के उस विश्वास का दस्तावेज जैसा लगता है, जिसे सरकार ने नौ सालों में पूरी शिद्दत के साथ अर्जित किया है। इसी कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 का सरकार का बजट जो कि 9,12,696 करोड़ रुपये के साथ आकार में अब तक का सबसे बड़ा है, वित्तीय लेखा-जोखा से ज्यादा, सरकार की आर्थिक सोच, राजनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक क्षमताओं का बखान करने के साथ स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी और रणनीतिक रहते हुए विकसित यूपी का रोडमैप प्रस्तुत करता है।

यदि समग्र आकार और संरचना पर नजर डालें, तो यह बजट पिछले वर्षों की तुलना में अधिक विस्तारवादी है। कुल परिव्यय पिछले साल की तुलना में करीब 12.2 फीसदी ज्यादा है। इसके साथ ही वित्तीय अनुशासन और पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर खास फोकस है। पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में वृद्धि के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि प्रदेश केवल कल्याणकारी योजनाओं पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे पर भी निवेश कर रहा है। एक्सप्रेस-वे, मेट्रो विस्तार, डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क, एग्री-एक्सपोर्ट हब, नए मेडिकल कॉलेज, एआई मिशन, प्लेसमेंट सेंटर्स आदि, ये सब मिलकर उस नए उत्तम प्रदेश की तस्वीर पेश करते हैं, जिसे सरकार निवेश-हितैषी और आधुनिक बनाना चाहती है, हालांकि पूंजीगत व्यय के साथ राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना आसान नहीं होता। यदि राज्य का कर्ज अनुपात बढ़ता है, तो भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ बढ़ सकता है। सरकार ने इसे लेकर संतुलन का दावा किया है, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर निर्भरता को देखते हुए उसे वित्तीय प्रबंधन की परीक्षा देना अभी बाकी है।

सरकार जब प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एक लाख 20 हजार होने और छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का आंकड़ा पेश करती है, तो यह बताना नहीं भूलती कि अर्थव्यवस्था का हाल पहले क्या था और किस तरह वह राज्य की अर्थव्यवस्था को एक डॉलर ट्रिलियन बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। इसी क्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का यह बताना कि उत्तर प्रदेश देश की तीन टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में प्रदेश की रैंकिंग 2018-19 में 29वें स्थान से सुधरकर 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है।

फरवरी 2024 में आयोजित चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार पैदा होने की संभावना है। अब तक 16 हजार से ज्यादा परियोजनाओं के लिए लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी हैं, तो योगी सरकार के इसी दावे पर मुहर लगती है कि उसके पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश या रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तीकरण हो या युवाओं का कौशल संवर्धन, किसानों की खुशहाली हो या गरीबी उन्मूलन। इन सारी बातों से सरकार यही संदेश हर किसी तक पहुंचाना चाहती है कि अब तक की बदलाव की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इस बार का बजट भी प्रदेश के संतुलित विकास, विशेषकर युवाओं और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, ताकि राज्य को देश की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाया जा सके।

बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित किया गया है। विशेष रूप से सड़कों और फ्लाईओवर के निर्माण पर 34,468 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे प्रदेश में एक्सप्रेसवे, मुख्य राजमार्ग, बाईपास, ग्रामीण सड़कों और पुलों के विस्तार पर तेजी से काम होगा। फिलहाल प्रदेश में सात एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक दौड़ रहा है, तीन एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। अब चार और नए एक्सप्रेसवे बनने की घोषणा से सरकार का इरादा साफ है कि प्रदेश के हर जिले को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, ताकि परिवहन सुविधाएं मजबूत हों और आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, क्योंकि यही वह बिंदु है, जिससे लोगों में विकास होने की आम राय बनती है।

निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। बेहतर सड़क नेटवर्क से औद्योगिक क्षेत्रों तक माल की ढुलाई आसान होने से लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है और व्यापार-कारोबार बढ़ता है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में सड़कों के विस्तार से किसानों की बाजार तक पहुंच आसान होने से उनकी आय में सुधार आ सकता है। बजट का दूसरा सबसे प्रमुख हिस्सा टेक्नोलॉजी और एआई मिशन है, जिसमें राज्य को आईटी हब बनाने का संकल्प है।

यूपी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट उम्मीदों के विपरीत चुनावी घोषणाओं से परहेज करता हुआ जनता के विश्वास का दस्तावेज जैसा लगता है।

सोशल फोरम

फिर चित्रा ने नहीं गाया

1975-76 के लगभग जगजीत-चित्राजी का पहला LP रिकार्ड Unforgettables आया, उसके बाद ही हिंदुस्तान में ही नहीं, एक हद तक पाकिस्तान में भी गज़ल गायकी का जैसे ट्रेंड ही बदल गया। उस समय ग़ज़ल गायकी में ग्रेट मेंहदी हसन बहुत बड़ा नाम थे और भारत में तलत महमूद थे और भी बड़े-बड़े शास्त्रीय ग़ज़ल गायक थे

रश्मि त्रिपाठी

ब्लॉगर

उस दौर के, किंतु जगजीत सिंह एक ऐसा नाम उभरा जो जीवन का अंत होने के समय तक निरंतर शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ता चला गया। बिना इस बात की परवाह किए कि बाकी गायक कितने बड़े और शोहरतमंद हैं?

अपनी सरल गायकी और मखमली आवाज़ के बल पर जगजीत सिंह न केवल खुद जन-जन के प्रिय होते चले गए, अपितु उन्होंने ग़ज़ल को भी अपार लोकप्रियता दिलाई। ग़ज़ल जो कुछ 'एलीट क्लास' की बैठकों के शौकीनों की शोभा मात्र हुआ करती थीं, अब आम लोगों में गुनगुनाने की चीज़ बन गई। बात यहां तक आ गई कि लोकप्रिय फिल्मी गीतों की तुलना में भी जगजीत जी को अधिक शोहरत मिलने लगी।

कुछ वर्षों के इस सफर के बाद जगजीत सिंह को हिंदी सिनेमा में गाने का मौका भी मिल गया। 'तुम इतना जो मुस्करा रहे हो' या फिर 'होठों से छू लो तुम,मेरा गीत अमर कर दो' जैसे अनेक कालजयी फिल्मी गाने जगजीत सिंह की गायकी और उन्हीं की मौसिक़ी से निकले थे। इससे पहले 1967 में जब जगजीत काम ढूंढ रहे थे, तब उनकी मुलाकात चित्रा दत्ता से हुई। चित्रा उस वक्त शादीशुदा थीं। वो मुंबई में जहां रहती थीं। उनके सामने वाले घर में जगजीत का आना-जाना लगा रहता था और यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई थी।

धीरे धीरे वे एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे और अलग सी बात ये थी कि जगजीत ने उनके पति देबू प्रसाद दत्ता से उन्हे मांग लिया था। दिसंबर 1969 में चित्रा ने अपने पति को तलाक देकर जगजीत सिंह से शादी कर ली। कहते हैं कि देबू दत्ता का भी कहीं और अफेयर था, इसलिए उनको भी तलाक में सुविधा हो गई।

चित्रा-जगजीत दोनों एक साथ एक के बाद एक कॉन्सर्ट लगातार करते जा रहे थे। शोहरत-दौलत दिन-दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। साल 1980 तक जगजीत सिंह गजल किंग बन चुके थे। इसी समय उनके एक मात्र पुत्र विवेक की 1990 में एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। दोनों ने गाना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद जगजीत सिंह तो रोमांटिक न सही, लेकिन थोड़े बदले मिज़ाज़ के गीत-गजल गाने लगे, लेकिन चित्रा ने फिर नहीं गाया। **–फेसबुक वॉल से**

सामयिकी

ईयू-यूएस से व्यापारिक समझौता सुनहरा मौका

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अब भारतीय निर्यातकों को 50 प्रतिशत शुल्क के स्थान पर सिर्फ 18 प्रतिशत शुल्क ही देना होगा, किंतु यह भी सत्य है कि पहले यह शुल्क मात्र 2.9 प्रतिशत ही था। यह दोनों समझौते भारत को विश्व पटल पर मजबूत स्थिति में खड़ा होने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते को सभी समझौतों की जननी कहा जा सकता है, तो भारत-अमेरिका व्यापार समझौता सभी समझौतों का जनक माना जा सकता है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया जाने वाला शुल्क अब 18 प्रतिशत रह जाएगा, हालांकि भारतीय यूरोपीय संघ समझौता अपने आप में महत्वपूर्ण है, किन्तु भारत द्वारा अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार अमेरिका से निर्यात को विविधतापूर्ण बनाना भी एक कठिन प्रयास था, जिसमें भारत को अंततः सफलता प्राप्त हुई। यह समझौता

प्रो. रिपुदमन सिंह

शिक्षाविद्

न केवल भारत की व्यापार स्थिति को बहाल करेगा, बल्कि दशकों पुराने भारत-अमेरिका राजनयिक संबंधों को भी मजबूत करेगा, जिनमें हाल ही में तनाव के संकेत दिखाई दिए थे।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते ने भारतीय उद्योगों को राहत की सांस लेने का मौका प्रदान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा भी चुनौतीपूर्ण है, भारत को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रूसी तेल पूरी तरह बंद करने पर भारत को अपने एक तिहाई तेल की आपूर्ति के लिए विकल्प तलाशना होगा तथा रूस के साथ भारत के संबंध पर भी असर पड़ेगा। रूस भारत का लंबे समय से मित्र और रक्षा उपकरणों का महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। यह कदम भारत के लिए संबंधों को पुनर्गठन करने जैसा होगा। इसी तरह वेनेजुएला से अधिक कच्चा तेल खरीदना शोधन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न करेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि भारत ने अमेरिका को टैरिफ रियायतों निवेशों और खरीद आदेशों के संदर्भ में क्या प्रतिबद्धतायें निर्धारित की हैं, क्योंकि ट्रंप और उनकी टीम, संवेदनशील कृषि उत्पादों और डेयरी उत्पादों के आदान-प्रदान किए जाने का दावा कर रहे हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्री ने ट्रंप के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है, लेकिन अमेरिकी व्यापार समझौते ने एक उम्मीद की किरण तो दी है, क्योंकि इससे शेयर बाजारों में तेजी आई है, रुपये को मजबूती मिली है और कपड़ा, परिधान, चमड़ा, जूते और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम प्रधान उद्योगों में उत्साह का माहौल है।

व्यापार के मोर्चे पर भारत के वस्त्र और चमड़ा निर्यातकों को त्वरित लाभ मिलने की संभावना है। वर्तमान में खेल सामग्री, रत्न और आभूषणों के निर्यातकों को उच्च टैरिफ के चलते कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और यह निर्यातक 10-20 प्रतिशत तक नुकान उठा रहे थे। यह डैडम् क्षेत्र में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत वस्त्र और परिधान का 28 प्रतिशत निर्यात अमेरिका को करता है, जो भारतीय चमड़े और खेल सामग्री का भी बहुत बड़ा बाजार है। भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता भारत के इतने बड़े निर्यात को इतनी जल्दी समायोजित करने की स्थिति में संभवतः नहीं था, किंतु एक वैकल्पिक व्यवस्था बनने की स्थिति में जरूर आगे आ सकता है। अमेरिकी रणनीतिकार संभवतः इसी संभावना को भांपने में सफल रहे हैं और भारत-अमेरिका समझौते को अति शीघ्र लागू करने के लिए तत्पर हो गए हैं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता का एक व्यापक रणनीतिक उद्देश्य भी है, यह द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने में भी मदद करेगा, जो नागरिक परमाणु समझौते के बाद से लगातार मजबूत होते गए हैं।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक त्रिनाथ शुक्ला द्वारा 25/16-ए, जाप्लिंग रोड, लखनऊ-226001 (उ.प्र.) से प्रकाशित एवं प्लाट नं.-42, निकट बद्री नगर,इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज, लखनऊ-226008 (उ.प्र.) से मुद्रित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, कार्यकारी संपादक- अनिल त्रिगुणायत***

0522-4008111 (कार्यालय), ईमेल-editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-50986/1989 *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा)।

वर्ड स्मिथ

कैसे बना शैंपू शब्द

आज शैंपू हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य शब्द बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जन्म भारत में हुआ और यह शब्द हिंदी-उर्दू नहीं, बल्कि संस्कृत मूल से होकर अंग्रेजी तक पहुंचा। 'शैंपू' शब्द की कहानी औपनिवेशिक भारत, आयुर्वेद और पश्चिमी संस्कृति के आपसी संपर्क से जुड़ी है। 'शैंपू' शब्द की जड़ संस्कृत के शब्द 'चम्पू' (Champu) में मिलती है। 'चम्पू' का अर्थ होता है-दबाना, मलना या मालिश करना। प्राचीन भारत में सिर और शरीर की तेल मालिश को 'चम्पू' कहा जाता था। यह केवल सौंदर्य का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। आयुर्वेद में सिर की मालिश को तनाव दूर करने, रक्तसंचार बढ़ाने और बालों को स्वस्थ रखने का प्रभावी उपाय माना गया है।

17वीं-18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश व्यापारी और अधिकारी भारत आए, तो उन्होंने यहां की मालिश और स्नान पद्धतियों को देखा। बंगाल में 'चम्पू' एक प्रचलित प्रक्रिया थी, जिसमें जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक तत्वों से सिर की सफाई और मालिश की जाती थी। अंग्रेजों ने इस शब्द को अपने उच्चारण के अनुसार 'Shampoo' कहना शुरू कर दिया। सन 1762 में यह शब्द पहली बार अंग्रेजी शब्दकोश में दर्ज हुआ। शुरुआत में 'शैंपू' का अर्थ केवल सिर की मालिश या शरीर को मलने की क्रिया था, न कि किसी तरल पदार्थ का नाम। बाद में, 19 वीं शताब्दी में जब तरल साबुन और बाल धोने वाले उत्पाद विकसित हुए, तब इस प्रक्रिया से जुड़े उत्पाद को ही 'शैंपू' कहा जाने लगा। इस प्रकार, 'शैंपू' केवल एक कॉस्मेटिक उत्पाद नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की देन है, जो संस्कृत से चलकर औपनिवेशिक रास्तों से होती हुई पूरी दुनिया की भाषाओं में शामिल हो गई। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि भारतीय परंपराओं का वैश्विक प्रभाव कितना गहरा और स्थायी रहा है।

नोटिस बोर्ड

- बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें रोजगार पाने के लिए बहुत जल्द सुनहरा अवसर मिलेगा। जिला सेवा योजन विभाग, अमेठी की ओर से 26 फरवरी को आरआरपीजी कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 50 से अधिक नामी कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। मेले के माध्यम से 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मेले में कक्षा आठवीं पास से लेकर स्नातक, परास्नातक, बीटेक, आइटीआइ और पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि मौके पर ही साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा साथ ले जाएं।

- बरेली कॉलेज के ललितकला विभाग ने बीए प्रथम सेमेस्टर चित्रकला विषय की प्रयोगात्मक परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विभागीय सूचना के अनुसार बैक और रेगुलर दोनों श्रेणी के विद्यार्थियों की परीक्षा 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। परीक्षा ललितकला विभाग में ही संपन्न होगी। विभाग के प्रभारी प्रो. एबीएल. लखटकिया ने छात्रों को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा के दिन निर्धारित समय से कम से कम आधा घंटा पहले विभाग में उपस्थित रहें, ताकि सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें और परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो।

राजेश जैन
लेखक

75% कॉलेज छात्रों को नहीं दे पा रहे जॉब वाली स्किल्स

भारत में हर साल लाखों युवा बड़े सपनों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं। परिवार उम्मीद करता है कि चार साल की पढ़ाई के बाद बच्चा अच्छी नौकरी पाएगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और समाज में सम्मान पाएगा, लेकिन आज की सच्चाई यह है कि डिग्री मिलने के बाद भी नौकरी मिलना किसी जुए से कम नहीं रह गया है। टीमलीज एडटेक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत के करीब 75 प्रतिशत कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने छात्रों को जॉब-रेडी स्किल्स देने में नाकाम हो रहे हैं। यानी डिग्री तो मिल रही है, लेकिन नौकरी के लायक नहीं है। यह सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

डिग्री की फैक्ट्रियां बनते जा रहे हैं कॉलेज

आज बड़ी संख्या में संस्थान सिर्फ डिग्री बांटने वाली फैक्ट्रियों में बदल चुके हैं। क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाई जाती है, पुराने सिलेबस रटाए जाते हैं, लेकिन असली दुनिया की जरूरतों से छात्रों का कोई संपर्क नहीं होता। नतीजा यह होता है कि छात्र पास होकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें यह तक नहीं पता होता कि इंडस्ट्री उनसे क्या चाहती है। आज कंपनियों को ऐसे युवा चाहिए जो टेक्नोलॉजी समझते हों, कम्युनिकेशन में मजबूत हों, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हों, लेकिन ज्यादातर कॉलेज इन स्किल्स पर काम ही नहीं करते।

प्लेसमेंट का कड़वा सच

कागजों में कई संस्थान 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ 16.67 प्रतिशत संस्थान ही ऐसे हैं, जो अपने 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत छात्रों को छह महीने के भीतर नौकरी दिला पाते हैं। बाकी छात्रों को या तो बहुत कम सैलरी वाली नौकरी मिलती है या फिर वे बेरोजगार घूमते रहते हैं या किसी दूसरे कोर्स की तैयारी करने लगते हैं। यह स्थिति उन माता-पिता के लिए भी चिंता का विषय है, जो भारी फीस भरकर बच्चों को प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाते हैं। इंडस्ट्री और पढ़ाई के बीच गहरी खाई आज की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही है कि पाठ्यक्रम और उद्योग की जरूरतों में तालमेल नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 8.6 प्रतिशत संस्थानों के कोर्स पूरी तरह इंडस्ट्री-फ्रेंडली हैं, 51 प्रतिशत से ज्यादा संस्थानों का उद्योग से कोई तालमेल ही नहीं। मतलब आधे से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं, जहां पढ़ाया कुछ और जाता है और नौकरी में चाहिए कुछ और।

क्लासरूम में इंडस्ट्री का अनुभव नदारद

अगर कॉलेजों में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाएं, तो छात्रों को असली दुनिया की समझ मिले, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 7.56 प्रतिशत संस्थानों में ही 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' जैसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया है। बाकी जगह वही पुराने प्रोफेसर, वही पुराने नोट्स, वही पुरानी थ्योरी। छात्रों को यह नहीं बताया जाता कि आज जॉब मार्केट कैसे बदल रहा है, नई भूमिकाएं क्या हैं, कंपनियां किस तरह की स्किल्स ढूंढ रही हैं।

सर्टिफिकेट्स से दूरी

आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखतीं, वे मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री सर्टिफिकेट्स को भी महत्व देती हैं। जैसे-एआई और डेटा साइंस सर्टिफिकेट, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, 60 प्रतिशत से ज्यादा संस्थानों ने इन सर्टिफिकेट्स को अपने कोर्स में शामिल करने पर कभी सोचा ही नहीं। नतीजा ये हुआ छात्र ऐसे स्किल्स के बिना ग्रेजुएट होते हैं, जिन्हें कंपनियां तुरंत पहचान सकें।

इंटर्नशिप: नाम की, काम की नहीं

नौकरी से पहले इंटर्नशिप सबसे जरूरी कदम होती है। यहीं से छात्र सीखते हैं-ऑफिस कल्चर, टीमवर्क, असली प्रोजेक्ट पर काम, लेकिन भारत में सिर्फ 9.4 प्रतिशत संस्थानों में सभी कोर्स के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप होती है और 37.8 प्रतिशत संस्थानों में इंटर्नशिप की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यानी लाखों छात्र बिना किसी प्रैक्टिकल अनुभव के सीधे जॉब मार्केट में उतर जाते हैं। फिर कंपनियां कहती हैं-आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है।

लाइव प्रोजेक्ट्स भी गायब

लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स छात्रों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ 9.68 प्रतिशत संस्थानों में ही ऐसे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं। बाकी जगह थ्योरी पढ़ाओ, एग्जाम लो, डिग्री दो और मामला खत्म।

एलुमनाई नेटवर्क की कमजोरी

पूर्व छात्र किसी भी संस्थान की ताकत होते हैं। वे मेंटरशिप दे सकते हैं, रेफरल दिला सकते हैं, जॉब के मौके खोल सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 5.44 प्रतिशत संस्थानों के पास सक्रिय एलुमनाई नेटवर्क है। यानी कॉलेज अपने ही पुराने छात्रों की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।

इसका असर सिर्फ छात्रों पर नहीं, देश पर भी-जब युवा बेरोजगार रहते हैं, तो इसका असर सिर्फ परिवार पर नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उत्पादकता घटती है, मानसिक तनाव बढ़ता है, स्किल गैप बढ़ता है, माइग्रेशन बढ़ता है, डिग्रीधारी बेरोजगारी, देश के लिए सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है।

यह है समाधान

रिपोर्ट साफ कहती है कि अब बदलाव विकल्प नहीं, मजबूरी है। इसके लिए इंडस्ट्री-अनुकूल सिलेबस, अनिवार्य इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की भागीदारी, सर्टिफिकेट कोर्स, मजबूत एलुमनाई नेटवर्क, कॉलेजों को सिर्फ पढ़ाने की नहीं, रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी।

सरकार की भूमिका भी अहम

नई शिक्षा नीति सही दिशा में कदम है, लेकिन जमीन पर उसका असर अभी सीमित है। सरकार को चाहिए कि कॉलेजों की जवाबदेही तय करे, प्लेसमेंट डेटा पब्लिक करे, स्किल-बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दे, इंडस्ट्री पार्टनरशिप अनिवार्य बनाए, छात्रों को भी जागरूक होना होगा। आज का छात्र सिर्फ डिग्री पर निर्भर नहीं रह सकता। उसे खुद भी ऑनलाइन स्किल्स सीखनी होंगी, इंटर्नशिप ढूंढनी होगी, नेटवर्क बनाना होगा, इंडस्ट्री ट्रेंड समझना होगा। अगर भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम आज नहीं सुधरा तो आने वाले सालों में डिग्रियों की भीड़ होगी, लेकिन नौकरियों की कमी। यह संकट सिर्फ शिक्षा का नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकट है। अब वक्त है डिग्री फैक्ट्रियों को रोजगार केंद्रों में बदलने का।

कैंपस में पहला दिन

जीवन को सोचने व समझने की यात्रा

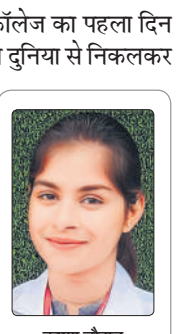

कृष्णा चौहान
बीएससी छात्रा, एसएस कॉलेज, शाहजहांपुर

आज भी स्मृतियों में किसी ताजी सुबह की तरह कॉलेज का पहला दिन चमकता है। स्कूल की सुरक्षित और जानी-पहचानी दुनिया से निकलकर बीएससी की छात्रा के रूप में कॉलेज की देहरी पर कदम रखना मेरे लिए उत्साह और संकोच दोनों का मिला-जुला अनुभव था। हाथ में नई फाइल, कंधे पर बैग और मन में अनगिनत सवाल, क्या मैं यहां अपने सपनों के करीब पहुंच पाऊंगी?

कॉलेज का विशाल परिसर देखते ही मन आश्चर्य से भर उठा। ऊंची इमारतें, हरे-भरे पेड़, भागते हुए छात्र, कहीं हंसी की आवाजें तो कहीं गंभीर चेहरों पर किताबों का बोझ, सब कुछ नया था। विभाग की ओर बढ़ते कदमों के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। बीएससी की छात्रा होने का गर्व तो था, लेकिन साथ ही यह डर भी कि विज्ञान जैसे गंभीर विषय को संभाल पाऊंगी या नहीं। पहली कक्षा का अनुभव कभी नहीं भूल सकती। प्रयोगशाला में रखे चमकते उपकरण, रसायनों की हल्की गंध और दीवारों पर टंगे वैज्ञानिकों के चित्र मुझे एक अलग ही दुनिया में ले गए। जब पहली बार अध्यापक ने अपना परिचय दिया और विषय की महत्ता समझाई, तब महसूस हुआ कि यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन के सोचने और समझने की एक नई यात्रा है। सबसे सुकून देने वाला पल तब आया, जब कुछ अनजान चेहरे मुस्कान में बदल गए। पास बैठी छात्रा से हुई छोटी-सी बातचीत दोस्ती की शुरुआत बन गई। लगा जैसे डर धीरे-धीरे आत्मविश्वास में बदल रहा हो। कैंटीन की पहली चाय और हल्की-फुल्की बातचीत ने उस दिन को और यादगार बना दिया।

शाम को कॉलेज से लौटते समय मन में थकान नहीं, बल्कि एक अजीब-सी खुशी थी। लगा, जैसे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं, तो समझ में आता है कि वह पहला दिन सिर्फ कॉलेज का नहीं था, बल्कि मेरे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम था, जो आज भी मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

करेंट अफेयर्स

- हाल ही में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम और कड़े हो गए हैं। संशोधित आईटी नियम 2021 के तहत अब एआई-जनित (AI-generated) सामग्री पर "स्पष्ट और प्रमुख" लेबल लगाना अनिवार्य होगा और अवैध सामग्री हटाने की समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर केवल तीन घंटे कर दी गई है। ये बदलाव 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे।
- भारत और सेशेल्स के द्विपक्षीय संबंध एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंचा गए हैं। हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सततता, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए सुदृढ़ संपर्कों के माध्यम से संयुक्त दृष्टि (SESEL) की घोषणा की। यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और एक करीबी समुद्री साझेदार के रूप में सेशेल्स के महत्व को रेखांकित करती है, जिसमें सुरक्षा, विकास और जन-केंद्रित सहयोग को केंद्र में रखा गया है।
- हाल ही में नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजना पेश की है। इस नीति ब्लूप्रिंट का उद्देश्य वर्ष 2035 तक आंध्र प्रदेश को भारत के प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलना है। घटती बिजली लागत और बड़े क्षमता विस्तार के साथ आंध्र प्रदेश को भविष्य में देश के लिए स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है।
- हाल ही में वैश्विक खेल प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य का चुनाव किया है। ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया अघाई हाजिआगहा को 4 फरवरी इटली के मिलान में आयोजित 145 वें IOC सत्र के दौरान निर्वाचित किया गया। इस चुनाव के साथ ही वे IOC की वर्तमान सबसे कम उम्र की सदस्य भी बन गई हैं।
- भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। यह उपलब्धि उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में सातवां स्थान हासिल करने के पांच दिन बाद दर्ज की। डबल शूट-ऑफ के बीच मनु ने मानसिक मजबूती दिखाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। यह 25 मीटर पिस्टल में उनका पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल है।

जॉब अलर्ट

एम.पी. राज्य सहकारी बैंक

- पद का नाम-कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा), सोसायटी मैनेजर, अधिकारी
- पदों की संख्या- (1763 क्लर्क + 313 अधिकारी) 2076 पद
- सैलरी/पे स्केल क्लर्क : लेवल-4 (Rs. 19,500-62,000) 7 वां पे स्केल / लेवल-7 (Rs. 28,700-91,300) / 6 वां पे स्केल (Rs. 5,200-20,200 + 1900 GP)
- शैक्षणिक योग्यता-स्नातक
- आयु सीमा -18 से 35 वर्ष (40 वर्ष छूट के साथ), कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा) : 18 से 55 साल
- आवेदन की अंतिम तिथि- 20 फरवरी 2026
- वेबसाइट-www.apexbankmp.bank.in

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग

- पद का नाम- ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती (विभिन्न विभाग / बोर्ड / निगम)
- सीईटी ग्रुप सी पर आधारित- विज्ञापन नंबर 01/2025 क्वॉलिफाइड कैंडिडेट
- पदों कि संख्या -4227
- एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख- 9 फरवरी 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि- 23 फरवरी 2026
- ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

- पद का नाम- डिप्टी जनरल मैनेजर (इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स), डिप्टी जनरल मैनेजर (माइक्रोवेव), दूसरे पोस्ट (डिप्टी इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, वगैरह
- पदों की संख्या- 34
- विज्ञापन नंबर 118/Pers/1/2026
- सैलरी- Rs.17,500 - 2,20,000/- हर महीने
- क्वालिफिकेशन- B.E./B.Tech / MBA / CA/ ICWA / ग्रेजुएट / 10th
- एज लिमिट- पदानुसार
- आवेदन की अंतिम तिथि- 3 फरवरी 2026
- वेबसाइट- https://www.celindia.co.in

बोर्ड परीक्षा से पहले सफलता का स्मार्ट स्टडी प्लान

डॉ. मनोज कुमार तिवारी
बीएचयू

बीते दिनों परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कुशल मनोवैज्ञानिक की भांति विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा की, उन्होंने सीधे परीक्षा तनाव पर चर्चा करने के बजाय छात्रों के जीवन व उनके क्षेत्र से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की, जिससे छात्र उनसे सीधे जुड़ सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर छात्र अद्वितीय हैं, उनकी अपनी क्षमता, विशेषता, जीवनशैली, सोचने-समझने का ढंग अलग-अलग होता है, इसलिए विद्यार्थियों का परीक्षा की तैयारी का तरीका अलग-अलग हो सकता है। उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी परीक्षा की तैयारी अपने ढंग से करनी चाहिए, सभी के सुझाव को सुनना चाहिए, किंतु अपनी तैयारी का पैटर्न अपने अनुभव के अनुसार तय करना चाहिए। यूपी बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं।

इन दिनों में परीक्षार्थियों को विशेष ध्यान रखते हुए परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। आइए आज आपको बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सुझाव, जिन्हें अपनाकर आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं।

सिलेबस के अनुसार बनाएं स्टडी प्लान

सबसे पहले एक सरल और व्यावहारिक टाइम टेबल तैयार करें। यह बहुत जटिल नहीं होना चाहिए। दिन के अलग-अलग समय के अनुसार विषय तय करें। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इस समय कठिन विषयों का अध्ययन करें। दोपहर में हल्के टॉपिक और शाम के समय रिवीजन पर ध्यान दें।

जरूरी टॉपिक पर करें फोकस

जब बोर्ड परीक्षा में कुछ ही दिन शेष हों, तब नया पाठ्यक्रम शुरू करने के बजाय महत्वपूर्ण अध्यायों पर ध्यान देना समझदारी है। सिलेबस में शामिल मुख्य चैप्टर और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करें। जिन टॉपिक से बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह तैयार करें। अगर कोई अध्याय पूरा नहीं आता है, तो उसे छोड़ने के बजाय उसके आसान हिस्सों को जरूर पढ़ लें।

प्रश्नों की लिखकर करें प्रैक्टिस

पढ़ी हुई सामग्री को बार-बार दोहराना बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम एक बार रिवीजन करें। साथ ही लिखकर अभ्यास करने से उत्तर लेखन की गति बढ़ती है और परीक्षा के समय समय-प्रबंधन में मदद मिलती है। गणित, विज्ञान और अकाउंट्स जैसे विषयों में यह तरीका विशेष रूप से लाभकारी होता है।

मॉक टेस्ट देना न भूलें

पुराने प्रश्नपत्र और फुल मॉक टेस्ट बोर्ड परीक्षा की तैयारी का सबसे बेहतर साधन हैं। छात्रों को सप्ताह में कम से कम दो से तीन फुल-लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए। इससे परीक्षा के माहौल की आदत बनती है। टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने पर काम करें।

तनाव से दूर रहें, बनाए रखें आत्मविश्वास

परीक्षा से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक तनाव पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। छात्रों को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। पूरे साल की गई मेहनत अंतिम समय में जरूर रंग लाएगी।

बाजार	सेंसेक्स ↓	निफ्टी ↑
बंद हुआ	84,233.64	25,953.85
गिरावट/बढ़त	40.28	18.70
प्रतिशत में	0.05	0.07

सोना 1,61,300 प्रति 10 ग्राम

चांदी 2,68,500 प्रति किलो

अमृत विचार

लखनऊ, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

www.amritvichar.com

बिजनेस ब्रीफ

अकासा एयर के सह-संस्थापक प्रवीण अय्यर का इस्तीफा

नई दिल्ली। अकासा एयर के सह-संस्थापक एवं मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी प्रवीण अय्यर ने इस्तीफा दे दिया है। एयरलाइन कंपनी में चार महीने के भीतर वरिष्ठ स्तर पर यह दूसरा इस्तीफा है। अकासा एयर ने बुधवार को कहा कि पांच वर्ष की उल्लेखनीय यात्रा के बाद अय्यर ने अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। वह कामकाज का सुचारू एवं व्यवस्थित हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए 30 अप्रैल, 2026 तक नेतृत्व दल के साथ मिलकर का करेंगे। अय्यर, नीलू खत्री के बाद कंपनी छोड़ने वाले दूसरे सह-संस्थापक हैं।

टोटलएनर्जीज ने एजीईएल में 1.7% हिस्सेदारी बेची

नई दिल्ली। फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटलएनर्जीज ने कहा कि उसने 2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) में 1.7% हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी ने कहा कि उसने अक्टूबर-दिसंबर, 2025 के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री से 2.08 अरब डॉलर जुटाए। टोटलएनर्जीज के मुताबिक, इन विनिवेश में नाइजीरिया के बोंगा क्षेत्र में गैर-संचालित हिस्सेदारी की बिक्री, मलेशिया के ब्लॉक एसके408 में आंशिक हिस्सेदारी की बिक्री, अमेरिका और यूनान में अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो में 50% हिस्सेदारी की बिक्री तथा अडाणी ग्रीन एनर्जी में 1.7% की बिक्री शामिल है।

दुबई हवाई अड्डे से 9.52 करोड़ यात्रियों ने किया सफर

दुबई। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 2025 में भी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 2025 में रिकॉर्ड 9.52 करोड़ यात्रियों ने टर्मिनल से सफर किया, जो अमीरात की जारी आर्थिक तेजी को दर्शाता है। वैश्विक महामारी के बाद के वर्ष में हवाई अड्डे की गतिविधियों में तेज उछाल आया है। इसे वैश्विक यात्रा रुचि के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सबसे बड़े शहर दुबई में बढ़ते पर्यटन, व्यापार एवं रियल एस्टेट अवसरों से बल मिला है।

भारत-अमेरिका समझौते में संवेदनशील क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित : वाणिज्य सचिव

दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर कर रहे काम

- दोनों देश मार्च के अंत तक समझौते के प्रारूप के अंतिम रूप दिए जाने के बाद हस्ताक्षर की उम्मीद

न्यूर्नबर्ग (जर्मनी), एजेंसी

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत ने व्यापार समझौतों में हमेशा उन क्षेत्रों को लेकर स्पष्ट सोच रखी है जो देश के लिए बेहद संवेदनशील हैं और अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते में ऐसे सभी प्रमुख क्षेत्रों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयुक्त बयान को कानूनी समझौते में बदलने पर काम कर रहे हैं जिसे मार्च के अंत तक अंतिम रूप देकर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

अग्रवाल ने कहा कि भारत ने हमेशा सभी समझौतों पर स्पष्ट सोच के साथ बातचीत की है। जो भी क्षेत्र भारत के लिए बेहद संवेदनशील हैं, जहां हमें लगता है कि हमारे किसान, मछुआरे, दुग्ध क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, वहां हमने अपने साझेदार देशों को साफ बता दिया है कि भारत ऐसे मामलों में बाजार नहीं खोल सकता या पहुंच नहीं दे सकता।

उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले एक साल में किए गए सभी समझौतों को देखें। हमने पांच व्यापार समझौते किए हैं। सभी में संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की गई है। अमेरिका के साथ भी सभी प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा गया है। जहां थोड़ी संवेदनशीलता थी, वहां हमने शुल्क दर कोटा व्यवस्था का इस्तेमाल किया ताकि बाजार तक पहुंच सीमित रहे और हमारे किसानों पर असर न पड़े। इस महीने की शुरुआत में घोषित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल (ईंधन), तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे संवेदनशील कृषि एवं दुग्ध उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा है। इन वस्तुओं पर अमेरिका को कोई शुल्क रियायत नहीं दी गई है। ये उत्पाद संवेदनशील हैं क्योंकि इनका संबंध देश के छोटे एवं सीमांत किसानों की आजीविका से है। अन्य मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भी भारत ने संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है।

देश का निर्यात सकारात्मक रहने की उम्मीद

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के वस्तु एवं सेवा निर्यात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है और जनवरी में भी इसके सकारात्मक रहने का अनुमान है। जनवरी के आंकड़े इस महीने आधिकारिक रूप से जारी किए जाएंगे। अग्रवाल ने कहा, कुल मिलाकर निर्यात अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वस्तु निर्यात में हम मजबूती से टिके हुए हैं। सेवाएं हमेशा की तरह बहुत अच्छा कर रही हैं। आप (जनवरी के आंकड़ों) के सकारात्मक रहने की उम्मीद कर सकते हैं। जनवरी के निर्यात आंकड़ों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने यह बात कही। अग्रवाल यहां बायोफैच 2026 प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे हैं जहां 100 से अधिक भारतीय प्रदर्शक और करीब 20 राज्य अपने जैविक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं।

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए को अंतिम रूप दिया है। कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे पशुपालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनसे 50 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहां कृषि अत्यधिक मशीनीकृत और कॉरपोरेट आधारित है, वहीं भारत में यह आजीविका का सवाल है। भारतीय कृषि क्षेत्र को वर्तमान में घरेलू किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए मध्यम से उच्च शुल्क एवं नियामकीय उपायों के जरिये संरक्षण दिया गया है। भारत को 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

समझौते पर संशोधित दस्तावेज से व्हाइट हाउस ने कुछ दालों का जिक्र हटाया

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने अंतरिम व्यापार समझौते पर जारी संशोधित दस्तावेज में उन अमेरिकी उत्पादों की सूची से दालों का जिक्र हटा दिया है जिन पर भारत के शुल्क समाप्त करने या कम किए जाने की बात कही गई थी। व्हाइट हाउस ने अमेरिका और भारत ने की ऐतिहासिक व्यापार समझौते (अंतरिम समझौता) की घोषणा शीर्षक से एक दस्तावेज (फैक्ट शीट) सोमवार को जारी किया था। भारत और अमेरिका के पारस्परिक एवं लाभकारी व्यापार से संबंधित अंतरिम समझौते के ढांचे की संयुक्त घोषणा के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने इसे जारी किया। इसमें समझौते की प्रमुख शर्तों को उल्लेख किया गया है जैसे कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं एवं अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त करेगा या घटाएगा। इनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं। साथ ही यह कहा गया था कि भारत ने अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने तथा ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य क्षेत्रों में 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। व्हाइट हाउस ने हालांकि मंगलवार को जारी संशोधित दस्तावेज (फैक्ट शीट) में दालों का जिक्र हटा दिया और भारत के लिए प्रयुक्त शब्द प्रतिबद्ध को बदलकर इरादा रखता है (इंटेंड्स) कर दिया गया है। संशोधित दस्तावेज में कहा गया है, भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं व अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क समाप्त या कम करेगा जिनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), रेड सोरघम, ट्री नट्स, ताजे व प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन तथा स्पिरिट और अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अधिक अमेरिकी उत्पाद खरीदने और 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कोयला और अन्य उत्पादों की खरीद का इरादा रखता है।

एसएमई की पूंजी बाजार में पहुंच सीमित

- सेबी प्रमुख पांडये ने कहा- सूचीबद्धता से कंपनियों का संचालन हो सकता बेहतर

मुंबई, एजेंसी

सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ समय में हुए विकास के बावजूद, पूंजी बाजार के नजरिये से लघु एवं मझोले उद्यम (एसएमई) क्षेत्र की पहुंच अभी भी सीमित बनी हुई है। पांडेय ने इंडिया एसएमई वित्तपोषण और निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि सूचीबद्धता से ऐसी छोटी कंपनियों में संचालन व्यवस्था बेहतर हो सकती है।

उन्होंने कहा कि नियामक संस्था को अतीत में इस मोर्चे पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत की क्षमता के मुकाबले एसएमई पूंजी बाजार अभी भी सीमित बना हुआ है। कंपनियां पूंजी बाजारों से अपरिचित होने और मर्चेंट बैंकरों तक सीमित पहुंच के कारण बाजार में आने से हिचकिचाती हैं। कुछ वर्षों में सूचीबद्धता में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पांडेय ने कहा कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से पूंजी जुटाने की लागत भी एक बाधा हो सकती है। ऐसी कंपनियां खुलासा और अनुपालन को बोझिल मानती हैं और दस्तावेज दाखिल करने संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन अक्सर अस्पष्ट होता है।

सेबी प्रमुख ने बाजार से पूंजी जुटाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा कदम संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाता है, जिससे पूंजी की लागत कम हो सकती है क्योंकि बाजार विश्वसनीयता को पुरस्कृत करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले, बाजार से पूंजी प्राप्त करने में एक और बाधा तब उत्पन्न हुई जब कुछ एसएमई ने एसएमई ढांचे के तहत उपलब्ध रियायतों का दुरुपयोग किया। ऐसे मामलों ने एसएमई आईपीओ में निवेशकों के भरोसे को बुरी तरह प्रभावित किया।

1,400 कंपनियां अलग एसएमई एक्सचेंज पर सूचीबद्ध

पांडेय ने कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए जहां कुछ एसएमई ने सकारात्मक माहौल बनाने और निवेशकों को अपने शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करने को अनुचित व्यापार गतिविधियों का सहारा लिया। सेबी और शेयर बाजार दोनों ने इस पर सुधार किया है। 1,400 कंपनियां अलग से बनाये गये एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और उनका कुल बाजार पूंजीकरण 4.1 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से 350 से अधिक कंपनियां मुख्य शेयर बाजार में स्थानांतरित हो चुकी हैं। पिछले वित्त वर्ष में कंपनियों ने 98 आईपीओ के माध्यम से 9,800 करोड़ रुपये जुटाए। 2025-26 में जनवरी तक 232 सूचीबद्धता के साथ बढ़कर 10,500 करोड़ रुपये हो गया है।

ईसी बिना खदान संचालन पर एनएलसी को कैग ने फटकारा

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने वैध पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अपनी एक खदान का संचालन करने के लिए एनएलसी इंडिया को फटकार लगाई है। कैग ने कहा कि पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के पुनः सत्यापन को कंपनी के समय पर आवेदन नहीं करने से एनएलसी इंडिया ने माइन-II का संचालन वैध ईसी के बिना किया।

ऑडिट में सामने आया कि अगस्त, 2017 में उच्चतम न्यायालय के आदेश और अप्रैल, 2018 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के बाद ईसी पुनः सत्यापन के लिए आवेदन में देरी से खदान में अनधिकृत संचालन हुआ। एनएलसी इंडिया के परिचालन प्रदर्शन पर 2017-18 से 2022-23 की अवधि को शामिल करने वाली ऑडिट रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में रखी गई।

देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.4% बढ़कर 19.44 लाख करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी

चालू वित्त वर्ष में 10 फरवरी तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.4% बढ़कर 19.44 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह बढ़ोतरी कॉरपोरेट कर की बेहतर वसूली और कर रिफंड की धीमी गति का परिणाम है।

आयकर विभाग से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 14.51% बढ़कर 8.90 लाख करोड़ पहुंच गया। वहीं गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह, जिसमें व्यक्तिगत आयकर और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से मिले कर शामिल हैं, 5.91% बढ़कर 10.03 लाख करोड़ रुपये रहा। शेयरों एवं अन्य प्रतिभूतियों के लेनदेन पर लगाया जाने वाला प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) का संग्रह 1 अप्रैल, 2025 से 10 फरवरी, 2026 के दौरान 50,279 करोड़ रहा। कर रिफंड जारी करने में 18.82% की गिरावट आई और यह घटकर 3.34 लाख करोड़ रहा। रिफंड में कमी से कर संग्रह वृद्धि दर को सहारा मिला।

देश का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.09% बढ़कर 22.78 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें 10.88 लाख करोड़ का सकल कॉरपोरेट कर और 11.39 लाख करोड़ रुपये का सकल गैर-कॉरपोरेट कर शामिल हैं। सरकार ने संशोधित अनुमान (आरई) में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है।

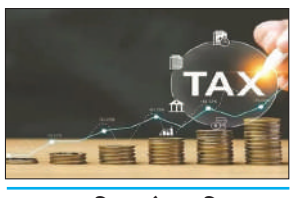

- आयकर विभाग के मुताबिक, शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह 14.51% बढ़कर 8.90 लाख करोड़ पहुंचा

राष्ट्रीय

बजट पर चर्चा : लोस में भाजपा-कांग्रेस में ठनी

जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है वे कभी भी टिक नहीं पाते : अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेने के तुरंत बाद राहुल गांधी के सदन से चले जाने को लेकर उनपर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं।

ठाकुर ने 2026-27 के बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, पहले यह होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल सदन से चले जाते थे, लेकिन अब तो यह स्थिति है कि वह पहले ही भाग जाते हैं।' क्योंकि जिन्हें असत्य बोलने की आदत होती है वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं। ना उनके आरोप कभी टिक पाए, न ये नेता कभी टिक पाए हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो भारत के लिए गर्व की और मुस्कुराने की बात है।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि राहुल गांधी पिछली बार कब मुस्कुराये थे। वह 31 जुलाई 2025 को चार बजकर 20 मिनट पर मुस्कुराये थे। जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया था। किसी ने भारत को तल्खी में डेड इकोनॉमी (मृत अर्थव्यव्यवस्था) कहा था। उन्होंने कहा कि भारत डेड इकोनॉमी नहीं, बल्कि डोमिनेटिंग (दबदबा रखने वाली) इकोनॉमी है।

उन्होंने वोट चोरी के आरोपों पर राहुल पर पलटवार करते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि इनकी प्रोग्रामिंग अंकल सैम (अमेरिका सरकार) और अंकल सोरोस (जॉर्ज सोरोस) ने की है। इनमें अंकल सैम का सिम कार्ड और अंकल सोरोस का सिम कार्ड है। उधर से टाइप होता है और इधर से टेलीकास्ट होता है। ठाकुर ने भारत में डेटा सेंटर के लिए बजट प्रस्ताव में 20 साल के लिए कर अवकाश का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे भारत में निवेश आएगा, लेकिन राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं।

सरकार ने अमेरिका के सामने समर्पण किया, भारत माता को बेच दिया : राहुल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बुधवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पूरी तरह समर्पण कर दिया है और उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है।

उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का समझौता करने को विवश हुए क्योंकि अमेरिका ने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। कांग्रेस नेता ने टोका-टाकी के बीच यह भी कहा कि भारत-अमेरिका समझौते में देश के किसानों के हितों को कुचला गया, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने मोदी और सरकार पर निशाना साधते हुए अमेरिका में एक भारतीय उद्योगपति के खिलाफ दर्ज मामले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रकरण का उल्लेख किया, जिस पर पीठासीन सभापति ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें उन आरोपों को सत्यापित करना चाहिए, जिस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में क्या हुआ। अगर हम इंडिया गठबंधन (की सरकार में) अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे होते, तो हम साफ़ करते कि इस पूरे समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी भारतीय डेटा है। अगर डॉलर को सुरक्षित रखना है, तो उसे यह मानना होगा कि भारतीय डेटा रणनीतिक पूंजी है और किसी भी चर्चा को बराबरी पर होना चाहिए, मालिक और नौकर की तरह नहीं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता और अमेरिका अपने किसानों की रक्षा करेगा, वहीं हम अपने किसानों की रक्षा करेंगे।

केंद्रीय करों के हिस्सेदारी में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया : सीतारमण

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को केंद्र से उनकी कर हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं होने संबंधी कुछ विपक्षी सांसदों के आरोपों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया है।

सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने बजट में पांच मेडिकल क्लस्टर, पांच मेगा औद्योगिक पार्क, बुजुर्गों के देखभाल के लिए पेशेवरों को तैयार करने जैसी कई घोषणाएं की हैं जिनसे लाखों रोजगारों का सृजन होगा। हम पर आरोप है कि हम राज्यों की 41% कर हिस्सेदारी का हस्तांतरण नहीं करते। मैं आश्वासन देती हूं कि हमने केंद्रीय करों में राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी में से किसी राज्य का हिस्सा नहीं घटाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने 2018-19 से 2022-23 तक राज्यों की कर हिस्सेदारी का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि केंद्र से राज्यों को मिलने वाला यह धन आयोग की सिफारिश से मेल खाता है और इसमें कोई कमी नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कुल कर हस्तांतरण 25.44 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 2.07 लाख करोड़ अधिक होगा। संविधान ने केंद्र को उपकर और अधिशेष लगाने का अधिकार दिया है और विभाज्य पूल में वह शामिल नहीं होता है, इसलिए राज्यों की कुल कर हिस्सेदारी की बात करते समय उपकर और अधिशेष संबंधी आरोप अनुचित हैं।

बंगाल में बम चलता है कानून नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं। सदन में विपक्षी सदस्यों के शोर-गुल के बीच, उन्होंने राज्य में महिलाओं के साथ हुई हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि तृणमूल सरकार कानून-व्यवस्था को बेहतर करने के बजाय दोष महिलाओं पर मढ़ रही है। वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए भी बोल रही हैं कि अगर महिला, विशेष रूप से लड़की हो तो रात्रि के समय बाहर नहीं जाओ। आप कानून-व्यवस्था को बेहतर नहीं कर रहे हैं, मगर महिला के उपर दोष डालते जा रहे हैं। उन्होंने दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना का भी जिक्र किया।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक

विचार को 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का किया गया गठन

नई दिल्ली, एजेंसी

- समिति में दोनों सदनों के सदस्य, प्रावधानों की समीक्षा के बाद रिपोर्ट करेगी प्रस्तुत

उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाने का प्रस्ताव करने वाले विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक (वीबीएसए) पर गौर करने के लिए संसद में 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व बीजेपी सांसद डी. पुरंदेश्वरी करेंगी।

लोकसभा सचिवालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस समिति में दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं और यह प्रस्तावित कानून के प्रावधानों की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संसद में वीबीएसए विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया गया था। यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव करने का उद्देश्य रखता है। प्रस्तावित कानून का लक्ष्य विभिन्न मौजूदा नियामकों को एक ही व्यापक संस्था से बदलना और मान्यता, वित्त पोषण और मानक निर्धारण की जिम्मेदारियों को अलग करना है। सरकार ने कहा था कि विपक्षी दलों द्वारा संघवाद, संस्थागत स्वायत्तता और शक्तियों के केंद्रीकरण से जुड़ी चिंता जताने के मद्देनजर परामर्श के लिए वह संयुक्त समिति को भेजना चाहती है।

एअर इंडिया विमान दुर्घटना जांच रिपोर्ट दाखिल करे केंद्र

- केंद्र ने कहा- एएआईबी जांच अंतिम चरण में, कुछ जांच विदेश में किए जाने की जरूरत

नई दिल्ली, एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने 12 जून, 2025 को एअर इंडिया विमान दुर्घटना के मामले में बुधवार को केंद्र से अब तक अपनाए गए प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब उसे सूचित किया गया कि हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच बोर्ड (एएआईबी) द्वारा अंतिम चरण में है।

लंदन जा रही एअर इंडिया की बोइंग 787-8 उड़ान एआई171 गुजरात के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 241 यात्री और चालक दल समेत 260 लोग मारे गए। दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई थी। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एएआईबी जांच अंतिम चरण में है और कुछ जांच विदेश में किए जाने की जरूरत है। मेहता केंद्र और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की तरफ से अदालत में पेश हुए। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि मामले पर तीन संबंधित याचिकाओं को व्यापक सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। पीठ का शुरू में विचार था कि एएआईबी जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए।

एसआईटी के समक्ष पेश हों पूर्व टीडीबी सचिव

शबरिमला सोना चोरी का मामला

उच्चतम न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) की पूर्व सचिव को शबरिमला सोना चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया और उनकी अग्रिम जमानत अवधि भी बढ़ा दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा की पीठ ने पूर्व टीडीबी सचिव एस जयश्री को गिरफ्तारी से दी गई राहत को बढ़ाते हुए उनसे मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा। न्यायालय ने कहा, प्रतिवादी केरल राज्य के जवाबी हलफनामे के अनुच्छेद 16 में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह आगे की पूछताछ के लिए 18 फरवरी, 2026 को दोपहर 12 बजे एक बार फिर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो। पूर्व में दी गई अंतरिम सुरक्षा अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी। इसने मामले को 20 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने 18 दिसंबर, 2025 को जयश्री की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करते हुए, उन्हें 8-9 जनवरी को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्ति की परतों से सोने की चोरी से संबंधित मामले में चौथी आरोपी जयश्री, 2019 में टीडीबी की सचिव थीं।

अजित पवार के बेटों ने भी जताया विमान हादसे में साजिश का शक

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत का मामला और गहराता जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने बुधवार को इस हादसे से जुड़ा एक नया वीडियो जारी किया और दावा किया कि अजित पवार के बेटे पार्थ और जय पवार को इस घटना पर गंभीर संदेह हैं। उन्होंने कहा, परिवार और पार्टी के भीतर इस हादसे को लेकर भारी अविश्वास का माहौल है। रोहित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में पार्थ पवार से मुलाकात की है, उनके मन में भी कई प्रश्न हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक सामान्य दुर्घटना होती तो अजित पवार गुट के नेता जैसे अमोल मिटकरी और रूपाली ठोंबरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने नहीं जाते। रोहित ने कहा कि इन नेताओं ने पार्थ और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की सलाह के बाद ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि यह हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी तह तक जाना जरूरी है।

ट्रेड यूनियनों की हड़ताल आज

नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साझा मंच की ओर से बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल की वजह से बृहस्पतिवार को पूरे देश में बिजली, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य के साथ गैस और पानी आपूर्ति से जुड़ी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इस आम हड़ताल में अलग-अलग क्षेत्र के 30 करोड़ कामगारों के शामिल होने की उम्मीद है।

वर्ल्ड ब्रीफ

फिलीपींस में जहाज डूबने से मरने वालों की संख्या 52 हुई

फिलीपींस। फिलीपींस के बेसिलन प्रांत के पास यात्री-मालवाहक जहाज 'त्रिशा कर्स्टिन 3' के डूबने से 52 लोगों की मौत हो गई है। फिलीपीन कोस्ट गार्ड (पीसीजी) ने तकनीकी गोताखोर टीमों के चल रहे प्रयासों का हवाला देते हुए बताया कि गोताखोरों ने मंगलवार तड़के बालुक-बालुक द्वीप के पास खोज और बचाव अभियान के दौरान एक और शव बरामद किया। कुल मिलाकर 316 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बचाव दल अभी भी शेष पीड़ितों की तलाश में जुटे हैं। यह जहाज 26 जनवरी की रात बेसिलन से लगभग एक समुद्री मील की दूरी पर डूब गया था, जिसमें 332 यात्री और चालक दल के 27 सदस्य सवार थे। अधिकारियों ने कहा कि डूबने का संभावित कारण तकनीकी खामी थी।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने में सिंगापुर में भारतीय को सजा

सिंगापुर। सिंगापुर की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय मूल के एक व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और एक सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के आरोप में 14 सप्ताह की जेल की सजा सुनाई। चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) की रिपोर्ट के अनुसार 36 वर्षीय विकनेस्वरन वी मोगनावल ने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के अधिनियम के तहत एक आरोप और एक लोक सेवक के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करने के दूसरे आरोप में दोषी होने की बात स्वीकार कर ली है। वह इसलिए नाराज था क्योंकि उसके पड़ोसी के बच्चे अक्सर उसके अपार्टमेंट के पास वाले साझा गलियारे में खेलते थे। उसकी पड़ोसी अपने पति, तीन बच्चों, सास, बहन और एक नौकरानी के साथ वहीं रहती थी।

तनाव कम करने के लिए यूनान और तुर्किए के नेता करेंगे वार्ता

अंकारा। यूनान के प्रधानमंत्री क्यारियाकोस मित्सोताकिस बुधवार को तुर्किए की यात्रा के लिए रवाना हुए, जहां दोनों देशों के बीच वार्ता होने की उम्मीद है। यह यात्रा ऐसे समय में संवाद बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है जब दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। वरिष्ठ मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आने वाले मित्सोताकिस तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात करेंगे। यह वार्ता उच्च स्तरीय सहयोग परिषद के तहत एक पहल है जिसे नाटो के दोनों सहयोगियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। यूनान और तुर्किये के बीच समुद्री सीमाओं, साइप्रस और पूर्वी भूमध्य सागर में 'ड्रिलिंग' अधिकारों सहित कई मुद्दों पर मतभेद बना हुआ है।

श्रीलंकाई सांसद की हत्या के मामले में 12 को मौत की सजा

कोलंबो, एजेंसी

● बेगमपुर इलाके में हुआ हादसा पुलिस ने दर्ज किया मामला

श्रीलंका की गम्पाहा हाईकोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2022 में तत्कालीन सांसद अमरकीर्ति अथुकोराला और उनके सुरक्षा अधिकारी की हत्या के मामले में 12 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। यह फैसला एक लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिसमें इन हत्याओं के संबंध में कुल 42 लोगों को आरोपित किया गया था।

मौत की सजा के अलावा, अदालत ने चार अन्य व्यक्तियों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। अन्य 23 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, मई 2022 में देशव्यापी अशांति के दौरान सांसद और उनके सुरक्षा अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों की एक आक्रोशित भीड़ पर उस समय गोलियां चला दी थीं, जब वे उनके वाहन को रोक रहे थे। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी दिन बाद में सांसद और उनके सुरक्षाकर्मी पास की एक इमारत के अंदर मृत पाए गए थे।

साइबर ठगों को सिस्टम का साथ

डिजिटल 'डकैती'

डिजिटल अरेस्ट के जरिए 54,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की ठगी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डकैती करार दिया है। यह निराशाजनक ही है कि साइबर ठगी यह तरीका कई वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन देश का गृह विभाग इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। रिकॉर्ड के अनुसार देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं का इतिहास करीब पांच साल पुराना हो चुका है। साल दर साल इन घटनाओं में बेहद तेज वृद्धि हुई है। इस बीच सबसे ज्यादा चिंताजनक यह है कि ठगी के कुछ मामलों में बैंक और टेलीकॉम अफसरों की साठगांठ भी सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस की कामयाबी की दर भी बेहद मामूली है। इसके साथ यह भी सवाल उठने लगे हैं कि देश में डिजिटल क्रांति पर जोर देने के साथ लोगों को ठगी से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं।

डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत

- लोगों को वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी के मामले 2021 में आने शुरू हुए और बाद में तेजी से इनकी संख्या बढ़ी।
- डिजिटल अरेस्ट में मनोवैज्ञानिक दबाव और वीडियो विजुअल्स की मदद ली गई जो जामतारा जैसे ठगी के केंद्रों से विकसित हुआ।
- भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 40,000 केस दर्ज किए गए थे जो 2024 तक बढ़कर 1.23 लाख से अधिक हो गए।
- नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार 2024 में तीन गुना वृद्धि हुई, शुरू के 4 महीनों में ही 120.30 करोड़ की ठगी हुई।

अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और तकनीक

- जांच में पाया गया कि ठग गिरोहों के तार दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से जुड़े हैं।
- हाल के वर्षों में अपराधियों ने एआई का उपयोग करके पुलिस अधिकारियों की आवाज और चेहरे की नकल करनी शुरू की है।

बैंक अधिकारियों की साठगांठ

- दिल्ली में येस बैंक के दो अफसर गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने फर्जी खाते खोले ताकि पैसे को लाउंडर किया जा सके।
- कमीशन लेकर फर्जी खाते खोलने पर हैदराबाद और बेंगलुरु में एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक शाखा प्रबंधक पकड़े गए।
- तेलंगाना में ऑपरेशन इनसाइडर के तहत कई बैंक अफसर पकड़े गए जो खाते खोलकर अपराधियों की मदद कर रहे थे।
- वोडाफोन के एरिया सेल्स मैनेजर ने साइबर ठगों को 21,000 सिम मुहैया कराए, जिसे दिल्ली में सीबीआई ने गिरफ्तार किया।

हैरतअंगेज मामले

- चेन्नई में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व केंद्रीय सचिव पद्म भूषण सम्मानित टी. रामासामी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने 57 लाख की ठगी की।
- अगस्त 2024 में ठगों ने पद्म भूषण से सम्मानित वर्धमान ग्रुप के एसपी ओसवाल को सीबीआई अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट किया और 7 करोड़ ठग लिए।
- चंडीगढ़ में रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी से 3.4 करोड़ रुपये की ठगी हुई।

डिजिटल क्रांति में सुरक्षा की कमी

- भारत का पहला व्यापक डिजिटल कानून डिजिटल क्रांति के कई वर्षों बाद आया। इसके नियम अभी भी पूरी तरह लागू होने की प्रक्रिया में हैं। इस देरी ने ठगों को बड़ा अवसर मुहैया कराया।
- टेलीकॉम और बैंकिंग कर्मचारी ही सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार कर रहे हैं, जो सिस्टम की बड़ी कमजोरी है। रिजर्व बैंक ने भी स्वीकार किया है कि म्यूल खाते खोलने के पीछे साठगांठ है।
- ठग अत्याधुनिक एआई और डीपफेक उपयोग कर रहे हैं जबकि देश के कई राज्यों में साइबर पुलिस के पास पुराना बुनियादी ढांचा है और वह विशेषज्ञों की भारी कमी से जूझ रही है।

आपसी मतभेदों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखे भारत

दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बाद चीन ने दिया जोर

बीजिंग, एजेंसी

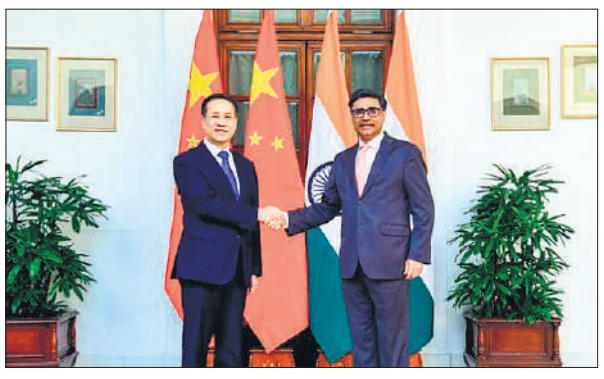

भारत ने संवेदनशील मुद्दों पर चिंता जताई

इस वार्ता पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति की समीक्षा की और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाकर तथा संवेदनशील मुद्दों पर चिंताओं को दूर करके संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। जायसवाल ने संवेदनशील मुद्दों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन समझा जाता है कि भारतीय पक्ष दुर्लभ पृथ्वी खनिजों से संबंधित चीन के निर्यात नियंत्रण उपायों को लेकर चिंतित है। मिसरी और झाओक्सू की वार्ता पर भारतीय पक्ष की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चर्चा मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने और पुनर्निर्माण में हालिया प्रगति तथा आगे संपर्क बढ़ाने के उपायों पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों की समग्र प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

चीन के विदेश मंत्रालय ने नR दिल्ली में भारत के साथ मंगलवार को हुई रणनीतिक वार्ता पर मंगलवार को कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, साथ ही मतभेदों को उचित तरीके से सुलझाना चाहिए और सहयोग बढ़ाना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिसरी और उनके चीनी समकक्ष मा झाओक्सू ने भारत-चीन रणनीतिक वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई।मा झाओक्सू भारत में 'ब्रिक्स' शेरपा बैठक में भाग लेने आए हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से मिसरी और झाओक्सू के बीच बातचीत पर कहा गया कि दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति, दोनों देशों की आंतरिक एवं बाहरी नीतियों, साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों तथा चीन-भारत संबंधों पर मित्रतापूर्ण, स्पष्ट और गहन संवाद किया। दोनों पक्षों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्थिति में जटिल और गहरे बदलावों को देखते हुए भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बनी महत्वपूर्ण समझ को गंभीरता से लागू करना चाहिए। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच बनी समझ के अनुसार, दोनों देशों को यह रणनीतिक धारणा बनाए रखनी चाहिए कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार हैं और दोनों एक-दूसरे के लिए विकास का अवसर हैं, खतरा नहीं।

चीन ने कहा कि दोनों देशों को आपसी विश्वास को मजबूत करना चाहिए, सहयोग बढ़ाना चाहिए, मतभेदों को सही तरीके से सुलझाना चाहिए और संबंधों को स्थिर एवं सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों पक्षों ने 2026 और 2027 में ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान एक-दूसरे के कार्यों का समर्थन करने पर सहमति जताई। इसके अलावा दोनों पक्षों ने बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका, 'ग्लोबल साउथ' में एकता एवं सहयोग को मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय न्याय एवं निष्पक्षता की रक्षा करने, बहुध्रुवीय विश्व के लिए मिलकर काम करने तथा एशिया और विश्व में शांति एवं विकास में योगदान देने पर सहमति जताई।

बीजिंग में भारत और अमेरिका के राजदूतों की मुलाकात

बीजिंग। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप रावत और उनके अमेरिकी समकक्ष डेविड पर्ड्यू ने बीजिंग में मुलाकात की और अमेरिका-भारत संबंधों एवं साझा हितों पर चर्चा की। पर्ड्यू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों पर घनिष्ठ सहयोग और क्वाड की भागीदारी के माध्यम से अमेरिका-भारत संबंध वास्तविक परिणाम देते हैं। उन्होंने कहा, अपने मित्र राजदूत रावत से मिलकर हमारी साझा रुचियों पर चर्चा करना हमेशा ही बहुत अच्छा अनुभव रहता है। दिसंबर के बाद से यह उनकी दूसरी बैठक है। रावत, पर्ड्यू और चीन में जापानी राजदूत केंजी कानासुगी ने पिछले साल दिसंबर में अमेरिकी दूतावास में मुलाकात की थी।

बांग्लादेश में आम चुनाव आज, 50% से ज्यादा मतदान केंद्र संवेदनशील

● सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, बॉडी कैमरे से लैस पुलिसकर्मी तैनात

ढाका, एजेंसी

बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को होने जा रहे आम चुनाव के लिए आधे से अधिक मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 90 प्रतिशत मतदान केंद्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। राजधानी ढाका में बॉडी कैमरों से लैस पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग की सुरक्षा प्रणाली जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है। निर्वाचन आयुक्त अबुल फजल मोहम्मद सनाउल्लाह ने मंगलवार देर रात संवाददाता सम्मेलन में कहा, स्थानीय स्तर पर संवेदनशीलता के आकलन के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि इन चुनाव में देश के चुनावी इतिहास में कानून प्रवर्तन कर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती और प्रौद्योगिकी का सबसे व्यापक उपयोग देखने को मिलेगा। सनाउल्लाह ने कहा कि निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि कानून प्रवर्तन एजेंसी मतदान के दौरान और चुनाव के बाद मतदाताओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करेंगी।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से काफी हद तक संतुष्ट है और पहले की तुलना में हम अब बेहतर स्थिति में हैं। उनकी यह टिप्पणी पुलिस महानिरीक्षक बहारुल आलम के उस बयान के कुछ देर बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश भर में लगभग 43,000 मतदान केंद्रों में से 24,000 मतदान केंद्र उच्च या मध्यम जोखिम वाले मतदान केंद्र पाए गए हैं।

आम चुनाव की पूर्व संध्या पर ढाका में मतपेटियां तैयार करता एक कर्मचारी।

मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के बीच

बांग्लादेश में एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ आम चुनाव हो रहे हैं। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को संसदीय चुनाव होंगे।

भारत-पाकिस्तान के बीच मार गिराए गए थे 10 विमान : ट्रंप

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यह दावा दोहराया कि उन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को टैरिफ की धमकी देकर रोक दिया था जो परमाणु युद्ध में बदल सकता था। उन्होंने कहा, इस संघर्ष में उनके हस्तक्षेप करने तक 10 विमान मार गिराए गए थे।

ट्रंप ने मंगलवार को एक साक्षात्कार में कहा, मैंने आठ युद्ध रुकवाए। इनमें से छह टैरिफ के कारण सुलझे। जैसे भारत और पाकिस्तान। मैंने कहा कि अगर आप यह युद्ध नहीं रोकते हैं तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने पूछा कि युद्ध का टैरिफ से क्या लेना-देना। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था, ट्रंप ने हमें लड़ाई रोकने के लिए राजी करके कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई।

पेजेश्कियान ने प्रदर्शनों पर खूनी कार्रवाई के पीड़ितों से माफी मांगी

दुबई, एजेंसी

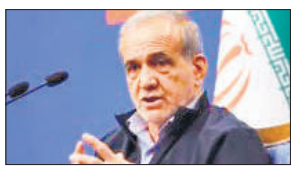

● देशव्यापी प्रदर्शनों पर पश्चिमी देशों के दुष्प्रचार की निंदा की

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देशव्यापी प्रदर्शनों और उसके बाद हुई खूनी कार्रवाई से पीड़ित सभी लोगों से बुधवार को माफी मांगी। हालांकि, राष्ट्रपति ने प्रदर्शनों को लेकर फैलाए कथित पश्चिमी दुष्प्रचार की भी निंदा की।

पेजेश्कियान ने कहा कि वह प्रदर्शनों और उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुए लोगों के गहरे दुख को समझते हैं लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि इस रक्तपात में ईरानी सुरक्षा बलों की भूमिका थी। उन्होंने कहा, हम जनता के सामने शर्मिंदा हैं और इन घटनाओं में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम जनता से टकराव नहीं चाहते। पेजेश्कियान ने यह भी जोर देकर कहा कि उनका देश परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा और वह किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं।

उनकी यह टिप्पणी ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में आई। ईरान इस समय अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ बातचीत के दौर में है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कोई परमाणु समझौता हो पाएगा या नहीं। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक और विमानवाहक पोत भेजने की धमकी दी है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कई महीनों से ईरान के परमाणु भंडार का निरीक्षण और सत्यापन करने में असमर्थ रही है।

ट्रंप के अलावा किसी ने नहीं कहा रूस से तेल खरीदना बंद करेगा भारत

मास्को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने भी यह नहीं कहा है कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को देश की संसद में यह बात कही। रूस ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को उससे तेल खरीदने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जिसके दो दिन बाद लावरोव की यह टिप्पणी आई है।

रूस का कहना है कि वाशिंगटन टैरिफ, प्रतिबंध और सीधे रोक सहित कई तरह के दबावपूर्ण कदम उठा रहा है। लावरोव ने बुधवार को स्टेट ड्यूमा (निचले सदन) में एक सांसद के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आपने उल्लेख किया कि ट्रंप ने भारत की रूस से तेल न खरीदने की

● लावरोव ने कहा- रूस भारत के साथ संबंधों को लेकर हरसंभव प्रयास करने को तैयार

सहमति की घोषणा की है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी अन्य भारतीय नेता से ऐसा कोई बयान नहीं सुना है। लावरोव ने उल्लेख किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में शेरपाओं की पहली बैठक में कहा था कि ऊर्जा सुरक्षा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों में से एक होगी, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल होने की उम्मीद है। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा।

लावरोव ने कहा कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा ने मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंधों को समृद्ध किया है।

एससीडीआरसी में लंबित उपभोक्ता मामलों की सुनवाई करें हाईकोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महत्वपूर्ण आदेश में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कुछ उच्च न्यायालयों से कहा कि वे राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (एससीडीआरसी) में लंबित उपभोक्ता शिकायतों और अपीलों की सुनवाई करें। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह अपने समक्ष लंबित मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सके।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता विवादों के त्वरित निपटारे के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जिला आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) शामिल है। राज्य आयोग एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के दावों वाले मामलों की सुनवाई करता है और जिला आयोगों के आदेशों के खिलाफ अपीलें भी सुनता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने उन राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई की, जहां उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों की संख्या बेहद कम है। कुछ राज्यों ने बताया कि उनके उपभोक्ता आयोग एक साल से अधिक समय से निष्क्रिय हैं।

आज का भविष्यफल

-पं. मनोज कुमार द्विवेदी

आज की ग्रह स्थिति : 12 फरवरी, गुरुवार 2026 संवत-2082, शक संवत 1947 मास-फाल्गुन, पक्ष-कृष्ण पक्ष, दशमी 12.22 तक तत्पश्चात एकादशी।

आज का पंचांग

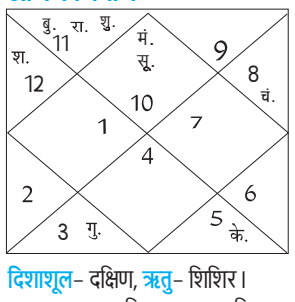

दिशाशूल- दक्षिण, **ऋतु**- शिशिर।
चन्द्रबल- वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ।
ताराबल- अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, रेवती।
नक्षत्र-ज्येष्ठा 13.42 तक तत्पश्चात मूल।

मेष — आज महिलाओं को अपना व्यवहार संयमित रखना चाहिए। मन में अनेक प्रकार के विचार एक साथ आएंगे। गूढ़ विषयों के अध्ययन के लिये प्रेरित हो सकते हैं। लोगों से अधिक सलाह न लें वरना अनावश्यक भ्रमित हो जाएंगे।

वृष — आज आपके रुके हुए कार्य गतिशील होने की संभावना है। नई तकनीक के प्रति जिज्ञासु रहेंगे। परिश्रम का बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। आंखों में परेशानी और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। जीवनसाथी की भावनाओं को समझें।

मिथुन — आज आपकी सलाह से लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति की खरीदी का विचार मन में आएगा। कार्यक्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। सरकारी जॉब कर रहे लोगों को पदोन्नति मिल सकती है।

कर्क — आज दोपहर के बाद का समय आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है। आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। अटके हुए धन का लाभ आपको मिलेगा। आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में आपको सुधार करना पड़ेगा।

सिंह — आज मन में साहसिक कार्य करने की इच्छाशक्ति जागृत होगी। अपनी कमियों को लेकर थोड़े कुंठित हो सकते हैं। अहंकारी व्यवहार के कारण स्वजन आपसे नाराज हो सकते हैं। अधिकारी वर्ग से अपना व्यवहार अच्छा रखें।

कन्या — आज अधीनस्थ कर्मचारी आपसे अत्यधिक प्रसन्न रहने वाले हैं। दूर के स्थानों की यात्रा करने के योग बन रहे हैं। नए कारोबार में आप निवेश कर सकते हैं। मीडिया और प्रकाशन समूह से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

तुला — आज विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपको कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। लोगों के लिए आप प्रेरणा का केन्द्र बनेंगे। घर का वातावरण बहुत ही सुखमय रहेगा। कड़वी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है।

वृश्चिक — आज रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। परिवार में सभी आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। किसी मांगलिक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी।

धनु — आज पहले की गई गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आर्थिक मामलों को लेकर आप थोड़े परेशान रहेंगे। अपना मन सदैव शान्त रखें। घरेलू खर्च को लेकर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। स्वार्थी लोग आपके संपर्क में रहेंगे।

मकर — आज दिन की शुरुआत किसी शुभ खबर से होगी। आपके कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। प्रेमीजन के साथ मतभेद दूर होंगे। गलत बातों में अपना समय बर्बाद न करें। व्यवसाय में आपको अपेक्षा से अधिक धन लाभ होगा। प्रेम संबंधों को पर्याप्त समय देंगे।

कुंभ — आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का मन काम में नहीं लगेगा। कारोबार में आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने के कारण मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। अपने काम के प्रति निष्ठावान रहें। मन में संतुष्टि का भाव रहेगा।

मीन — आज अनर्गल कार्यों में अधिक ध्यान न लगाएं। सहकर्मी आपकी अत्यधिक सहायता करेंगे। व्यवसाय में आकस्मिक धन हानि झेलनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। पिता के किसी निर्णय से आप नाराज हो सकते हैं।

सुडोकू-59

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

		1			4		7	
				3				5
2					9			
6	5			7			8	
			1		8			
	1			6			9	2
			7					8
9				4		3		
	8		3			1		

सुडोकू - 58 का हल

6	1	9	2	5	4	7	3	8
7	2	4	3	8	6	1	9	5
3	5	8	1	9	7	6	2	4
1	6	7	5	3	9	4	8	2
2	4	3	6	7	8	9	5	1
8	9	5	4	2	1	3	6	7
4	3	6	8	1	2	5	7	9
9	8	1	7	6	5	2	4	3
5	7	2	9	4	3	8	1	6

भारतीय टीम 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए उत्साहित हैं। हम खेलने के लिए तैयार हैं। हम सभी टीमों पर नजर रखे हैं। हम गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को देख रहे हैं।
–तिलक वर्मा

स्टेडियम

लखनऊ, गुरुवार, 12 फरवरी 2026

अमृत विचार

www.amritvichar.com

अभिषेक की तबीयत खराब होने से मेजबान टीम चिंतित

नई दिल्ली, एजेंसी

मौजूदा चैंपियन भारत को गुरुवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप मैच में नामीबिया से किसी तरह का खतरा नहीं है लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पेट के संक्रमण के कारण मुख्य कोच गौतम गंभीर सहित टीम प्रबंधन चिंतित होगा क्योंकि इससे उसकी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में वानखेड़े की चिपचिपी पिच पर बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें फिरोज शाह कोटला की पिच पर आक्रामक खेल दिखाना चाहेगा, जिसे बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन पिच कहा जा सकता है। नामीबिया के खिलाफ भारत का पलड़ा बहुत भारी है जिसकी टीम इसी मैदान पर नीदरलैंड्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस तरह से देखा जाए तो भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले महत्वपूर्ण मैच से पहले यह मैच अभ्यास मैच की तरह है।

टीम

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह।

नामीबिया : गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जान बाल्ट, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), मालन क्रूगर, डायलन लीचर, लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लोफ्टी-ईटन, विलियम मायबर्ग, जे जे स्मिट, जैक ब्रासेल, मैक्स हेंगो, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, बेन शिकोंगो, रूबेन ट्रम्पेलमैन।

अभ्यास सत्र के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव। एजेंसी

आज के मैच

टीम	समय
श्रीलंका-ओमान	पूर्वाह्न 11 बजे
इटली-नेपाल	दोपहर 3 बजे
भारत-नामीबिया	शाम 7 बजे

हाईलाइट

बांगड़ ने कहा- बेखौफ होकर खेलना जारी रखे भारत

नई दिल्ली। पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने कहा कि भारत को टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ बल्लेबाजों की नाकामी का ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है और उसे अपना बेखौफ रवैया जारी रखना चाहिए जिसके कारण उसने काफी सफलता हासिल की हैं। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए अपने पहले मैच में भारत 13वें ओवर में 77 रन पर छह विकेट खो बैठा था, लेकिन फिर भी उसने अमेरिका पर 29 रन से जीत हासिल की। बांगड़ ने जिओ हॉटस्टार के एक कार्यक्रम में कहा मुझे नहीं लगता कि भारतीय बल्लेबाजों को वानखेड़े में अमेरिका के खिलाफ जो हुआ उसका बहुत अधिक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि टी20 क्रिकेट में आजकल जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर जोखिम भरा हुआ है।

अनीश ने रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य जीता

नई दिल्ली। विश्व चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता अनीश भानवाला ने एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में पुरूषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता जबकि आठवें दिन कजाखस्तान का दबदबा रहा। अनीश का एशियाई चैम्पियनशिप में यह तीसरा पदक है। एड्रियन कर्माकर ने 50 मीटर राइफल प्रोन जूनियर पुरूष वर्ग में और जूनियर पुरूष 25 मीटर आरएफपी में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के अब 41 स्वर्ण, 19 रजत और 15 कांस्य पदक हो गए हैं जबकि स्पर्धा के दो दिन बाकी हैं। अनीश और आदर्श सिंह क्वालीफाइंग दौर में सातवें और आठवें स्थान पर रहे थे। कजाखस्तान के पूर्व चैम्पियन निकिता चिरयुकिन क्वालीफायर में शीर्ष रहे। फाइनल में आदर्श चौथी सीरिज के बाद बाहर हो गए जबकि अनीश, निकिता व जापान के योशिओका संयुक्त बढ़त पर थे।

दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका की अफगानिस्तान पर रोमांचक जीत

टी-20 विश्व कप : पहले 187 और 17 रनों पर टाई हो गया था मुकाबला

अहमदाबाद, एजेंसी

सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के साहसिक खेल के बावजूद अफगानिस्तान को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को यहां रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचे मैच में दूसरे सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा जिससे उसकी सुपर आठ में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद छह विकेट पर 187 रन बनाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 19.4 ओवर में 187 रन पर आउट हो गई। फिर पहला सुपर ओवर भी टाई रहा। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लुंगी एनगिडी ने सुपर ओवर किया जिसमें अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। इसमें अजमतुल्लाह उमरजई का एक छक्का और दो चौके शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका ने फजलहक फारुकी के ओवर में एक विकेट पर 17 रन बनाए। ट्रिस्टन स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर बराबर किया। उमरजई दूसरा सुपर ओवर करने के लिए आए जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने डेविड मिलर के दो छक्कों की मदद से 23 रन बनाए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने पहली दो गेंद पर कोई रन नहीं दिया और मोहम्मद नबी को आउट किया। गुरबाज ने इसके बाद लगातार तीन छक्के लगाए लेकिन आखिरी गेंद पर वह आउट हो गए।

इस जीत से दक्षिण अफ्रीका के दो मैच में चार अंक हो गए हैं जबकि अफगानिस्तान की यह लगातार दूसरी हार है। उसे अगले चरण में जाने के लिए न सिर्फ अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे बल्कि अन्य मैच के परिणाम भी अनुकूल रहने के लिए दुआ करनी होगी। अफगानिस्तान इससे पहला लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में था लेकिन लगातार विकेट गंवाने के कारण उसे नुकसान हुआ। उसकी तरफ से गुरबाज ने 42 गेंद पर 84 रन बनाए जिसमें चार चौके और सात छक्के शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनगिडी ने 26 रन देकर तीन विकेट लिए। इससे पहले रयान रिकेल्टन ने 28 गेंद पर 61 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें पांच चौके और चार छक्के शामिल हैं। क्विंटन डीकॉक ने 41 गेंद पर पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। कप्तान एडन मार्करम (05) के जल्दी आउट होने के बाद 114 रन की साझेदारी की।

सुपर ओवर में अफगानिस्तान पर जीत दर्ज करने के बाद जश्न मनाते दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी। एजेंसी

संक्षिप्त स्कोर

दक्षिण अफ्रीका 187/6 (20 ओवर)
- मार्क रयान रिकलेटन 61
- क्विंटन डी कॉक 59

गेंदबाजी : अजमतुल्लाह उमरजई 3-41, राशिद खान 2-28

अफगानिस्तान 187/10 (19.4 ओवर)
- रहमानुल्लाह गुरबाज़ 84
- अज़मतुल्लाह उमरज़ई 22

गेंदबाजी : लुंगी एनगिडी 3-26, केशव महाराज 1-27

पहला सुपर ओवर : टाई

अफगानिस्तान - 6 बॉल में 17/0

दक्षिण अफ्रीका - 6 बॉल में 17/1

दूसरा सुपर ओवर: द. अफ्रीका 4 रन से जीता

दक्षिण अफ्रीका - 6 बॉल में 23/0

अफगानिस्तान - 6 बॉल में 19/2

खिलाड़ियों से कहा था कि आखिर तक लड़ना होगा

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टीम के साथी खिलाड़ियों से कहा था कि उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ 'चुनौती' के लिए तैयार रहना होगा और बुधवार को यहां खेला गया यह मैच टी20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक साबित हुआ। इसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। जीत और अंक मिलने के लिए शुक्रगुजार हूं। मार्करम ने कहा आखिरकार सुपर ओवर में आप अपने बेहतर, सबसे आत्मविश्वास से भरे खिलाड़ी को चुनते हैं। पहले ओवर में लुंगी से ज्यादा गलती नहीं हुई, लेकिन फिर उन्होंने अच्छा स्कोर बना लिया। केशव के साथ भी यही कहानी रही। स्पिनर के लिए यह मुश्किल होता है, फिर भी हमने उन पर भरोसा किया। उन्होंने कहा मैंने लड़कों से कहा था कि लक्ष्य ठीक है, लेकिन हमें चुनौती का सामना करना होगा।

वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 30 रनों से परास्त किया

- शेरफेन रदरफोर्ड की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद गुडाकेश मोती ने की घातक गेंदबाजी

मुंबई, एजेंसी

शेरफेन रदरफोर्ड के नाबाद 76 रन और गुडाकेश मोती के तीन विकेट की मदद से वेस्टइंडीज ने बुधवार को टी20 विश्व कप के ग्रुप सी के अहम मुकाबले में इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया।

रदरफोर्ड ने चिर परिचित कैरेबियाई अंदाज में खेलते हुए 42 गेंद में पांच छक्कों और दो चौकों की मदद से नाबाद 76 रन बनाकर वानखेड़े स्टेडियम पर मौजूद करीब 21000 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं मोती ने गेंदबाजी में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जीत के लिए 197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 19 ओवर में 166 रन पर आउट हो गई। सैम कुरेन ने सर्वाधिक 43 रन की नाबाद पारी खेली। फिल साल्ट ने 14 गेंद में 30 रन बनाये जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे। उन्होंने जैसन होल्डर के दूसरे ओवर में 24 रन निकाले। साल्ट को रोमारियो शेफर्ड ने कवर में रदरफोर्ड के हाथों लपकवाया। पावरप्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट पर 67 रन था। जोस बटलर (21) भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। वह रोस्टन चेस की गेंद पर लांग आन में पॉवेल को कैच देकर लौटे। इसके बाद मोती ने इंग्लैंड को दोहरे झटके दिए। पहले उन्होंने टॉम बेंटोन (दो) को कवर में कैच आउट कराया और इसके बाद जैकब बेथेल (33) को चाइनामैन गेंद पर आउट किया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक (17) मोती को रिटर्न कैच देकर लौटे। इससे पहले रदरफोर्ड के नाबाद 76 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने खराब शुरूआत से उबरते हुए छह विकेट पर 196 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने दस ओवर के बाद 79 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे। पर आखिरी दस ओवर में 117 रन बने। रदरफोर्ड ने पांचवें विकेट के लिये रोवमैन पॉवेल (14) के साथ 51 रन की साझेदारी की। इसके बाद पूर्व कप्तान जैसन होल्डर (17 गेंद में चार छक्कों, एक चौके की मदद से 33 रन) के साथ छठे विकेट के लिये 32 रन जोड़े। टेस्ट कप्तान रोस्टन चेस ने चौथे नंबर पर उतरकर 34 रन बनाए। होल्डर ने आखिरी ओवरों में सैम कुरेन को एक ही ओवर में तीन छक्के लगाए। रदरफोर्ड को 18वें ओवर में आदिल रशीद ने जीवनदान दिया था। होल्डर ने आतिशी पारी खेलकर रदरफोर्ड पर से दबाव कम किया। पिछले मैच में नेपाल के बल्लेबाजों से नसीहत पाने वाले रशीद ने मजबूती से वापिस की और 16 रन देकर दो विकेट चटकाए।

टीम के साथ जश्न मनाते वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती। एजेंसी

इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है : अफगानिस्तान के कोच ट्रॉट

अहमदाबाद। अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रॉट ने टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका से दूसरे सुपर ओवर में मिली हार के बाद कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका ने क्षेत्ररक्षण में उनकी टीम को कमजोर साबित किया। टी20 विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में दक्षिण अफ्रीका ने दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को हराया। ट्रॉट ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा इससे साबित होता है कि हमारे पास कितनी शानदार टीम है। हमारे पास कुछ बेहतरीन खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ दिन पहले मिली हार के बाद दक्षिण अफ्रीका से करीबी मुकाबला हारना दिल तोड़ने वाला है। हमें कठिन ग्रुप भी मिला है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ट्रॉट ने कहा कि इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है। उन्होंने कहा टीम को अपने प्रदर्शन पर गर्व होना चाहिये लेकिन कई बार इस तरह की हार लंबे समय तक चुभती है। अब अहम यह है कि हम इसके सकारात्मक पहलुओं को देखें और यह भी प्रयास करें कि जहां गलतियां हुई हैं, उनमें सुधार हो। ट्रॉट ने कहा दक्षिण अफ्रीका की फील्डिंग बहुत अच्छी थी। रन आउट, सीमा पर कैच और रन बचाने के प्रयास। जबर्दस्त फील्डिंग और शायद यही फर्क था। ट्रॉट के कोच रहते अफगानिस्तान पिछले टी20 विश्व कप सेमीफाइनल और 2023 वनडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। इस विश्व कप के बाद वह टीम से विदा ले रहे हैं लेकिन अभी इस बारे में उन्होंने कुछ कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद इस पर बात करेंगे। अभी दो अहम मैच खेलने हैं। अभी कुछ और बात करने का समय नहीं है। मैं अभी भी कोच हूं और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में यूएई के खिलाफ हम अच्छा खेलें।

एलिस-जम्पा की मारक गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को हराया

कोलंबो, एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज नाथन एलिस (12 रन देकर चार विकेट) और लेग स्पिनर एडम जम्पा (23 रन देकर चार विकेट) के शानदार प्रदर्शन से बुधवार को यहां ग्रुप बी मैच में आयरलैंड पर 67 रन की जीत के साथ आईसीसी टी20 विश्व कप में अपना अभियान शुरू किया। एलिस ने अपने शुरूआती स्पैल में तीन विकेट झटककर जीत की लय तय की। उन्होंने शीर्ष क्रम को पवेलियन भेजा तो वहीं जम्पा ने मध्य और निचले क्रम पर कहर बरपाया जिससे आयरलैंड की पारी 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 16.5 ओवर में नौ विकेट 115 रन पर खत्म हुई।

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग एक गेंद खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए और फिर बल्लेबाजी करने नहीं उतरे।

ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज नाथन एलिस।

आयरलैंड के लिए जॉर्ज डॉकरेल ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने धीमी पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए हरफनमौला मार्कस स्टोइनिस (45 रन) और मैथ्यू रेनशॉ (37 रन) के बीच पांचवें विकेट के लिए 61 रन की अहम साझेदारी की मदद से छह विकेट पर 182 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। आयरलैंड की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए पावरप्ले में चार विकेट गंवा दिए थे। मिचेल मार्श ग्रोइन चोट के कारण टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गए हैं। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी चोट के कारण बाहर हैं जबकि मिचेल स्टार्क संन्यास ले चुके हैं तो एलिस ने मुख्य तेज गेंदबाज के तौर पर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। एलिस ने इस तरह तीन ओवर के शुरूआती स्पैल में नौ रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने रोस एडेयर (12), कर्टिस कैम्फर (04), बेन कालिट्ज (02) को आउट किया। फिर जम्पा ने गेरेथ डेलानी (11), लोरकान टकर (24), डॉकरेल और मार्क एडेयर (12) के विकेट झटके। आयरलैंड हालांकि 100 रन का स्कोर पार करने में कामयाब रहा। आखिर में एलिस अपना अंतिम ओवर करने के लिए आए और बैरी मैकार्थी (02) को आउट करके मैच खत्म किया।

ग्रीनपार्क या इकाना में होगा रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल

देहरादून। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पिच क्यूरेटर ने उत्तराखंड में देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करने के बाद मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में यहां के मैदान की हालत को बेहद निराशाजनक बताया है। इससे यहां रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल की मेजबानी को लेकर झटका लगा है।

क्यूरेटर राकेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि स्टेडियम की पिच और आउटफील्ड का स्तर इतना खराब है कि यहां सेमीफाइनल जैसा महत्वपूर्ण मुकाबला आयोजित नहीं किया जा सकता। निरीक्षण टीम के अनुसार, ग्राउंड का रखरखाव मानकों के अनुरूप नहीं है। सूत्रों की मानें तो बीसीसीआई अब इस सेमीफाइनल को कानपुर के ग्रीनपार्क या लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित करने पर विचार कर रहा है।

तैयारी पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने कहा- मुकाबले के प्रति टीम बेहद गंभीर

भारत के खिलाफ अलग मानसिकता के साथ खेलेंगे

कोलंबो, एजेंसी

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ रविवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप मैच को एक आम मैच करार दिया। लेकिन इसके साथ ही कहा कि इस बार उनकी टीम इस मुकाबले में अलग मानसिकता के साथ उतरेगी। पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड और अमेरिका को हराने के बाद ग्रुप ए में शीर्ष पर काबिज हो गई है। नीदरलैंड को हराने में उसे संघर्ष करना पड़ा था लेकिन अमेरिका को उसने आसानी से 32 रन से हराया जिसमें फरहान ने एक 41 गेंद में 73 रन की शानदार पारी खेली।

मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में फरहान से भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बारे में पूछा गया जो पाकिस्तान सरकार द्वारा बहिष्कार की अपील वापस लेने के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को खेला जाएगा।

फरहान ने कहा लगातार दो मैच जीतने और तालिका में शीर्ष पर काबिज होने से आत्मविश्वास मिलता है। अगला मैच भी एक आम मैच जैसा ही होगा। यह पहला अवसर नहीं है जबकि हम उनके खिलाफ खेलेंगे। उन्होंने कहा हम पहले भी उनके खिलाफ खेल चुके हैं लेकिन इस बार हमारी मानसिकता अलग होगी। आपने देखा ही होगा कि शादाब (खान) रन बना रहे हैं, (मोहम्मद) नवाज़ रन बना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको उनके खिलाफ हमारा खेल पसंद आएगा। फरहान ने कहा यह एक सामान्य मैच होगा और हम इसे एक अन्य मैच की तरह ही लेंगे। हम यह नहीं सोचेंगे कि यह भारत और पाकिस्तान का मैच है। हम इसे एक सामान्य मैच की तरह ही खेलेंगे।

भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है। उसने हाल में एशिया कप में पाकिस्तान को सभी मैच में हराया था। तब भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि हाल के वर्षों में उनकी टीम के दबदबे को देखते हुए वह अब पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता को बराबरी का नहीं मानते हैं। फरहान हालांकि इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता।

मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया

फरहान से जब पूछा गया कि क्या उनके पास भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का सामना करने के लिए कोई विशेष योजना है, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जब आप रन बनाते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं। मैं भी बहुत आत्मविश्वास से भरा हूं और जिस तरह से मैंने पिछली दो पारियां खेली हैं, उससे मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं मानता। एशिया कप में हमने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसे देखते हुए मुकाबले एकतरफा नहीं थे। हमने आखिर तक डटकर मुकाबला किया था। उम्मीद है कि इस बार भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के लगातार दो मैच जीतने से फरहान काफी उत्साहित हैं।